साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569
Mob: +91 9479535569

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 14 | अंक 18 | प्रति सोमवार इंदौर, 2 से 8 दिसम्बर 2019 | पृष्ठ 8 | मूल्य 2/- रुपए

कबाड़ी मोदी ने विदेशों में अपनी मौज मस्ती के लिए

विनाश पुरुष मोदी ने देश की कबाड़ कर दी अर्थव्यवस्था

रिजर्व बैंक को रू 40 लाख करोड़ से लूटा। सार्वजनिक उपक्रमों को बेंचा। मोटे कमीशन पर व्यापार व्यवसाय विदेशी कंपनियों को सौंपा।

प्रदेश की पूर्व मु.मं. उमा भारती ने कहा था मोदी विकास पुरुष नहीं विनाश पुरुष है, इस विनाश पुरुष मोदी ने जो विकास के सपने जनता को दिखाए थे। मोदी का बचपन स्टेशन पर चाय बेचने की आड़ में रेलवे का कबाड़ा चोरी कर बेंचते, चुरकटी करते हुए गुजरा था। मां के जेवर चोरीकर भागने वाला देश की जनता को मूर्ख बनाकर और ईवीएम की जालसाजी से अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ब्लैकमेल करके सत्ता हथिया कर प्रधानमंत्री जरूर बन गया। पर उसकी विनाश की, और मुफ्त के माल को लूटो खाओ की मानसिकता ने हीं देश में पहले 5 साल में 90 से ज्यादा विदेश यात्राओं में, विदेशों में अपने आकाओं की व्यवसायिक प्रतिनिधि बनकर गया उनके लिए विदेशी कंपनियों से मोटे मोटे सौदेबाजी करने की आड़ में देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर चौपट करता रहा। इसके साथ ही पूर्व के कार्यकाल में नोटबंदी जो उसने अपने आकाओं के व्यवसाय बढ़ाने के लिए की थी। उनके आकाओं का व्यवसाय तो 10 गुना तक बढ़ गया। उसका मित्र मुकेश अंबानी दुनिया का 9वें नंबर का सबसे अमीर बन गयाबदले में जनता, 1.5 करोड़ छोटे उद्योग और 3 करोड़ व्यवसाय धंधे चौपट हो गए। उसका दिल यहीं तक नहीं भरा। विदेशी कंपनियों और अपने देसी पूंजीपति आकाओं के इशारे पर उसने फिर मोटी अरबों रुपए की टैक्स चोरी के लिए ऐसा क्लिष्ट कर वसूली की व्यवस्था जिसे माल एवं सेवा कर या जीएसटी के नाम से जाना जाता है। बनाई जिसे स्वयं बनाने वाले भी और लगाने वाले भी आज तक 2 साल बाद भी समझ नहीं पाए। स्वाभाविक था, छोटे-मोटे उद्योग धंधे और व्यवसायी उसे न समझने के कारण अपना व्यापार धंधा चौपट कर बंद करने के लिए मजबूर हो गए।

नोटबंदी और जीएसटी ने देश में 18 करोड़ को न केवल बेरोजगार कर दिया। वरन देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाने से जो विकास की प्रक्रिया चल रही थी। वह भी मंद होने लगी। कपड़ा उद्योग, ऑटोमोबाइल, कृषि पर आधारित खाद्य उद्योग, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, धातु, रसायन, कंप्यूटर व सॉफ्टवेयर, संचार सेवाएं, सौंदर्य प्रसाधन आदि के अनेकों बड़े-बड़े उद्योग नगदी की कमी और जीएसटी के कारण आर्थिक मंदी का शिकार होने के कारण बंद होने की कगार पर आ गए जिसमें अशोक लीलैंड होंडा कार टाटा महिंद्रा व अनेकों अन्य ऑटोमोबाइल क्षेत्र की कंपनियों को पहले उत्पादन - और बाद में बंद करने की नौबत आ गई जिसे समाचार पत्रों ने नहीं छापा।

बार-बार विदेश यात्राओं में अमेरिका और रूस जाने के कारण वहां के राष्ट्रपतियों ने जिसमें ट्रंप और पुतिन थे इज्जत करने की तो बात दूर इस कबाड़ी को इसके अय्याशी और कुकर्मों के आधार पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसलिए हर बार की यात्रा में अरबों डालर के कबाड़ा हथियार खरीदने, डर कर पुतिन को इसने मुफ्त में ही एक अरब डॉलर का भुगतान रुस के विकास के नाम पर करना स्वीकार कर लिया। जो भारत के 7000 करोड़ रुपए होते हैं। साथ ही वहां से अनेकों समय बाधित जिसमें S-400 मिसाइल व अन्य हथियार खरीदने के लिए यह बाध्य भी हो गया। (शेष पृष्ठ 8 पर)

प्रदेश में 51 जिले, जनता से लूटा धन छिंदवाड़ा के विकास में ही

मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार हर मोर्चे पर असफल रही

चारों तरफ सरकार ना केवल करो से मोटी वसूली कर रही वरन सारी सरकारी सुविधाएं स्वास्थ्य शिक्षा 24 घंटे सतत विद्युत आपूर्ति भी जनता को मोटी वसूली पर देने की तैयारी उपलब्धियों में महंगाई भ्रष्टाचार अपराधों में पूरे प्रदेश में बढ़ोतरी

मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को लगभग 11 महीने हो चुके हैं जिन वादों के दम पर कांग्रेस ने सत्ता हथियाई थी।यथार्थ में जनता ने कांग्रेस को सत्ता नहीं सौंपी वरन भेड़िया झुंड पार्टी के माई के लालो को अहंकार भ्रष्टाचार बदतमीजी जालसाजियों व मधुमक्खियों के शहद चाटने में जनहितों को भूल, भ्रष्टाचार, जालसाजियों और लूट का तांडव करने वालों को सबक सिखाने हटाया है। प्रदेश के एक करोड़ से से ज्यादा किसानों का कर्जा माफी का सपना 70% किसानों के लिए अभी तक सपना ही बना हुआ है। कर्मचारियों को पदोन्नति देने संविदा कर्मियों को नियमित करने का सपना भी अभी तक दिवास्वप्नहै। दूसरी तरफ सभी मंत्रियों को सौंपे गये विभागों में भारी भ्रष्टाचार और लूट का तांडव (शेष पृष्ठ 5 पर)

साढ़े 5 साल के शासन में प्र.मं. मोदी का पहला राष्ट्रहित का अच्छा काम

132 करोड जनता के हित में क्षेत्रीय सर्वग्राही आर्थिक साझेदारी में शामिल होने से इनकार

चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते से पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट होने के साथ भारत की 132 करोड़ जनता चीन के लिए विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाता। जिससे भारत में सभी प्रकार का उत्पादन कार्य नष्ट हो जाता। भारत ने 4 नवंबर 19 को बैंकॉक थाईलैंड में हुए क्षेत्रीय सर्वग्राही आर्थिक साझेदारी समझौते जो 10 एशियाई देशों के साथ भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के शामिल हुये थे।

एशिया पेसिफिक के इन देशों में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यामार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम पूर्व से ही है। इनके बीच में व्यापारिक सेवाओं और सामान के क्रय-विक्रय पर पर किसी प्रकार का कोई करारोपण नहीं होता है। ये सभी देश आपस में करमुक्त व्यापार करते हैं। जिसमें भारत, चीन, जापान, आस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड के साथ शामिल होने का कार्यक्रम था। जिसका समझौता कार्यक्रम 4 नवंबर 2019 को बैंकॉक थाईलैंड में संपन्न हुआ। पर मोदी ने इस कार्यक्रम से दूर रहकर शायद अपने साढ़े 5 साल सत्ता में सबसे पहला और बढ़िया काम किया।पहली बार बुद्धिमता पूर्ण तरीके से राष्ट्रहित और जनहित में अपने शासनकाल में अपने घूमने की प्रवृत्ति को त्याग, दूर रहकर निर्णय किया।(शेष पृष्ठ 5 पर)

मप्र सामान्य प्रशासन विभाग के भ्रष्ट टुकड़खोर, भ्रष्टाचार को संरक्षण दे,

सूचना अधिकार अधिनियम को बना रहे भोथरा अपने परिपत्रों से

मुख्यमंत्री मुख्य सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग में बैठे सुकरो की फौज अपनी मोटी वसूली औ भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के लिए के लिए पिछले 14 सालों में सूचना के अधिकार अधिनियम का मजाक बनाते हुए

इस अधिनियम की धारा 19 का उल्लंघन करते हुए पंचायत और इसके ग्रामीण यांत्रिकीय, उद्यानिकी, महिला एवं बाल विकास, कोष एवं लेखा, आदिम जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक, खनिज, शिक्षा विभाग, कृषि, पंचायत विभाग आदि में जिला अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी होना चाहिए था, उनके वरिष्ठ को अपीलीय अधिकारी होना चाहिए था। परंतु कानून की धज्जियां बिखेरते हुए लूट और भ्रष्टाचार के लिये अपनी मनमर्जी से सूचना अधिकारी को ही अपीलीय अधिकारी बना दिया गया तो कहीं जिलाधीशों और मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अपीलीय अधिकारी बना दिया।

पंचायत विभाग में प्रधान सचिव और मंत्री से लेकर सरपंच और सचिव सबसे ज्यादा और सबसे बड़े भ्रष्टाचारी होते हैं।

मेरी यह बात और लेखन जो पिछले 20 वर्षों से पंचायत के बारे में लिख रहा हूं, मैं।

जिसे मैंने काफी निकट से समझा और देखा है।

देपालपुर में पड़े सचिव दुबे के ऊपर लोकायुक्त छापे ने सिद्ध कर दी।यहां पर भी ग्राम पंचायतों से लेकर जनपदों, जिला पंचायतों जहां संविदा कर्मियों में महिलाओं का खुलकर यौन शोषण किया जाता है।

खुलकर हनी ट्रैपिंग होती है। तब ही महिलाओं की समयवृध्दि और वेतन मिलता है।

यहां पर भी 20 -20, 25- 25 साल तक बैठे रहने वाले बाबू सहायकों लेखाकार व अन्य सभी स्टाफ भारी भ्रष्ट और जाल साज होते हैं हर योजनाओं में धन वितरण अनुदान आदि में खुलकर भ्रष्टाचार का तांडव होता है। (शेष पृष्ठ 8 पर)

घोर पाखंडी सत्ताधीश अपनी नाकामी छुपाने जनता को भ्रमित करने ऐसे षड्यंत्र रचते हैं

भारत का चंद्रमा पर यान उतारना पूर्ण नौटंकी और जन धन की बर्बादी

अमेरिका ने वियतनाम की हार को छुपाने 1969 में चंद्रमा पर उतरने का नाटक किया। वही मोदी ने नोटबंदी, जीएसटी, रिजर्व बैंक को लूट विदेशों में मौज मस्ती करने से ध्यान हटाने चंद्रमा की नौटंकी की।जो पूर्ण बकवास और देश की जनता का समस्याओं से ध्यान हटाने व मूर्ख बनाने का षड्यंत्र था

अमेरिका 1956 से लेकर 1975 तक वियतनाम से युद्ध में बुरी तरह से पिटता रहा। उसकी एक इस नाकामी नहीं पूरी दुनिया में उसकी थू थू करवा दी। पूरी दुनिया में उसे बहुत कमजोर और फांकू समझा जाने लगा। अपनी उस नाकामी को छूपाने दुनिया में अपने को महानतम वैज्ञानिक रूप से समृद्ध राष्ट्र सिद्ध करने के लिए चंद्रमा पर आर्मस्ट्रांग को उतारने का नाटक किया था। पिछले 50 सालों से अमेरिका मूर्ख बना रहा था। अब उसमें भारत भी शामिल हो गया। यह केवल दुनिया की जनता को अपनी फर्जी उपलब्धियों को गिनाने का षडयंत्र कारी तरीका है। रूस ने कभी नही कहा-वह चंद्रमा के निकट या उसके करीब पहुँचा। इस सच्चाई की पोल सन 2002 में मैंने खोल दी थी। जब मैं अपने कार्यालय में बैठकर कार्य कर रहा था ऊपर से क्लब का 2 सीटर जहाज गुजरा। सीधी सी बात थी। दिमाग में खुजली हुई अपने जहाज न उड़ा पाने के कारण। तो अचानक मस्तिष्क में अपने द्वारा पढ़ी हुई हवाई जहाज से संबंधित किताबों को की हवाई जहाज पृथ्वी के वातावरण में हवा पर तैरता है। तो अमेरिका पिछले 33 सालों से दुनिया की जनता को यह कहकर क्यों मूर्ख बना रहा है कि वह चंद्रमा पर उतरा। जबकि वहां पहुंचना संभव नहीं। मैं तत्काल अपने कंप्यूटर पर आर्मस्ट्रांग की चंद्रमा की लैंडिंग की फोटो डाउनलोड करके उनको बड़ा करना शुरू किया। तो देखा सब झूठ और बकवास है। (शेष पृष्ठ 6 पर)

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

जाहिल सत्ताधीश हांके सत्ता, जन से लूट, विदेशों में मौज मस्ती, पूंजीपतियों को छूट

स्वतंत्र भारत के इतिहास में वर्तमान प्रधानमंत्री जैसा पाखंडी, घोर धूर्त, अनपढ़, आपराधिक प्रवृत्ति का, घोर स्वार्थी, झूठा, मक्कार, डरपोक व्यक्ति नहीं आया। जो जनता को झूठे वादों के सब्जबाग दिखाकर और ईवीएम की जालसाजी के सहारे, अपने ही वरिष्ठ नेताओं को ब्लैकमेल कर सत्ता हथिया लेने के उपरांत, जो अपनी मौज मस्ती और विदेशों में नौटंकी दिखाने के लिए केंद्रीय बैंक को लाखों करोड लूटकर खाली कर दे, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर देश की सरकार की बैंकरों की बैंक रिजर्व बैंक से लगभग 40लाख करोड का धन अपनी विदेश यात्राओं में मौज मस्ती और नौटंकी में खर्च किया।

अपनी पूंजीपति आकाओं की सेवा में, उनके लाभ के लिए, नोटबंदी कर जनता के हाथ से धन छीन कर 3 महीने तक पूरा देश बंद कर करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दे। देश के 50लाख से ज्यादा उद्योग धंधे को चौपट कर दे। फिर भी दिल ना भरे तो अपने चंद गिने-चुने उद्योगपतियों और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आकाओं के लाभ और गुलाम बनाने के लिए जनता को बेरोजगार कर लघु व्यापारियों, उद्योगों, धंधों व सेवाओं को नष्ट करने माल एवं सेवा कर लगा, सबको उलझा कर नष्ट करने का षडयंत्र रच दे। जिसे स्वयं सरकार और उसके अधिकारी कर्मचारी ना समझ पाए इसके बाद में भी करदाता पर दंड और कारागार की सजा की व्यवस्था करें। जो देश को आर्थिक रूप से पूरी तरह से भिखारी बनाने पर तुला हुआ है। डरपोंक इतना की, अपने कुकर्मों को दवाने, छुपाने, अपनी बदनामी को रोकने, जनता का मुंह बंद करने, जनधन से लुटे पैसे से अरबों रुपए खर्च कर प्रसार माध्यमों यथा समाचार पत्रों, दूर दर्शनीय समाचार श्रृंखलाओं को डरा धमकाकर, खरीद कर, अपनी सच्चाई बताने से रोके। अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए,

वर्तमान में जनता के व्यक्तिगत संपर्क व प्रसार माध्यमों यथा मोबाइल फोन, ईमेल, सोशल साइट्स, आदि पर सूक्ष्मता से निगरानी करें, उस पर चलने वाली अपनी सच्चाई के संदेशों को रोकने जनता को डराये- धमकाये, और ना मानने पर कमजोर हिंदू जनता पर कहर ढाते हुए उन्हें कारागार में डाल दे।

केंद्र व राज्य सरकार के सभी मंत्रालयों में बैठे घोर धूर्त भारतीय प्रताड़ना सेवा अधिकारीयों की गिद्ध फौज अपनी मोटे कमीशन और कमाई के लिए देशी विदेशी पूंजीपतियों के इशारे पर नाच हर दिन नये षड्यंत्रो की रचना करते हुए ऐसी जाहिल प्रधानमंत्री को हांकते लूटने सलाह देते रहते हैं।

पिछले साढ़े 5 सालों में, जनता को भयक्रांत कर महंगाई, बेरोजगारी, विदेशों में मौज मस्ती करना जनता से लूटे धन, रिजर्व बैंक से 40लाख करोड रुपए लेने के साथ अपनी पूंजीपति आकाओं का लाखों करोड का ऋण माफ करने, बड़ी राष्ट्रीय कृत बैंकों का पैसा हजम करने, सरकारी संपत्तियों को, सरकारी कंपनियों को आपको पहले लूटा और लुटाया गया, फिर घाटे में दिखाकर उनको ओने पोने में बेचने, का षड्यंत्र रचा जा रहा हैं। इससे भी पेट नहीं भरा, तो जनता की बैंकों में जमा पर हाथ साफ करने पर आ गया। बात यहीं तक नहीं रुकती। देशी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश के 5 करोड़ से ज्यादा छोटे व्यापारियों, 15 करोड से ज्यादा किसानों, दो करोड़ से ज्यादा लघु एवं ग्रामोद्योगों जिनसे लगभग 70 करोड लोगों की रोजी रोटी चलती है को समाप्त कर सारा खेती किसानी, उद्योग धंधे, का पूरा व्यापार सौंपने के लिए हर दिन नये षड्यंत्र की कहानी लिखी जाती है। यथार्थ में भारत में 70 साल की आजादी इन सत्ताधीशों को हजम नहीं हो रही। देश को पुनः गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं।

घोर भ्रष्ट उच्चतम और सभी उच्च न्यायालयों ने भ्रष्टाचार छुपाने बर्बाद किया

सबसे बड़े बलात्कारी हैं जनता के विश्वास और पारदर्शिता के कानून सूचना के अधिकार के

न्यायालय न्याय के मंदिर नहीं जुएं के अड्डे।

सन्सद के बनाये इस कानून का सबसे ज्यादा बलात्कार सरकारी संस्थाओं जिसमें केंद्रीय सरकार के साथ देश का उच्चतम न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों ने अपने भ्रष्टाचारों को, कुकर्मों को, छुपाने, बचाने, दबाने सबसे ज्यादा उल्टे सीधे निर्णय देकर सूचना अधिकार अधिनियम05 का किया गया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत एक अधिकार यह भी है की सरकार जनता से लिए गए करों व धन का एक एक पैसे का हिसाब जनता को देगी। ताकि जनता और सरकार के बीच में विश्वास व पारदर्शिता बनी रहे। चूंकि हमारे देश का संविधान और सारा कानून दूसरे देशों के संविधानों को लेकर बनाया गया है। संविधान के ज्ञानी ध्यानी होने का पाखंड सरकार अपने फायदे के लिए करती रही। दूसरी तरफ सारे कानून ब्रिटिश सरकार ने लागू किए हुए यथावत चल रहे हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय दंड संहिता 1860 और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1870। बेशक इन कानूनों में समय2 पर हमारे नेताओं और पूंजीपतियों ने अपने हिसाब से संशोधन किए। सूचना के अधिकार कानून को लगाने में भी संविधान की इच्छा को पूरा करते करते 58 साल गुजर गए थे।

वह भी सरकार ने अपनी मर्जी से नहीं मुझ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं, संस्थाओं के साथ विदेशी पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में उनके निवेश की सुरक्षा में लागू किया।

इसका भी राज्य सरकारों ने अपने-अपने तरीके से संशोधन करके अपने आप को बचाने के लिए ना केवल दुरुपयोग किया बल्कि जनता के हाथ में जानकारियां ना पहुंचे इसके लिए उसने जैसे कि दस्तावेजों के अवलोकन की प्रति घंटे केंद्र ने शुल्क रु5 रखा। राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश में रु50 कर दिया। फिर सरकारी कर्मचारी और अधिकारी काम ना करने दस्तावेज ना दिखाने के उनके पास सैकड़ों घड़े घड़ाये बहाने जो सदियों से चले आ रहे हैं। तैयार रहते हैं। ताकि अपने कुकर्मों पर जनता की या सूचना का अधिकार मांगने वालों की नजर ना पड़ जाए। वैसे भी 14 साल में यह कानून सभी सरकारी विभागों से लेकर उच्च

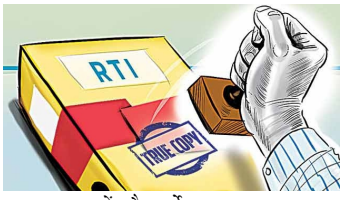

न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में मजाक का केंद्र बनकर रह गया और बची खुची कसर उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कुकर्मों को छुपाने दवाने बचाने इतने सारे उस कानून की आत्मा रूपी पारदर्शिता का बलात्कार करने और उसकी हत्या करने हर साल हजारों उल्टे सीधे निर्णय किए जाते हैं। कोई भी देश के उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय ने कभी नहीं कहा कि आखिर जब धारा 4 में सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन करने की व्यवस्था है। तो सभी दस्तावेज 14वर्षों बाद भी ऑनलाइन क्यों नहीं किए जाते। कोई निर्णय नहीं दिया यहां तक कि कानून में स्पष्ट व्याख्या है कि किसी भी आवेदक से उसका मंतव्य और औचित्य नहीं पूछा जाएगा। इसको भी अपने स्वविवेक से बलात्कार कर उन्होंने उसमें भी कारण और औचित्य और मंतव्य पूछने का अधिकार दे दिया।

दूसरी तरफ इंदौर के जिलाधीश क्योंकि ये जनता का पैसा आप के बाप की जागीर नहीं है।आपको हिसाब देना ही होगा। की अपेक्षा केंद्र सरकार उस कानून को खत्म करने से लेकर उसमें संशोधन करने धारा 4 में स्वयं जानकारी ना लोड करने यहां तक कि केंद्र सरकार ने इस बार तो अपना बजट भी अपने कुकर्मों को छुपाने जनता का धन हड़पने सूकरों की फौज ने हीं सही ढ़ग से पूरा अभी तक साइट पर नहीं डाला।

अभी तक साइट पर पूरा लोड नहीं किया और हाल ही में एक संशोधन करते हुए सारे देश के सूचना आयुक्तों की कमान अपने हाथ में रखकर उन्हें अपनी तरीके से नचाने दबाव बनाकर काम करवाने के लिए हरामखोरों, जालसाजों भ्रष्टों ने पास कर ही दिया। अब सूचना आयुक्तों को चुनाव आयुक्तों की भांति वेतन भी नहीं मिलेगा और उनको नचाने, कुदाने, दबाव बनाकर काम करवाने, जानकारी ना देने के लिए केंद्र सरकार ने सारे सूत्र अपने हाथ में रख लिए ताकि वह गिद्धों की फौज देश को कैसे भी नोच कर खाए। परंतु उन गिद्धों पर कभी उंगली ना उठाएं य मोदी अमित शाह और भेड़ियों का झुंड इस देश पर सो 200 साल तक राज करने की तैयारी में देश को लूट के, बैच के गिरवी करके, बर्बाद करने की ताक में बैठी हुई है।

रेलवे, बी एस एन एल, ओ एन जी सी, सारी तेल कंपनियां, बीमा कंपनियां, सरकारी बैंक, राज्यों के विद्युत मंडल, एयर इंडिया व सरकारी उपक्रम सब का निजीकरण कर मोटा कमीशन जो लाखों करोड़ में है। वह हजम कर रही है।

इसका जनता सभी पत्रकार साथी पूरे देश में तरीके से ना केवल विरोध करें। वरन उसको उसके मूल स्वरूप में रखकर उस में दिए हुए प्रावधानों का सख्ती से पालन करवाने के लिए हर मंत्रालयों, उच्च व सर्वोच्च से लेकर सत्र न्यायालयों व हर राज्यों की सरकार पर दबाव बनाएं।

आखिर सरकार को मिला धन सरकारी संपत्तियां आप के बाप की नहीं। जनता की है। जिसे आप जब चाहे जैसे चाहे अपने पूंजीपति मित्रों को लुटाते, बेंचते और गिरवी करते रहे। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस को इस बात को लेकर पूरे देश में हल्ला मचा कर जोरदार तरीके से विरोध कर उठाना चाहिए। आंदोलन धरना प्रदर्शन सड़कों पर किए जाने चाहिए लोकसभा में भले ही संख्या कैसी और कितनी भी हो इस बात को समझना चाहिए कि 1984 में भाजपा के मात्र दो सांसद लोकसभा में थे। इसके विपरीत भाजपाई हर बात को सड़कों पर उठाते थे। पर कांग्रेस के वर्तमान में आत्मविश्वास की कमी और भेड़ियों की बकवास से भयाक्रांत हो, आपातकालीन ऑक्सीजन पर चल रहे सारे नेता मरे हुए चुपचाप पड़े हुए हैं। जागो और देश की लड़ाई लड़ो अन्यथा नवयुवाओं की भर्ती कर नये जोशीले दूसरों को आने दो।

मोटी वसूली के लिए, खाद, बीज, कीटनाशकों उत्पादकों पर छापे की नौटंकी

शुद्ध के लिए युद्ध अभी शुरू हुआ उसके पहले तो वसूली

कृषि विभाग में झाबुआ में खाद उत्पादकों पर, छापे मारकर, नमूने लेकर जांच किये जाने पर उन फैक्ट्रियों को बंद की जाने की कार्रवाई की गई। पिछले 20 वर्षों से वही घोर भ्रष्ट अधिकारी संयुक्त संचालक उपसंचालक और सहायक संचालक के कुंडली मार कर मारकर बैठे है जिन्होंने मोटी वसूली कर इन सब को लाइसेंस दिए थे।

शुद्ध के लिए युद्ध अभी शुरू हुआ उसके पहले तो वसूली जारी थी। जबकि शुद्ध का नौटंकी का युद्ध के साथ जिन लोगों ने इस वसूली का वर्षों से युद्ध किया है उनकी भी जांच की जानी चाहिए आकर वह हरामखोर जाल साज भी लपेटे में आए आंख मीच कर इन सब उर्वरक कीटनाशक और बीज कंपनियों को इस तरह मिलावटी और नकली माल किसानों को बैच कर पूरी फसलें बर्बाद करने के साथ किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे थे जिन्होंने प्रदेश की कृषि को बर्बाद किया अखिलेश ऐसे उपसंचालक को सहायक संचालकों से लेकर प्रधान सचिव राजेश राजौरा तक सब खा पी कर पिछाड़ी हाथ बांधकर कैसे मौज मस्ती में घूम रहे हैं कांग्रेस के आने से यह उम्मीद थी कि भ्रष्ट और जालसाजी को पकड़ कर पर्याप्त सजा देगी और जनता को राहत दिलाएगी परंतु यह सब भी शामिल होकर लूटने में लगे हुए हैं सच तो यह शुद्ध के युद्ध के नाम पर केवल वसूली का युद्ध चल रहा है सैंपल लिए जाते हैं मोटा पैसा लेकर बदल दिए जाते हैं और उनकी जांच रिपोर्ट भी बदल जाती है पर भी पर्याप्त सूक्ष्मता से निगरानी की जा कर दोषियों को जिन्होंने ऐसे जाल साज लोगों को पाला पोसा बड़ा किया उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।

मध्य प्रदेश के 51 जिलों के अधिकांश उप संचालक कृषि और संबंधित उप संचालकों ने जिसमें पूर्व के आलोक मीणा और वर्तमान विजय चौरसिया ऐसे लोगों ने इंदौर में रहकर ऐसे फर्जी उत्पादकों को पाला पोसा बड़ा किया और मोटा कमीशन हजम कर उस समय के प्रधान सचिव राजेश राजौरा तक को पहुंचाया। वर्तमान में भी विजय चौरसिया 2-3 स्थानांतरित होने के बाद लौट कर आया। मोटी वसूली के बाद बांट कर ही तो यहां जमा हुआ है। ऐसे अधिकारियों ने जो रोल अदा किया है। उसकी भी गहनता से जांच की जा कर दोषियों को पर्याप्त दंड दिया जाना चाहिए।

15 वर्ष से भूखे बैठे कांग्रेस सरकार के मंत्री आंख मीचकर वसूली में व्यस्त

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी में सिंहस्थ के सभी भ्रष्टों को पाल किया पुरस्कृत

भ्रष्टों को बचाने अच्छी पदस्थापना से पुरस्कृत कर वसूली के बाद सब चुप

मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सभी विभागों में बनाए गए मंत्री केवल लूटपाट के तांडव में लगे हुए हैं जिनका उद्देश्य भ्रष्टों को पाल पोस कर मोटी वसूली कर अरबों रुपए के सिहस्थके भ्रष्टाचार को न केवल ठंडा कर दिया गया हैं। ऐसे सभी भ्रष्ट जिसमें कार्यपालन यंत्री उदिया उज्जैन संभागमें जो सन् 2012 से कुंडली मारे वहां बैठाया हुआ था। उसको पहले 2 संभागों का प्रभारी बनाया गया बाद में जब ज्यादा हल्ला मचा तो उसे हटाकर इंदौर में पदस्थ कर दिया गया। दूसरी तरफ घोर भ्रष्ट जाल साज धर्मेंद्र वर्मा जो पहले इंदौर नगर निगम संभाग में कई भ्रष्टाचार पर चुका था स्थानांतरण के बाद में भी कई महीनों तक इसने प्रभार नहीं छोड़ा की कई जांचें लंबित है।मोटा धन हड़प कर भाजपा ने उसको सिंहस्थ संभाग उज्जैन में पदस्थ कर दिया था। साथ ही अधीक्षण यंत्री के रूप में घोर भ्रष्ट रतनावत को भी बैठा दिया गया कि इन चारों संभागों का भ्रष्टाचार का मोटा खिलाड़ी था जो ग्रामीण, सिंहस्थ, यांत्रिकी और उज्जैन नगर निगम संभाग को समन्वय करके सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार का खेल खेल रहा था।बेशक भ्रष्टाचारी टीम के साथ मुख्य अभियंता सोनगरिया मुख्य अभियंता विद्युत यांत्रिकी अशोक बघेल और प्रमुख अभियंता गुमान सिंह डामोर प्रधान सचिव अश्विन राय, मंत्री कुसुम महदेले और मुख्यमंत्री शिवराज सब अरबों रुपए के भ्रष्टाचार की कबड्डी खेल रहे थे। इन सब ने मिलकर उल्टे ही ऐसे भ्रष्टों को चूंकि चुन-चुन कर इसलिए बैठाया गया। ताकि सिंहस्थ के नाम पर आसानी से केंद्र का राज्य का व बाजार से धन लेकर सिंहस्थ के दर्शनार्थियों व मेले में आने वाली जनता को पानी पिलाने व सिवर लाइन बिछाने, टंकियां लगवाने,आदि के नाम पर लगभग रुपए 600 करोड़ से ज्यादा की बंदरबांट हुई। लंबे लंबे मोटे मोटे ठेके दिए गए सिंहस्थ के नाम पर अनावश्यक 1', 2', 4', 6', की हजारों मीटर मोटी पीवीसी पाइप लाइनों को खरीदने से लेकर1' से लेकर 3 फुट मोटी पाइप लाइन बिछाई गई। हजारों टंकी खरीदी गई 74000 से ज्यादा स्नानागार संडास और मुत्रालय कागजों पर बनाए गए। जो कि वास्तविकता में 20-22 हजार से ज्यादा नहीं थे। उनमें पाइप लाइन टोंटियां प्लास्टिक की रू 10-20/- की नहीं थी। प्रति टोंटी रुपए 50 से 100 लगाई गई। खरीदी में ही लगभग दो अरब से ज्यादा का अधिक भुगतान किया गया। पूछने पर बताया गया कि काम ज्यादा जरूरी है। सरकार की साख और नाक का सवाल है। दूसरी तरफ इन हरामखोर जालसाजों ने जब सभी संभागों से सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी गई तो किसी ने जानकारी नहीं दी और उसके अपीलीय अधिकारी के रूप में बैठे हुए रतनावत ने क्योंकि सब ने मोटी बंदरबांट की थी। सारी अपील खारिज कर दी गई। यही काम इंदौर देवास, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम, झाबुआ धार संभागों में भी हुआ क्योंकि जो गांव रास्ते इंदौर, देवास, रतलाम, शाजापुर, धार, झाबुआ से होकर उज्जैन जाते थे वहां पर भी पानी पीने की व्यवस्थाओं के नाम पर यहां बैठे इंदौर के कार्यपालन यंत्री उस समय के संतोष श्रीवास्तव और अन्य ने भी उज्जैन से जुड़े कार्य हुए सभी गांव में पीने के पानी की व्यवस्थाओं के नाम पर मोटी बंदरबांट की।उन सब की15 वर्ष से भूखे बैठे कांग्रेस सरकार में जांच करने की बात जरूर कह गई थी। परंतु वर्तमान मंत्रीसुखदेव पांसे ने सबसे मोटा धन हजमकरचहेतों कोअभय दान और संतोष श्रीवास्तव को छोड़कर रतनावत को यहीं पर मुख्य अभियंता बना दिया। यही हाल इंदौर में 5 वर्षों से ज्यादा समय से बैठेसंजीव श्री श्रीवास्तव को जो नगर निगम इंदौर के साथ मिलकर हर कदम भारी भ्रष्टाचार कर रहा है यहां तक कि पुरानी लाइनों में सुधार कार्य जो कि अधिकांशविभागीय कर्मचारियों और छोटे ठेकेदारों से करवा लिया जाता है 25 से रू.50 लाख का हर मरम्मत कार्य में बिल बनाया जाता है 5 साल से ज्यादा समय से लगातार चल रहा है और जिसमें हर साल 50 से 80 करोड़ के बीच में 50% तक फर्जी काम दिखा कर हजम कर लिया जाता है बेशक इस फर्जीवाड़े में संभागायुक्तनिगमायुक्तमहापौर से लेकर उपयंत्री तक का मोटा सा होता है इसलिए इस बंदरबांट में कोई आवाज नहीं आती देश की जानी मानी घोर भ्रष्ट जाल साज राम की जिसने अपने पूरे देश में भ्रष्टाचार और जालसाजी के रिकॉर्ड कायम किए हैं को रुपए 270 करोड़ का ठेका लगभग 80 किलोमीटर लाइनें बिछाने और 27 शहर में टंकियां बनाने का दिया गया है सुहानी सी बात है 20 से 30% ज्यादा पर डीपीआर बनाई जाती है फिर जो डिजाइन किया जाता है टर्न क्योंकि इसकी फाउंडेशन में 20 से 25% तक उसका फाउंडेशन कम कर दिया जाता है जिस स्तर की टॉर्च ऑफ डाली जानी है उस से 20% तक कमजोर कामना की और जल जाती है और प्रकार टंकियों निर्माण में में भी 20 से 30% पैसा हजम कर लिया जाता हैसंजीव श्रीवास्तव का चुनाव से पहले स्थानांतरण कर दिया गया था इसके विपरीत बंदे ने मोटा पैसा खर्च कर वापस यही जम गया बेचारे 15 साल के भूखे कांग्रेसियों के सामने तो सवाल अभी वसूली का है अगली बार सत्ता में आए नहीं आए और 15 साल का पुराना जो खर्च किया है उसकी बसूली ही करनी बाकी है इसलिए अभी जितने भी भ्रष्टाचारी है स्वभाविक है वही मोटा धन देंगे इसलिए न केवल संजीव श्रीवास्तव धर्मेंद्र श्रीवास्तव रत्नाकर जो अभी अब मुख्य अभियंता के प्रभारी हैसबको वहीं यथा योग्य भेंट स्वीकार कर पदस्थ कर दिया गया है यही हाल पूरे मध्यप्रदेश में चल रहा है अधिकांश संभागों में महीना वसूल कर प्रभारी बनाए जा रहे हैं सिंहस्थजिसको गुजरे 3 साल हो गए पहले भाजपा की सरकार के मुख्यमंत्री मंत्री और मुख्य बा प्रधान सचिव ने प्रमुख अभियंता मुख्य अभियंताअधीक्षण यंत्री सारे कार्यपालन यंत्री कोपाला क्योंकि उसने मोटा हिस्सा खाया था अब कांग्रेसी मुख्यमंत्री मंत्री क्षेत्रीय मंत्री व विधायक पाल रहे हैं क्योंकि सबको उनके मुंह के आकार का टुकड़ा डाल दिया गया है इसलिए बेचारे भूखे रे अब पेट भर कर पहले जिम आएंगे फिर डकार आने के बाद सोचा जाएगा। इसी प्रकार इंदौर में 10 साल से बैठे विद्युत यांत्रिकी के पालन यंत्री चेतन रघुवंशी इनका भी स्थानांतरण नहीं किया बदले में इनको इंदौर नगर निगम का मंडलेश्वर का कार्यपालन यंत्री भी बना दिया गया इनके आने के बाद लगातार जुलूद में फाल्ट हो रहे हैं और कई दिन तक इंदौर को नगर निगम पानी की आपूर्ति नहीं कर पा रहा है यह भी घोर भ्रष्ट है दोनों हाथों से वसूली में विश्वास रखते हैं रोड लाइनर फूट रही है। रोज पंप बंद हो रहे हैं। बेशक यहां भी भ्रष्टाचार का लंबा चौड़ा खेल खेल रहा है। जो अच्छे कार्यपालन यंत्री कुरील थे उन्हें नगर निगम में क्योंकि वो ज्यादा भ्रष्टाचार करने में सक्षम नहीं थे इसलिए वहां अटैच कर दिया गया है यहां पर प्रभारी मंत्री सज्जन वर्मा का बोलबाला है जो उनको मोटा धन देता है उसे उसके मनचाही जगह पर बैठा दिया जाता है

वर्तमान में प्रमुख अभियंता के रूप में बैठाए गए संकुले जो बड़े ही सीधे साधे स्वभाव के हैं उनकी आड़ में बैठे हुए प्रभारी मुख्य अभियंता रत्नावती व प्रदेश के अन्य सभी मुख्य अभियंताउनकी आड़ में मोटी वसूली कर रहे हैं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुखदेव पांसे को कितनी भी शिकायतें व पत्र भेजो चुपचाप शांति से हजम कर जाते हैं। उज्जैन विद्युत अभियांत्रिकी संभाग में बैठा हुआ कांपालन यंत्री चौधरी जो कि भोपाल में रहता है। उज्जैन में सप्ताह में एक-दो दिन ही उपस्थित होता है।

सूचना के अधिकार में पूरे प्रमुख अभियंता कार्यालय से लेकर सभी मुख्य अभियंता कार्यालयों अधीक्षण यंत्री कार्यालयों नीचे संभागों और उप संभागों में जालसाजों की फौज बैठी हुई है। जो मोटा धन जमा कर रही है। हर कदम पर इसलिए कोई भी जानकारी देना पसंद नहीं करता। अपीलें लगाने पर अधिकांश अपीलें खारिज कर दी जाती हैं। धारा 6 (3) के अंतर्गत इंदौर का प्रमुख अभियंता कार्यालय में बैठे सभी भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारी उसकी प्रतिलिपि या जानकारी मांगने के लिए उनके अधीक्षण यंत्री कार्यालयों को अंतरित नहींकरते। बेशक मध्यप्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग में बैठे (छोटू मकानों) की फौज मोटा पैसा खाकर इस कानून की धज्जियां बिखेरते हुए धारा 6 (3) के अंतर्गत पत्रों के अंतरित करने से मना कर दिया गया है। इसलिए स्वाभाविक है हरामखोर उनको और मौका मिल गया इसलिए अभी पत्रों के अंतरण भी नहीं करते हैं और संभागों से कोई जानकारी नहीं दी जाती है। इस प्रकार 15 साल गुजर जाने के बाद में भी प्रमुख अभियंता कार्य आज तक धारा 4 की 17 बिंदुओं की जानकारी अभी तक अपनी विभागीय साइट पर नहीं डाली और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद तो भ्रष्ट कमलनाथ ने सारे विभागों की साइटों को भी ठंडा और मंदा कर दिया है। अब वहां अधिकांश विभागों की जानकारियां उपलब्ध नहीं हो रही है शायद यह 15 साल से भूखे बैठे अपनी लूट और भ्रष्टाचार से वसूली के लिए हर व्यवस्था को ध्वस्त करके ही मानेंगे।

लोकनिर्माण के परियोजना क्रियान्वयन इकाई घोर जालसाजों भ्रष्टों का अड्डा

मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग के घोर भ्रष्ट मंत्री सज्जन वर्मा की कहानियां तो पिछले जब कांग्रेस का शासन था तब से 15 साल के अंतराल के बाद जब से कांग्रेस सरकार आई है। जिस प्रकार से कांग्रेसी नेताओं को मंत्री पद क्या मिला। अहंकार में और संदेह का भय कि ना जाने कब सरकार गिर जाए के चक्कर में दोनों हाथ से लूटने बटोरने और घोर निकम्मे, जाल साज, भ्रष्ट अधिकारियों, इंजीनियरो को पाल पोष और संरक्षण देकर, मोटी वसूली कर भ्रष्टाचार को संरक्षित कर अपनी 15 साल की धन की भूख मिटाने में जुटे हुए हैं।

अब सत्ता में आए ना आए। कोई भरोसा नहीं और कब सरकार गिर जाए? इसका भी कोई भरोसा नहीं।

इसलिए पूर्व से बदनाम लोक निर्माण विभाग जिसमें इंदौर में पिछले दो-तीन सालों में केसरी, माथुर, जायसवाल के लोकायुक्त के चंगुल में फंसने के बाद यह तो स्पष्ट हो ही गया की। इंदौरी लोक निर्माण मंत्री सज्जन वर्मा ने चुन चुन के अपनी मोटी कमाई के लिए ऐसे भ्रष्टों को बैठाया है। जो काम के नाम पर काम कम और दाम ज्यादा वसूल कर उनके चरणों में डालते रहें।

इइ जयसवाल सं. 1 जो 35 लाख देकर इंदौर में बैठाया था। तीन चार महीने के ही कांडों में उसने भ्रष्टाचार से लगभग डेढ़ से दो करोड़ रुपए कमा लिया था। पकड़े जाने के बाद विश्वस्त सूत्रों के अनुसार मंत्री को उसने 3 करोड रुपए पुनः ऑफर किया था। पर वह इतना बदनाम हो चुका था। लगातार इंदौर के दैनिक समाचार पत्रों में 15 दिन तक प्रकाशित होता रहा। जिससे पूरे विभाग से लेकर पूरा कांग्रेस मंत्रिमंडल भी भारी बदनाम हुआ। इसलिए मजबूरन मंत्री को वह प्रस्ताव ठुकरा कर उसे सागर में मुख्य अभियंता कार्यालय में संलग्न करना पड़ा। यह कहानी का एक छोटा हिस्सा है।

लोक निर्माण विभाग के इसी प्रकार पीआईयू में चुन-चुन कर घोर भ्रष्ट और मक्कारों की पोस्टिंग कर दी गई है। चाहे वह जालसाज भोपाल का परियोजना संचालक विजय सिंह हो, इंदौर का अतिरिक्त परियोजना संचालक नायक हो, सभी संभागीय परियोजना यंत्री हो पूरे मध्यप्रदेश में क्या तांडव चल रहा है इसकी सभी विभागों के बनाए जाने वाले भवनों की बारीकी से जांच की जाए तो मालूम पड़ेगा कि ठेके पर बनाई गई डिजाइन में डेढ़ से दोगुना कीमत पर डीपीआर बनाई गई है क्योंकि डीपीआर जितनी ज्यादा की होगी आर्किटेक्चर और भवन की डिजाइन करने वाले को इतना ज्यादा कमीशन मिलेगा। डिजाइन, नींव डालने, लोड फैक्टर, देखरेख से 60से 90% तक का निर्माण करना इस तरह कम निर्माण करना आदि कार्यों में मोटी कमाई की जा रही है। स्वभाविक सी बातें हैं, की हरामखोर पीआईयू के डीपी से लेकर अतिरिक्त परियोजना संचालक या बैठा नायक जो कि टेलीफोन लगाने पर जवाब नहीं देता सूचना के अधिकार में अपीलों को लगाने के बाद पहले मई-जून की सारी अपीलों को इस हरामखोर ने दबाकर हजम कर लिया और सबसे पैसे की वसूली कर ली। अभी भी जानकारी प्राप्त करने के लिए दिए गए पत्रों में जब जवाब नहीं मिले तो उनकी अपील फाइल की। यहां बैठाा और मक्कार कामचोर स्टेनो जैन सब की फाइलें दबा कर बैठ जाता है। और आखरी दिन जानबूझ के उन पत्रों को डाक में पहुंचाता है। ताकि कभी भी समय पर वह डाक संबंधित को ना मिल सके। सारे दिन तो वैसे यहां वहाँ गायब रहता है और सारे अधिकारियों को अपने संबंध नेताओं व मंत्री से होने के कारण चमकाता धमकाता भी रहता है।

यह उसका पूरा विभाग कुछ लोग जो नये पहुंचे हैं। वह तो उसकी कार्यशैली से इतने रूष्ट हैं कि चुपचाप बैठे रहते हैं सारे दिन।

अपील की तारीख लगाई गई एक और एक ही तारीख को 22 तारीख का हस्ताक्षरित किया हुआ पत्र रजिस्टर्ड पोस्ट 1अक्टू. 19 को भेजा गया जो 3 अक्टूबर को मिला स्वाभाविक था 1 अक्टूबर की अपील की सुनवाई निकल चुकी थी।

फिर 16 अक्टूबर को अपील की तारीख निश्चित की गई। पत्र कभी नहीं मिला इस प्रकार यह हरामखोर नायक जो अपनी बदतमीजी के कारण पूरे विभाग में कुख्यात है।

अपनी कार्यशैली से बाज आने को तैयार नहीं और सब को बचाने और सब के भ्रष्टाचार को सिंचित कर मोटी वसूली करने का कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। इसके कार्यकाल के जितने भी भवनों का निर्माण इसके डीपीइ कर रहे हैं यदि जांच की जाए तो सभी भवनों के निर्माण में घोर अनियमितता स्तर हीनता के साथ 10- 20% तक भवन के सारे निर्माण छोटे व कम कर दिये गये।

उनकी फाउंडेशन जितनी डिजाइन में थी उतनी डाली नहीं गई। 20% से लेकर 70% तक कम, लोड फैक्टर के नाम पर भी ठेकेदार और डीपीई मिलकर जमकर बंदरबांट कर रहे हैं।

दरवाजे खिड़कियों से लेकर बिजली फिटिंग में भी 25 से 40% मार्जिन रखकर स्तर हीन काम व सामान का प्रयोग किया जा रहा है। अधिकांश भवनों में एक्स्ट्रा कास्ट स्वीकृत की जा रही है। और मोटी कमाई में बंदरबांट मंत्री पीएस सचिव परियोजना संचालक द्वारा डी पी ई और ठेकेदारों के भ्रष्ट गठजोड़ से सब को बंट रही है।

यहां नायक के संबंध में भोपाल से लेकर इंदौर तक उसके वरिष्ठ और कनिष्ठ सभी अधिकारी उसकी बदतमीजीयों से परेशान रहते हैं पर मंत्री को क्या उसको तो जितना मिल जाए, उतना थोड़ा, विभाग बदनाम हो, बर्बाद हो, उनकी बला से।

साप्ताहिक समय माया

प्रज्ञा से गोडसे की तारीफ करवाना, भाजपा का सुनियोजित षड्यंत्र

भाजपा का अपने कुकर्मो से मीडिया व विपक्ष ध्यान हटाने

देश की महापंचायत रूपी संसद में पिछले 5 दिनों से 25से30 नव. तक बड़े आराम से भाजपा ने अपने विरुद्ध महाराष्ट्र का अचानक 2 घंटे में राष्ट्रपति शासन हटाकर देवेन्द्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाने वाला कांड के साथ बीपीसीएल को बेंचने रिजर्व बैंक से लगभग 40 लाख करोड रुपए निकालने बीएसएनएल एयर इंडिया को नीलाम करने से लेकर देश में बढ़ती बेरोजगारी, नोटबंदी और जीएसटी से रसातल को जाती अर्थव्यवस्था, सभी गैर भूखे राजन पार्टी की सरकारों को उनके हिस्से का जीएसटी के घाटे का और उनके राज्य से वसूली किए गए आयकर के हिस्से का धन केंद्रीय योजनाओं का धन देने की अपेक्षा जानबूझकर उन कांग्रेसी राज्यों की सरकारों को जिसमें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान आदि आते हैं को आर्थिक रूप से परेशान करने के लिए धन ना देनेआदि पर होने वाली विपक्ष के शब्दों के आक्रमणों से व बहस से बचने और पूरे देश में अपनी महाराष्ट्र में हार और खोते जनाधार से किरकिरी ना हो को बचने बचाने के लिए जो तुरुप का पत्ता रूपी प्रज्ञा ठाकुर को गोडसे की तारीफ और गांधी के विरुद्ध बुलवाकर पूरी संसद का 5 दिन का बहुमूल्य समय बर्बाद करवाया गया। वह काबिले तारीफ है। और भूखेरा जन पार्टी के जाल साज आपराधिक डकैत प्रकृति के प्रधानमंत्री मोदी गृह मंत्री अमित शाह वित्त मंत्री सीतारमण आदि को आसानी से बचाते हुए

पूरी संसद के मूर्ख दूसरे सभी पार्टियों के सांसदों को ऊलझाकर और आसानी से क्षमा मांगने का कांड करवा कर देश की जनता से लूटा गया लगभग दो हजार करोड़ रुपए की संसद और सांसदों के वेतन भत्तों आदि पर होने वाले खर्च की बर्बादी कर दी गई। उसके साथ देश की अर्थव्यवस्था सुधारने, बेरोजगारी दूर करने, सर्वजनिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ रिलायंस की भुगतान व्यवस्था के साथ जोड़ने जैसे कुकर्मों पर आसानी से बहस टाल दी गई। दूसरी तरफ सारे देश के मीडिया को उस बहस को अपने पहले पन्ने पर लगवा कर सारे मीडिया को महाराष्ट्र में होने वाले शिवसेना राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने संयुक्त रूप से सरकार बनाई और उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह के संबंध में छापने से भी रोक दिया गया।

कहानी यहीं तक नहीं थमी इन शातिर आपराधिक प्रवृत्ति के भूखे रे जन पार्टी के अमित शाह और मोदी ने केजरीवाल ममता बनर्जी सोनिया गांधी राहुल गांधी कमलनाथ आदि को भी समारोह में शामिल होने से डरा- धमकाकर रोककर मीडिया में अपने विरुद्ध बनने वाले माहौल और जनता में अपनी जालसाजी और पैंतरेबाजी की नकारात्मक छवि ना बने आसानी से प्रज्ञा ठाकुर के माध्यम से बड़ा पूर्व नियोजित षड्यंत्र रुचकर अंजाम दे दिया गया जिसे देश की 99% जनता नहीं समझ पाई।

यही हाल समाचार पत्रों से लेकर पूरे देश के खरीदे हुए मीडिया टीवी समाचार चैनलों ने भी किया वैसे तो मोदी की धन, छल, बल के डर और दहशत से लगभग 50इ समाचार श्रृंखलाओं ने समाचार दिखाने ही बंद कर दिए। उन्होंने नाच गाने गीत संगीत आदि की महफिल सजा ली है और जो दिखा भी रहे हैं उसमें से 25% स्वयं भेड़िया झुंड पार्टी की अपने ही नेताओं आदि की प्रायोजित समाचार श्रृंखलायें हैं।

कोई भी समाचार पत्र मीडिया चैनल इस सच्चाई को पिछले 5 दिन से दिखाने की अपेक्षा प्रज्ञा की संसद में सुनियोजित रणनीति की नौटंकी दिखाने में व्यस्त है जनता उसमें मस्त है। पूरा देश उसका प्रशासन सभी मंत्रालय आर्थिक रूप से ध्वस्त हैं। केंद्रीय सरकार की राज्यों में प्रायोजित सभी विभागों में चल रही योजनाएं परियोजनाएं वाह राज्यों की केंद्र से मिलने वाले हिस्सों के आर्थिक वह वित्तीय सहायता ना मिलने से सभी गैर कांग्रेसी सरकारें अपने कार्यों को योजनाओं परियोजनाओं को सभी विभागों में संचालित नहीं कर पा रही है और बदनाम वहां की कांग्रेसी सरकारें हो रही है और और उसका पूरा लाभ भेड़िया झुंड पार्टी को मिल रहा है और मोदी और अमित शाह जी यही चाहते हैं इसीलिए वह किसी सरकार को गिरा नहीं रहे क्योंकि जो धन केंद्र के पास जाता था उसे मोदी और अमित शाह अपनी मनमर्जी से विदेश यात्राओं में उनका भाई दिखाकर अमेरिका रूस फ्रांस इसराइल आदि से वहां के समय बाधित और बेकार हो चुके हथियारों का कबाड़ा नए बने हुए हथियारों की कीमत से भी 3-4 से 10 गुना ज्यादा तक में मुकेश अंबानी की दलाली से खरीद कर ही अपने आका मुकेश अंबानी को भारत जैसे विशाल 132 करोड़ की आबादी वाले देश में दुनिया का नौवें नंबर का रईसजादा बनवा दिया। यह है उस बेचारी प्रज्ञा ठाकुर से दबाव देकर बुलवाएं गए वाक्यों का गांधी के विरुद्ध और गोडसे की प्रशंसा का सुनियोजित षड्यंत्र का धारावाहिक।

नोटबंदी और जीएसटी से अर्थव्यवस्था की तबाही

सीजीएसटी के कर्मचारियों की लूट का तांडव और मारपीट

जाहिल मोदी की नोटबंदी और जीएसटी जो उसने अपने पूंजीपति आकाओं के लिए लगाई थी। बेशक सभी उसके पूंजीपति आका पिछले दो-तीन सालों में सैकड़ों गुना कमाई करके अरबपति से खरबपति हो चुके हैं।बदले में पूरे भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। नोटबंदी में जनता को भ्रमित करने के लिए जो कारण बताए गए थे। वह सभी निरर्थक और तबाही साबित हुए। ना ही आतंकवादियों को धन की कोई कमी आई और ना ही कोई काला धन बाहर आया बल्कि काला धन जैसा कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा था 1000 का नोट खत्म करके 2000 का नोट चलाने से ज्यादा बढ़ेगा और बढ़ गया।

दूसरी तरफ नगदी की मार और जीएसटी ने जिसे बिना पूर्ण तरीके से लागू करने से पूर्व अध्ययन निष्कर्ष और उसके बाद के परिणामों का अंदाजा लगाएं पूंजीपतियों के इशारे पर लागू कर दिया। लगभग 800 दिन गुजर जाने के बाद में भी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों से लेकर देश के 27 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में वहां के अधिकारी कर्मचारियों तक आज तक जीएसटी उसके प्रावधान आदि के संबंध में कुछ भी ढंग से समझ में नहीं आया। इसके विपरीत व्यापारियों को, उत्पादको, ट्रांसपोर्टरों को अपने तरीके से सारा केंद्रीय कस्टम जो अब सीजीएसटी हो गया है और राज्यों के विक्रय कर विभाग के अधिकारी अपने तरीके से मनमानी व्याख्या कर व्यापारियों को मनचाहे तरीके से दंड अधिरोपित कर लूटने के साथ परेशान करने में लगे हुए हैं। जबकि केंद्रीय जीएसटी परिषद भी आज तक ढंग से किसी भी कानून की पूरी और स्पष्ट व्याख्या नहीं कर सकी है। ने चारों तरफ तबाही मचा दी।

8 नव. नोटबंदी की कि 3री बर्षी थी, धूर्त पाखंडी मोदी ने अपनी असफलताओं को स्वीकार करने की अपेक्षा एक कार्यक्रम में मोदी ने नोटबंदी की जारी थी कि जबकि 3 वर्ष बाद में भी नोटबंदी के दुष्प्रभावों का असर खत्म नहीं हुआ। नगदी की कमी ने हीं, देश के 10 करोड लोगों को पूर्ण रूप से बेरोजगार कर दिया।

देश के 90% मध्यम, वृहत और लघु उद्योगों को तबाह कर दिया। देश के 50 लाख से ज्यादा लघु उद्योग नकदी की कमी के कारण तालाबंदी के शिकार हुए! बची खुची कसर जीएसटी ने पूरी कर दी।

आटो मोबाइल इंडस्ट्रीज से लगभग से जुड़े हुए 20 लाख लोग सीधे-सीधे बेरोजगारी से बर्बादी के मुहाने पर आकर खड़े हुए हैं। वही हाल कपड़ा और तैयार वस्त्रों इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल खाद्य वस्तुओं औषधियों रसायनों लोहा, धातुओं, निर्माण, औषधियों व अन्य उद्योगों और व्यापार का भी हुआ।

बड़े ट्रक बनाने वाले अशोक लीलैंड बंद हो गई। टेल्को तालाबंदी की कगार पर है। जिसकी खबरें छोटे अखबारों में आई। बड़ों में नहीं छपी। से लेकर होंडा, सुजुकी, महिंद्रा, मारुति, टाटा, वाल्कस वेगन जैसे कारों के

निर्माताओ ने कारों के उत्पादन सभी ने घटा दिए। कुछ ने तो उत्पादन बंद कर दिया। चलते हैं। मूल कहानी की तरफ जीएसटी की। व्यापारी उत्पादक जो देश की अर्थव्यवस्था चलाता है। उसको सेंट्रल जीएसटी जो पूर्व में कस्टम था और वर्दी पहनता है।

सूत्रों के अनुसार पूरे देश में सामान ढोने वाले ट्रक ड्राइवरों, व्यापारियों, उत्पादकों के साथ सरकारी डकैतों की तरह पेश आ रहा है। डकैती तो कस्टम वाले पहले भी डालते थे पर अब व्यापारियों को या माल के मालिकों के साथ जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं। उनके मुखबिर ट्रकों के संबंध में जानकारी देते हैं। फिर यह चोरों उठाईगीरों की तरह उन ट्रकों का पीछा कर पकड़ लेते हैं। पहले ड्राइवरों की पिटाई करते हैं। उसके बाद माल के ट्रकों के मालिक को ट्रांसपोर्टरों को बुलाते हैं।

यह सरकारी डकैतों जालसाजों की फौज डराने धमकाने के बाद में फिर पेनल्टी लगाते हैं। और पेनल्टी के बराबर अपनी रिश्वत

की वसूली भी करते हैं।

जीएसटी की कौन सी धारा में व्यापारियों के साथ जानवरों की तरह व्यवहार कर ड्राइवरों की पिटाई करना व्यापारियों को डराना धमकाना बदतमीजी दिखाना और फिर पैनल्टी वसूल करने के साथ उसके बराबर ही रिश्वत वसूल करना आदि की कौन सी धाराएं बनाई गई है। व्यापारियों से निवेदन है कि इस संबंध में सीधे सीबीआई के साथ प्रदेश के लोकायुक्त और पुलिस को साथ में लेकर जाएं क्योंकि केंद्रीय सरकार की इस कस्टम के अधिकारी और कर्मचारी जिला न्यायालय और क्षेत्रीय पुलिस से बहुत डरते हैं। बेशक क्षेत्रीय पुलिस को अपनी वर्दी का रोब ऐंठेंगे। परन्तु क्षेत्रीय पुलिस को बिना डरे चमके उनके विरुद्ध f.i.r. फाइल करके क्योंकि भारतीय दंड संहिता और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता दोनों पूरे एक देश में एक कानून की तरह लगाई जाती हैं और व्यापारियों के साथ जानवरों की तरह पेशकर उनकी पिटाई करना और दुगनी वसूली करना जिसमें आधी पेनाल्टी और आधी रिश्वत होती है। जो पूर्णतः गैरकानूनी और आपराधिकता है।

इसलिए ऐसी मारा पीटी डराने धमकाने और वसूली करने की सीधे f.i.r. क्षेत्रीय थाने में जरूर करवाएं।

पूरे देश में हर प्रदेश में अगर क्षेत्रीय स्तर पर हर प्रदेश में हर महीने 25-50 केस अगर इन केंद्रीय जीएसटी वालों पर लगा दिए जाएंगे।तो इनको इनकी औकात समझ में आ जाएगी। दूसरी तरफ व्यापारियों का मान सम्मान करने के साथ पेनल्टी जो कानून के अनुसार है। वसूली जाए। परंतु दुगनी रिश्वत की वसूली न की जाए।

ना मानने पर व्यापारियों वकीलों और उत्पादकों, ट्रक मालिकों, ट्रांसपोर्टरों को बेखोफ इनके विरुद्ध हर प्रदेश में पूरे देश में 25-50 केस न्यायालय में लगा दिए जाएं।

व्यापारी उत्पादक ट्रांसपोर्ट अपनी मेहनत के दम पर सरकार चला रहे हैं। वो सरकारों को टेक्स चुका कर सरकारों को चला रहे हैं। सरकार के दम पर व्यापारी उत्पादक ट्रांसपोर्ट ट्रक मालिक नहीं चल रहे। उन्होंने अपने दम पर अपनी सल्तनत खड़ी की है। उनका भी वहाँ मान सम्मान है। केंद्रीय कस्टम जीएसटी अधिकारियों कर्मचारियों का मतलब यह नहीं कि वह जनता का उत्पादको, व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों का अपमान करें। ये अधिकारी कर्मचारी की व्यापारिक संस्थाओं को बेईमान बनाते हैं। और फिर लूटते हैं।

संचार क्रांति का अंतरजाल मनुष्य की जिंदगी का भयावह मकड़जाल बन गया

(पृष्ठ 12 का शेष)

बेशक यह तो स्वयं सिद्ध है कि जो व्हाट्सएप आज जासूसी और डाटा का दुरुपयोग कर रहा है। आने वाले दो 4 सालों में हाइक भी वही करेगा। परंतु जब तक सरकार बदल चुकी होगी।

समय बदलने के साथ इन कंपनियों पर सरकारों की और जनता की आवाज उठने के कारण जनता के डाटा का दुरुपयोग करना बिना मर्जी के डाटा को बेचना आदि की बत्तमीजीयों पर जनता के बढ़ते दबाव के कारण कानून बनाकर रोकना पड़ जाएगा।

गंभीरता से सोच कर व्हाट्सएप त्याग कर हाईक की तरफ बढ़ने का सिलसिला शुरू कर देने पर 15-20 दिनों के अंदर आसानी से व्हाट्सएप को त्यागने में सफलता मिल जाएगी और आप अपने आप को व संपर्क सूची मैं अपने वार्तालाप को सुरक्षित कर पाएंगे।

मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार हर मोर्चे पर असफल रही

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

15 वर्ष से भूखे बैठे स्वयं मंत्रियों ने अपनी वसूली के लिए स्थानांतरण पदस्थापना भ्रष्टों को पालना मेहनतकश सक्षम इंजीनियरों अधिकारियोंको किनारे कर घोर जालसाजों को संरक्षण देकर अपनी मोटी वसूली के लिए कमाई वाले पदों पर पुलिस, लोक निर्माण, आदिम जाति, ग्रामीण एवं पंचायत विकास, कृषि उद्यानिकी,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, वाणिज्य कर, परिवहन, आबकारी, जल संसाधन,शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, खाद्य एवं औषधि, विद्युत मंडल की कंपनियों, खनन, तहसील, जिलाधीश कार्यालयों से लेकर संभागों और मुख्यालयों में चुन चुन कर भ्रष्टों को बैठा कर पूरे प्रदेश में लूट और वसूली का तांडव मचा रखा है। पूरे प्रदेश में भारी बरसात के कारण प्रदेश के राजमार्गों की लगभग 40हजार किलोमीटर सड़कें काफी गंभीर हालत में है। उनमें गड्ढे भराई की प्रक्रिया धनाभाव के कारण बड़ी मंद गति से चल रही है। जबकि कमलनाथ सरकार ने पेट्रोल डीजल गैस शराब में लूट का तांडव मचाने के साथ वाहनों के क्रय पर, मार्ग कर 7% से बढ़ाकर 10 से 20% तक कर दिया। वही हाल पेट्रोल डीजल गैस शराब पर भारी करारोपण कर पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगा बेचा जा रहा है। साथ ही अन्य सेवाओं की शासकीय शुल्क में भी वृद्धि कर दी गई है। बेशक केंद्र सरकार का जो हिस्सा था। वह मोदी सरकार जानबूझकर जनता को परेशान करने नहीं दे रही है। यह सच है, पर इसके विपरीत जो धन नियमित रूप से कांगरेस सरकार को प्राप्त हो रहा है। उसमें अधिकांश धन कमलनाथ केवल और केवल छिंदवाड़ा में जहां उसकी अनेकों फैक्ट्रियां हैं और 40 साल पुराना उनका लोकसभा क्षेत्र है। वह केवल वहां खर्च कर रहे है। मध्य प्रदेश जल संसाधन, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, कृषि, उद्यानिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, शहरीय विकास, अनुसूचित जाति, आदिम जाति, परिवहन सभी विभागों में पर्याप्त धन आवंटन व नए कार्यों की शुरुआत केवल छिंदवाड़ा में ही हो रही है! वहां सरकार ने हवाई पट्टी जहां बोइंग 747 तक उतारे जा सकेंगे, बनाने से लेकर चिकित्सा महाविद्यालय, में रु2000करोड़ कृषि उद्यानिकी महाविद्यालय रु3000करोड़ में बनाने की घोषणा कर लगभग मध्य प्रदेश से लूटा धन रु5000करोड़ से ज्यादा खर्च करने का खाका तैयार कर दिया है। जैसे मध्य प्रदेश का पूरा धन कमलनाथ के बाप की जागीर हो और इसका उपयोग वे केवल अपनी छिंदवाड़ा की सल्तनत में खर्च करना चाहते हैं। जबकि 50 जिलों के जिसमें सभी विभागों में धन आवंटन नहीं दिया जा रहा है मप्र जल संसाधन विभाग में सबसे ज्यादा नए कार्यों की नई निविदाएं नई परियोजनाएं छिंदवाड़ा में शुरू कर दी गई। परंतु पूरे प्रदेश में जल संसाधन विभाग के सारे कार्य बंद कर दिए गए हैं। यही हाल लोक निर्माण विभाग में सारी नई सड़कों के कार्य बंद कर केवल पुरानी सड़कों पर वहां के गड्ढे भराई व पेंच मरम्मत की जा रही है। जल संसाधन विभाग में भी पुराने सभी तालाबों नहरों, बांध व आदी का काम प्रदेश के 48 जिलों में बंद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग में केवल काम हो रहा है तो छिंदवाड़ा जल संसाधन मंत्री के जिला शाजापुर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के जिला गुना में भर नए परियोजनाओं, बांधों, नहरों और तालाबों की नई निविदाएं भर जारी की गई है। बाकी 48 जिलों में सरकार जल संसाधन विभाग के बांधों, नहरों, तालाबों के निर्माण को पूर्णता बंद कर चुकी है। पुराने कार्यों में भी आवंटन के अभाव में कार्य बंद कर दिए गए हैं। कृषि विभाग में भी जिन योजनाओं में केंद्र का धन आ रहा है। उन्हीं योजनाओं में काम हो रहा है। परंतु आयोजित योजनाओं जिनमें प्रदेश सरकार का धन लगता है वह 50 जिलों में बंद हैं। स्वास्थ्य विभाग में सरकार ने स्वयं ही घोषणा कर दी है कि वे सरकारी अस्पतालों में गरीबों का इलाज करने में केवल आयुष्मान योजना में पंजीकृत होंगे जबकि यथार्थ यह है कि 90% आमजन भी उसमें पंजीकृत नहीं है। आखिर लोकतंत्र में जो कि अब लूट तंत्र बन चुका है क्या सरकार मनचाहे तरीके से करो के माध्यम से जैसे चाहे लूटे और अपनी जिम्मेदारियों जिसमें जनता को मुफ्त स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें, स्वच्छ जल वायु, वह जीवन की अन्य सुविधाएं प्रदान करें परंतु इसके विपरीत हालात यह है की सरकार में बैठे मंत्रियों अधिकारियों को अपनी लूट में पूरी छूट चाहिए, परंतु बदले में जनता को परेशानियां, दहशत, खराब सड़कें, खराब स्वास्थ्य, सुविधा एवं स्तरहीन सरकारी शिक्षा। वाह-वाह रोजगार-धंधों को नष्ट करने के षड्यंत्र बदले में अपने पूंजीपति मित्रों के पेट भरने के लिए नित नए कानून सरकारें जब चाहे जैसे चाहे जनता पर थोपती रहती हैं। जनता से इकट्ठा किया हुआ और लूटा हुआ धन अपने प्रचार-प्रसार माध्यमों पर अपने विशेष क्षेत्र की जहां से मुख्यमंत्री पिछले 40 साल से जीता हुआ आ रहा है, उसके उन्नति विकास पर अपने मनमर्जी से खर्च और लुटाया जा रहा है। दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता जो सरकारी योजनाएं पूर्व से चल रही थी उनको बंद कर दिया गया है। स्वास्थ्य सुविधाएं जो गरीब लोग सरकारी अस्पतालों में जाते थे उन अस्पतालों का निजीकरण के साथ वहां पर भी मोटे-मोटे शुल्क ठोक दिए गए हैं। आखिर जनता से लूटा धन अपने बाप की जागीर नहीं है। कमलनाथ जी जो जहां चाहे जैसा चाहे अपने मनमर्जी से अपने प्रचार-प्रसार और प्रशंसा में प्रसार माध्यमों पर खर्च किया जाता रहे। जब से कांग्रेस सत्ता में आई है सभी मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने जो 15 वर्ष से भूखे बैठे हुए थे चारों तरफ लूट का तांडव मचा रखा है। सरकार के नियमित खर्चे पूरे हो ना हो जबकि जनता को भ्रमित करने के लिए कोई शुद्ध का युद्ध चलाने की आड़ में वसूली का युद्ध चला रहा है जिसमें खाद्य एवं औषधि विभाग जो स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, जिसके मंत्री तुलसी सिलावट हैं। चारों तरफ अब मिश्रण करने वालों से मोटी वसूली करके उन्हें पूरी छूट दी जा रही है और जो ईमानदारी से व्यवसाय व काम करते हैं स्वाभाविक है इसलिए भी वसूली ना दे पाने के कारण उन्हें परेशान किया जा रहा है जबकि पूरे मध्यप्रदेश में बरसों से अवैध वसूली करके लूटने वाले खाद्य एवं औषधि निरीक्षकों को उनके मन चाहे पदों पर दस बरसों से ज्यादा समय से बैठा रखा गया है। यही हाल कृषि में भी मचा हुआ है। कृषि विभाग में भी पूरे मध्यप्रदेश में जो भ्रष्ट अधिकारा- कर्मचारी जिन्होंने स्तरहीन खाद बीज और कीटनाशकों के मोटी वसूली करके लाइसेंस जारी किए थे। जबकि वह जानते थे कि उत्पादक पैकर और विक्रेता जो मोटी वसूली दे रहा है कोई भी ईमानदारी से नियमानुसार काम नहीं करेगा। बदले में किसान की फसल स्तरहीन, नकली, खाद बीज और कीटनाशकों के कारण बिगड़ने पर किसान लिए गए कर्ज को नहीं चुका पाने के कारण आत्महत्या कर लेगा। सैकड़ों किसान इन्हीं हरामखोर जालसाज विजय चौरसिया जो खरगोन में सहायक संचालक रहते हुए और वर्तमान का संयुक्त संचालक रेवाराम सिसोदिया दोनों इंदौर में बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में एग्रो फॉस जैसे नकली खाद बनाने वाले जैसे सैकड़ों स्तरहीन और साधारण तरीके से बीज उत्पादक सोसायटियों को भारी अनुदान का मोटा धन बांटकर अपना मोटा हिस्सा डकारा है। वे सोसाइयटियां बाजार से साधारण कृषि उत्पाद खरीद कर चलनी लगाकर छानकर बोरों में भरकर बीज प्रमाणीकरण संस्था से टैग खरीद कर टैगिंग कर पैकिंग कर रहे हैं।। वही बीज बाद में आलोक मीणा जैसे जो अपनी जाटाओं के चलते अभी देवास में आत्मा में बैठा हुआ है। आसानी से पूरे इंदौर उज्जैन संभाग में वही बीज में दलाली खाते हुए कंपनियों से बिकवा रहा है। ऐसे पूरे मध्यप्रदेश में सभी जिलों में उपसंचालक और सहायक संचालक बनकर बैठे हुए भ्रष्ट अफसरों को मोटा धन लेकर कृषि मंत्री आंख मीच कर संरक्षण दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के पास सारी खबरें होने के उपरांत भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। यही हाल परिवहन, आबकारी, वाणिज्य कर, खनन, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य, जल संसाधन, पंजीयन, महिला बाल विकास, वन, शिक्षा, ग्रामीण विकास, जिला पंचायता, स्वास्थ्य विभाग, उद्योग विकास, श्रम, पुलिस आदि का भी है। सभी विभागों में भ्रष्टों को पाला-पोसा जाकर मोटी वसूली की जा रही है। बदले में जनता को हर कदम भारी परेशानी का सामना, पेट्रोल, डीजल, गैस, शराब, खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पानी, बिजली, कृषि, उद्यान की मैं झेलना पड़ रही है। इसके विपरीत कमलनाथ जो एक व्यापारी, व्यवसाई, उद्योगपति और पूंजीपति है। उसे इन सब जनता की परेशानियों से मतलब नहीं वह केवल अपने क्षेत्र के औद्योगिक आर्थिक, सामाजिक विकास के लिए व्यक्तिगत स्तर पर पूरे प्रदेश के 50 जिलों को छोड़कर छिंदवाड़ा के विकास में पूरी तन्मयता से लगा हुआ है, जो भविष्य में कमलनाथ के लिए घातक सिद्ध होने वाला है। उसका नियंत्रण ना अपने मंत्रियों पर है ना सरकार पर है। सरकार पर वैसे भी पूर्व के मुख्यमंत्री दिग्गी दानों का साया है जहां डिग्गी दानव ने अपने मनपसंद मुख्य सचिव घोर भ्रष्ट और जॉर्ज साइज सुधी रंजन मोहंती को बना रखा है वहीं दूसरी तरफ सभी मंत्रालयों में अपनी मनपसंद के प्रधान सचिवों, आयुक्तों, संचालकों से लेकर सभी तकनीकी विभागों में अपनी पसंद के प्रमुख अभियंता बैठा रखे हैं। यही कारण है कि कहने को मुख्यमंत्री कमलनाथ है पर सारी सत्ता पीछे से केवल दिग्विजय सिंह चला रहा है जिसके ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ अनेकों विपक्षी विधायकों ने टिप्पणियां की हैं जो पूर्णता सच है। इस पर कमलनाथ को ध्यान देना होगा और अपना छिंदवाड़ा प्रेम छोड़कर पूरे मध्यप्रदेश के समग्र विकास की तरफ अपने वादे पूरे करते हुए किसानों का कर्जा माफ करते हुए पेट्रोल गैस शराब खाद्यान्नों की कीमतें कम करने के लिए करो को घटाना चाहिए। दूसरी तरफ निशुल्क अच्छी शिक्षा, सड़कें, स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था पूर्व की तरह की जानी चाहिए अन्यथा कमलनाथ की सरकार गिरने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा।

132 करोड जनता के हित में क्षेत्रीय सर्वग्राही आर्थिक साझेदारी में शामिल होने से इनकार

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बेशक इस समझौते के कुछ फायदे होते। परंतु चीन के साथ इस समझौते में शामिल होने का मतलब था चीन का सारा गुणवत्ता हीन अविश्वसनीय सारा दुनिया से नकारा हुआ सामान भारत के बाजारों में सस्ते के नाम पर बैचकर सभी उद्योग धंधे चौपट कर दिए जाते। जैसा कि दुनिया के अधिकांश छोटे देशों में और भारत में हुआ।

न्यूजीलैंड के शामिल होने पर अत्यधिक मात्रा में उत्पादित होने वाले दूध के पाउडर के सस्ते आयात से भारत में प्रतिदिन 50 करोड़ लीटर दूध की भारी कमी को पूरा करने मैं भारी सहायता मिलती गरीब जनता के 2 करोड़ नौनिहालों को सस्ता दूध उपलब्ध करवाया जा सकता है। जो हमारे देश के घोर नीच जाल साज रसायनों से बना कर पूरा कर रहे हैं। पूरे देश की जनता के लिए भारी घातक होता है। जो गंभीर बीमारियों किडनी लीवर कैंसर, चर्म रोग हृदयाघात को जन्म देते हैं। और 5 साल से कम उम्र के गरीब जनता के 5% बच्चे गंभीर बीमारियों के शिकार हो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जिसे केंद्र सरकार सीधा समझौता करके आसानी से आयात कर सकती है। ताकि रासायनिक घातक पदार्थों से बने दूध पर रोक लगाई जा सके।

बेशक यह भी संभावित है। कि इसमें भी अदानी, अंबानी, टाटा बिरला व अन्य को अपने कारोबार की चिंता सताने लगी हो क्योंकि अभी जो ₹60 अरब का माल भारत में आता है। आज छोटे व्यापारी अपनी छोटी दुकानों से देश की जनता को बेचकर काम चला रहे हैं। यदि कर मुक्त व्यापार चीन के साथ में हो जाएगा। तो वहां से यह आयात 60 अरब डॉलर से बढ़कर 300 अरब डालर तक पहुंच जाएगा जिससे भारत की कृषि से लेकर सभी उद्योग धंधे पूर्ण रूप से चौपट हो जाएंगे और भारत एक उत्पादक नहीं उपभोक्ता और उपभोग करने वाले देशों की श्रेणी में आ जाएगा। जिससे भारत में चलने वाले अदानी अंबानी टाटा बिरला वॉलमार्ट आदि के बड़े शॉपिंग मॉल और पूरे व्यवसाय पर कब्जा करके पूरे देश को गुलाम और मजदूरों का देश बनाने का सपना टूट सकता है। संभावित है कि अपने 10-12 पूंजीपति आकाओं के कहने पर मोदी ने शामिल होने से मना कर दिया हो।

इस पर भारत की गरीब जनता को ध्यान में रखकर मोदी ने इसे अपनी आत्मा की आवाज पर निर्णय लेते हुए इस समझौते में हिस्सा लेने से मना कर दिया। क्योंकि पूर्व से ही चीन का भारतीय बाजारों पर कब्जा हो जाने से भारत का व्यापार, उत्पादन, बड़े, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग, कृषि आदि सब भारी बुरी तरह से चीनी माल के गुणवत्ताहीनता और सस्ता होने के कारण पिछले 20 सालों में बर्बाद हो चुके हैं। और उसके खिलाफ लगातार 6लाख गांवों से लेकर महानगरों तक आवाज उठाई जाती रही है।

अभी भी कांग्रेस के साथ अनेकों व्यापारिक संगठनों किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री कार्यालय पर दबाव डालकर इस समझौते में शामिल ना होने के लिए कहा था।

आरसीईपी एक व्यापार समझौता है, जो इसके सदस्य देशों के लिए एक-दूसरे के साथ व्यापार करने को आसान बनाता है। इस समझौते के तहत सदस्य देशों को आयात-निर्यात पर लगने वाला टैक्स या तो भरना ही नहीं पड़ता या फिर बहुत कम भरना पड़ता है। आरसीईपी में 10 आसियान देशों के अलावा भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के शामिल होने का प्रावधान था. पर भारत इससे दूर रहा। आरसीईपी को लेकर भारत में लंबे समय से चिंताएं जताई जा रही थीं. किसान और व्यापारी संगठन इसका यह कहते हुए विरोध कर रहे थे कि अगर भारत इसमें शामिल हुआ तो पहले से परेशान किसान और छोटे व्यापारी तबाह हो जाएंगे.

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति से जुड़े स्वराज पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने आरसीईपी से बाहर रहने के भारत के फैसले को अहम बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने जनमत का सम्मान किया है. जिस पर शायद अपने शासनकाल में पहली बार बुद्धिमता पूर्ण तरीके से मोदी ने जनता की आवाज को ध्यान में रखकर शामिल होने से स्पष्ट इनकार करते हुए ग्रामीण जनता की बुनियादी रोजगारों, उद्योगों, कृषि उत्पादों आदि के हित की चिंता को लेकर समझौते में शामिल होने से मना किया है। इसे सोनिया और राहुल अपनी जीत मान रहे हैं। बेशक कुछ हिस्सा तो रहे हैं। क्योंकि उन्होंने भी ऐसे अनेकों देशों व संगठनों के व्यापारिक समझौते अपने लंबे शासनकाल में जनहित में करने से लगातार मना किया।

साप्ताहिक समय माया

जनता की जेबों की सफाई, निगम अधिकारियों, इंजीनियरों, पार्षदों, कर्मियों की लुटाई

स्वच्छता का पाखंड, बदले में विषैली प्राणवायु जनता को दे रही बिमारियां और अकाल मृत्यु

इंदौर नगर की मुख्य सड़कों पर ही सफाई दिखाई देती है। जबकि अंदर की बसाहटों में, गृह निर्माण मंडल की, विकास प्राधिकरण की, बड़े नेताओं, भू माफिया की कॉलोनियों की सड़कों और मकानों की बैकलाइन में न केवल कचरा भरा रहता है, इस निगम में वर्षों से कुंडली मारे बैठे डकैतों के शहर में पिछले 20 वर्षों में नालिया बिछाने के नाम पर, एडीबी, विश्व बैंक का, जेएनएनयूआरएम, खुले बाजार से बेचे गये बांड का 6 हजार करोड़ से ज्यादा डकार गए, परंतु सड़कों के किनारे व मकानों की पिछाड़ू में नालिया सीवर लाइन, स्टार्म लाइन, आजादी के 70 साल बाद भी अभी तक ढंग से नहीं बनाई जा सकती। इसकी आड़ में पिछले 40 साल से खोदने, फोड़ने, बनाने के तांडव में जनता परेशान भी हो रही है। फिर भी गंदा पानी बदबु मारता रहता है। बरसात में तो इंदौर मुख्य मार्गों पर भी पानी भर जाने के कारण दर्शनीय और नाव चलाने लायक हो जाता है। फिर भी 3 बार सफाई का पुरस्कार बांटने वाले और लेने वाले दोनों ही जनधन की लूट के साझेदार है। हर नगर की जनता को भ्रमित करने सफाई में नंबर वन है। इस सफाई की आड़ में, बड़ी पूंजीपति कंपनियों टाटा, महिंद्रा, लीलैंड, आदि के जिसके हजारों करोड़ के, 2लाख छोटे बड़े ट्रकों की बिक्री अनावश्यक रूप से देश की 6 लाख गांव से 20 बड़े महानगरों 560 नगरों में कर दी गई। खरीदी का यह खेल लाखों करोड़ों रुपए के इस खेल मैं इंदौर में कमीशन में के रूप में सभी बड़े अधिकारियों, आयुक्त, महापौर और समीतर्ि??यों के पार्षदों को कारें मुफ्त में कमीशन में ही मिल गई। जबकि शहर में पिछले साल भर से चारों तरफ विषैली बदबू जिसमें मिथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनो व डाइऑक्साइड, आदि जहरीली गैस है। जो शाम को 4-5 बजे से लेकर रात 9-10 बजे तक जनता का दम घोंट रही है। इंदौर में। जो कि अंबेडकर नेहरू नगर मैं यह बदबू साल भर से महसूस की जा रही है। जिसके संबंध में मैंने 13 नवंबर 19 को जब यह बदबू पत्रकार कॉलोनी, से पलासिया चौराहे ब एमआईजी थाने तक आती हुई महसूस की, तो मैंने आसपास के लोगों से पूछ कर यह धारणा पुष्ट की, यह बदबू ना केवल सभी को आ रही है वरन सब परेशान भी हो रहे हैं। तब तत्काल अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रदुषण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी गुप्ता को फोन लगाया परंतु अहंकारी ने भी फोन नहीं उठाया। तो दूसरों को लगाया, पूछने पर मालूम पड़ा गुप्ता किसी का फोन नहीं उठाता। क्योंकि उसने सारे मंत्रियों को पैसा बांट दिया है। तो बदबू के संबंध में उनको बताया। कर्मचारियों को और प्रशासन को आगाह किया था जो 16 नव के पत्रिका में भी छपा। परंतु पत्रिका ने विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार लैंड फिल गैसों की कान्हा और सरस्वती नदी की सफाई के कारण बताया। दूसरी तरफ ओपी जोशी ने आधा सच बताया कि यह बदबू लंबे समय से दबे कचरे की जोकि शहर कें बीच में से बहने वाले नालों को कचरे से भराई और पाटने के कारण उत्पन्न हो रही है। जबकि सच की खोज जो मेरे सामने आई बदबू आने के कारणों का अध्ययन का निष्कर्ष यह है, कि घोर धूर्त कमीशन खोर नगर निगम के कर्मचारियों और इंजीनियरों ने मिलकर मोटा धन हड़पने अधिकांश मोहल्लों में, खाली पड़ी बगीचे की जमीनों खेलकूद के मैदानों खाली पड़े प्लाटों में अवैध रूप से कब्जा कर, नालों के आस-पास जो कचरा डंपिंग स्टेशन बनवाए हैं। जिन

पर पिछले 5 सालों में लगभग 500 करोड़ से ज्यादा स्वच्छता के नाम लगभग 300 करोड़ हजम कर बर्बाद कर दिया गया। जिनमें सारा कचरा इकट्ठा कर डंप और उसकी नष्ट करने की प्रक्रिया आदि किया जा रहा है। जैसे न्यू पलासिया के नाले के किनारे दबंग दुनिया के बाजू में एक डंपिंग स्टेशन बना हुआ है उसके आसपास चारों तरफ 2 किलोमीटर में बहुत बदबू फैल रही है दूसरा स्टेशन पंचम की फैल में नाले के किनारे, तीसरा स्टेशन एमवाई के पीछे हंस बस सर्विस के पास राज होटल के बाजू में ईसाई कब्रिस्तान के प्लॉटों पर बनाया गया। ऐसे सैकड़ों स्टेशन पूरे इंदौर शहर में बनाए गए जो शाम को 4-5 बजे से और रात में 9-10 बजे तक दिन ढलने से रात गहराने तक बदबू फैला कर 15 लाख की आबादी से ज्यादा लोगों को दम घोंट रहे हैं। सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर वहां बैठी गिद्धों की फौज जिसमें पार्षद महापौर निगमायुक्त पूर्व में मनीष सिंह से लेकर वर्तमान का आशीष सिंह और सभी सहायक, उपायुक्त व अन्य अधिकारी व कर्मचारी एक लाइन की जानकारी देना पसंद नहीं करते और आवेदकों को भटकाया और परेशान किया करते हैं। क्योंकि वह हर कदम रू. 1 का काम 10/- से रू. 20/- में होता है सब डकैतों की फौज को लूटना और खाना है। कोई सुनियोजित शहर का विकास कचरा डंपिंग सफाईकर्मी नहीं है। बस जहां जगह मिले वहां पर कचरा डंपिंग स्टेशन खाद बनाने के कार्यक्रम के नाम पर पैसा निकालो। और हजम करो। मेरे आजू-बाजू में एक संजय व अंबेडकर गार्डन और धारकर गार्डन है। इन तीनों में भी लाखों रुपए खर्च कर खाद बनाने के टांके और सेड बनाया गया पर उसमें आज तक किसी को काम करते हुए और बगीचों का कचरा डालते हो नहीं देखा गया। जहां बगीचे के कचरे डालकर खाद बनाई जा सके और ऐसा हुआ भी नहीं। बस बना बना कर खड़े करो। पैसा हजम करो। सीमेंट की सड़कों पर डामर की सड़क में डालो डामर की सड़कों पर सीमेंट की सड़कें डालो। मुफ्त वाईफाई इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए लगभग 200 करोड रुपए से ज्यादा के हर चौराहे पर खंबे खड़े किए गए 5 साल गुजर जाने के बाद में भी शहर को मुफ्त वाईफाई इंटरनेट की सुविधा नहीं मिली और उसमें लगभग 50 से 100 करोड़ का मोटा कमीशन हजम कर लिया गया इन हरामखोरों, महापौर मालिनी गौर से लेकर सभी पार्षदों निगम आयुक्तों उपायुक्तों सहायक आयुक्तों लेखा अधिकारी, बाबुओं आदि पर कोई भी लोकायुक्त की कार्रवाई इतने वर्षों बाद क्यो नहीँ हुई।

बेशक लोकायुक्त के सुकरों को भी निगम से महीना पहुंचता है। इसलिए वह भी सब चुप रहते हैं। शिकायतें ढेर पहुंचती हैं।सब मिल बांट कर खा रहे हैं। इसलिए कोई चिल्ला नहीं रहे हैं। जनता कल की मरती आज मरे इन्हें बस लूट से काम है। सफाई के, सड़क बनाने के, पानी पिलाने के नाम पर लूट, हर काम में, हर टेंडर में, खरीदी, निर्माण,, मरम्मत, ठेकेदारी, सब में हर कदम लूट का तांडव, सुविधाओं के नाम पर अपने अपने बालों को अंधों की रेवड़ी की तरह बांट दी जाती है।

जनता बेचारी मरने और लुटने के लिए ही पैदा हुई है।

बेलदार करोड़पति, बाबू करोड़पति, इंजीनियर हरभजन ने तो जमे रहने अय्याश नेताओं मंत्रियों आयुक्तों को लाखों रुपए की सुरासुंदरी की सेवाएं वर्षों से उपलब्ध करवाई है। तो कमाई अरबों में हुई।

तभी वह 25 साल से यहां जमा रहा और जब गले में लड़कियां अटक कर उसे बुरी तरह से निचोड़ने लगी तो वह चिल्लाया। अन्यथा 20-22 सालों से खेल सबको सुरासुंदरी की सेवाएं उपलब्ध करवाने के कारण सभी अधिकारी नेता मंत्री कर्मचारी खुश थे।

सुविधाओं का उपभोग कर ऐसे सैकड़ों गिद्धों को ना केवल इंदौर में बल्कि पूरे प्रदेश के नगर निगम पालिकाओं में पाल रहे हैं। सब सेवाएं महान घोर भूतपूर्व का मुख्यमंत्री दिग्गी दानव लेकर पालता था और अब उसका बेटा राजवर्धन सिंह उपभोग कर रहा है इसलिए वह सुअर भी ऐसे गिद्धों का स्थानांतरण नहीं कर रहा है। आखिर बाप के पद चिन्हों पर ही तो चलेगा। उसे सब से दोस्ती रख कर लूटना है और लुटाना है ताकि आने वाले कल में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने की चाहत तो है।

ऐसे सैकड़ों कर्मचारी अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर इंदौर में अजगर की तरह कुंडली मारकर जमे हुए हैं। और इन कुकर्मों से जनता को मौत के मुंह में धकेल कर मोटा पैसा हजम कर रहे हैं।

यहां पैसा हजम करो का 1 सूत्री कार्यक्रम सफाई कर्मियों से लेकर निगम आयुक्त महापौर तक का है। कल रहे न रहे। तो फिर इनकी निकंमी आपराधिक प्रवृत्ति की औलादे क्या करेंगी।

इंदौर प्रदूषण मंडल में बैठा हुआ क्षेत्रीय अधिकारी गुप्ता यह सूकर भी फोन नहीं उठाता। क्योंकि यहां आए नए कांग्रेसी भूखे गिद्धों मंत्रियों सज्जन वर्मा, तुलसी सिलावट, बाला बच्चन सबको टुकड़े डालकर पाल रहा है।वह। इसलिए जिसको जो करना है। वह करो।

शहर को जहरीली वायु के प्रदूषण से मारना हो तो मारो। जल स्त्रोतों में फैक्ट्रियों से निकले तेजाबी कचरे को जो पीथमपुर, देवास व प्रदेश के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से मध्यप्रदेश में लाया जा कर जल स्त्रोतों में भूमि में, नदियों, नालों, पाइप लाइनों में छोड़ा जाकर दूषित पानी से मारना हो तो मारो। बस पैसा बांटो जो करना है। सब करो। यहां की भेड़ों का झुंड, जनता, कुछ नहीं बोलेगी।

समाचार पत्रों के बिकाऊ भड़वे भास्कर पत्रिका नई दुनिया नवभारत यह सभी शौकीन मिजाज पैसे के ही हैं। सच जानकर भी सच नहीं लिखेंगे सभी भू माफिया, कालोनी माफिया, अपराधिक प्रवृत्ति के नेता अधिकारियों मंत्रियों के संरक्षणदाता और उनसे मोटी कमाई करने वाले हैं। जनता चिल्लाएगी, हल्ला मचाएगी, तो नेता, मंत्रियों, अधिकारियों, समाचार पत्र वालों की कमाई ही करवाएगी।

भारत का चंद्रमा पर यान उतारना पूर्ण नौटंकी और जन धन की बर्बादी

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यह सारा वातावरण पृथ्वी का ही था। क्योंकि दूर पीछे झाड़ झंखाड़ और रेगिस्तान दिख रहा था। बस मैंने इस सिद्धांत को सामने रख पूरी कहानी लिखी और दुनिया के अनेकों टीवी चैनल जिसमें डिस्कवरी भी था। सीएनएन बीबीसी को भी भेजी तो डिस्कवरी चैनल वाले उनके पीछे पड़ गए। और मालूम पड़ा कि अमेरिका ने वह सारा षड्यंत्र मन्च लगाकर धरती पर ही पूरा किया था। सारे फर्जी फोटो जारी कर अपनी उपलब्धियों और वैज्ञानिक प्रगति का दबदबा बनाने के लिए चंद्रमा पर उतरने की झूठी कहानी गढ़ी थी। वह कहीं नहीं गए थे उन्होंने कैलिफोर्निया के मरुस्थल में वे सारा सेट लगाकर सारी कारस्तानी से फोटो खींचे गए थे। जिसकी पोल डिस्कवरी चैनल ने बरसों पहले टीवी पर प्रसारित की थी। अमेरिका ऐसे कांड 1910 से बीमारियों को फैलाने की आड़ में औषधियों की भारी भरकम बिक्री, कृषि, चिकित्सा, अंतरिक्ष, रसायन, भौतिकी, युध्द, विधि, आदि सभी क्षेत्रों में कर अपना दबदबा बना व्यवसाय बढ़ाने में करता रहा है। मैंने भी हवाईजहाज उड़ाया है। बहुत सारी किताबें हवाई जहाज उड़ान से संबंधित और हवाई जहाज की तकनीकी पर पढ़ी हैं। हवाई जहाज पृथ्वी के वातावरण में हवा पर अपनी पक्षियों की भांति बनावट के कारण तैरता है। जिस में लगे पंखे या प्रपोलर, और जेट इंजन में वही प्रोपलर अंदर की तरफ होते हैं। जोकि पेट्रोल के इंजन से घूर्णन गति पैदा कर पंखों को घुमाते हैं। अंदर या बाहर। जो पृथ्वी के वातावरण में वायु को बाहर से अंदर खींच कर पीछे की तरफ फेंकते हैं। और वह पक्षी की तरह बना हुआ विमान डैनों के कारण तैरता हुआ रडर से नियंत्रित दिशा में आगे बढ़ता है। जमीन से उड़ान भरने और उतरने के लिए एलरान और दाएं बांये मुडने के लिए रडर काम करता है। जो कि पूंछ में होता है। बहुत सीधा सा सिद्धांत है कि, जब अंतरिक्ष में सब कुछ शून्य है। तो विमान काहे पर तैरेगा। किस ईंधन का उपयोग करेगा क्योंकि पृथ्वी के वातावरण में पेट्रोल ऑक्सीजन के साथ जलकर घूर्णन गति पैदा कर तैरता है। अंतरिक्ष में सब कुछ शून्य होने के कारण कोई भी ईंधन कार्य नहीँ करेगा। अग्नि उत्पन्न नहीँ होगी। रसायन क्रियाशील नहीँ होते। फिर पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 32,80,000 किलोमीटर है। पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलते ही वहां ना तो हवा है। ना किसी पिंड के त्वरण का गुरुत्वाकर्षण। बेशक अंतरिक्ष में रॉकेट लेजाकर वहां पर जो उपग्रह छोड़े जाते हैं। वे वहां रॉकेट ले जाकर अंतरिक्ष में छोड़ देता है। वे वहीं पर पड़े रहते हैं। और वहीं से अपनी उसी स्थिति में पढ़े रहकर रेडियो तरंगों का एंटीना के माध्यम से उपयोग कर हमारे मोबाइल सिस्टम दूरदर्शन इंटरनेट आदि को चलाने में सहायक रहते हैं। पर वे भी पृथ्वी की कक्षा से 1000-2000 किलोमीटर ही ऊपर तक जा पाते हैं। वैसे अधिकांश मानव निर्मित उपग्रहों की यह दूरी पृथ्वी से लंबवत 500 से 2000 किमी तक ही होती है। परंतु चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 32लाख80हजार किलोमीटर है कितना भी कश लगा लिया जाए कोई भी रॉकेट 10 20 हजार से ज्यादा अधिकतम 1 लाख किलोमीटर से आगे अंतरिक्ष में नहीं बढ़ सकता। यह सारी कहानियां पूरे विश्व के अमेरिका, फ्रांस, चीन, इंग्लैंड, रूस और भारत की केवल जनता के पैसे का दुरुपयोग कर, वहां की निकम्मी, निठल्ली, भ्रष्ट सरकारों का अपने भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने उस पर अपनी उपलब्धियों का मानसिक दबाव बनाने की है। जो केवल झूठ और झूठ का पुलिंदा है। जनता के पैसे का दुरुपयोग और जनता को मूर्ख बनाने का षड्यंत्र है। जो आज नहीं तो कल इस पाखंड का भी खुलासा होगा ही होगा। धरती पर देश की जनता और बच्चे भूख से बेहाल हैं। 30 करोड़ बेरोजगार हैं। उन धूर्त राजनीतिज्ञों और वैज्ञानिकों को उसकी चिंता कदापि नहीं। उन्हें अपनी मौज मस्ती और प्रयोगशालाओं में उपलब्धि दिखाने में ही उनकी शान है।

60% खा. सु. अ. टुकड़े डालकर बैठे हैं, 10 साल से ज्यादा से एक ही स्थान पर

शुद्ध के लिए युद्ध नहीं, शुद्ध वसूली का युद्ध

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा लगवाये गये खाद्य सुरक्षा व मानक अधि 06, का उद्देश्य ही था, कि वह पानी और शीतल पेय में भी कीटनाशकों के शुद्ध जहर भी बेचे तो भी टुकड़खोर सरकारी तंत्र उनकी पहरेदारी करता रहे। दूसरी तरफ छोटे उत्पादकों, विक्रेताओं, को कानूनों के मकड़जाल में उलझा कर, सजा और मोटे दंड की धमक की आड़ में मोटी वसूली करना, ताकि वो करोड़ों लोग अपना काम बंद कर दे।

पूरे प्रदेशों व पूरे देश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि 06 को 11 अगस्त 11 से लगाये जाने के बाद किसी भी बड़ी और बहुराष्ट्रीय कंपनीयों जो कीटनाशक, व अन्य विषैले घातक रसायनों का, शीतल पेय जिसमें लिम्का, थम्सप, कोक, कोला, माजा, ताजा, जैसे सैकड़ों, खाद्य पदार्थों में पिज्जा, मैगी, नूडल्स, चिप्स, फिंगर चिप्स, चॉकलेट, बिस्कुट, बर्गर जिसमें नकली दूध मक्खन व अन्य घातक पदार्थ होते हैं। जैसे हजारों के विरुद्ध, उनकी सारी खाद्य वस्तुओं में क्योंकि उनकी करोड़ों की सौदेबाजी, देश व प्रदेश की राजधानी में वहां बैठे मंत्री और अधिकारियों से हो जाती है। इसलिए उनके किसी भी प्रकार के नमूने आदि नहीं लिये जाते। और यदि ले भी लिए गए सब कुछ नकली और घातक होने के उपरांत भी उनके सारे नमूने निजी, सरकारी और सार्वजनिक प्रयोगशालाओं में धन बांट कर आसानी से पास हो जाते हैं ।और अगर फिर भी फेल हो गए तो भी जिले का घोर भ्रष्ट डकैत मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला दंडाधिकारी को भी खरीद लिया जाता है। अर्थात बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भ्रष्टाचार का डंका चारों ओर बज रहा है।

अब सरकार बदल चुकी है भाजपा के नेता व उनके पाले हुए मिलावटी नकली दूध दही घी मक्खन व उसी से निर्मित आइसक्रीम मिठाई आदि निर्मित पदार्थों को और मिलावटी खाद्य वस्तुओं को संरक्षण देने वाले और उनसे महीना वसूली करके मंत्रियों अधिकारियों और नेताओं को टुकड़े डालने व बांटने वाले लगभग 265 खाद्य सुरक्षा अधिकारी सहायक खाद्य निरीक्षक में से लगभग 154 खाद्य निरीक्षक पिछले 10 सालों से एक ही शहर में एक ही स्थान पर डटे हुए हैं आखिर स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने क्या किया इसके लिए? उनमें से 50% तक के स्थानांतरण तक नहीं किये। उन सब से वसूली की जो औसतन रू 20से 40 लाख तक हर खाद्य निरीक्षक से थी, की और सबको वहीं वसूली के लिए छोड़ दिया। अर्थात लगभग 50 से 80 करोड़ की कमाई की गई। फिर ये नकली दूध, दही, मक्खन, मावा, पनीर, घी, के साथ आइसक्रीम, मिठाईयां आदि के बारे में मिलावटीओं को प्रदेश छोड़ दो।

वह तो प्रदेश नहीं छोड़ेंगे बस खाद्य निरीक्षक सह सुरक्षा अधिकारी बसूली दुगुनी करेंगे। फिर सबसे महत्वपूर्ण सांची और अमूल जो कि शासकीय सहकारी संस्थाएं हैं। और अपने माल को बहुत शुद्ध और ताजा माल बता रहे, अर्थात दूध घी मक्खन दही पेड़ा व अन्य उत्पाद बेचती हैं। पूर्णता विदेशी आयात दूध के पाउडर पर निर्भर करती हैं। साची जो दूध एकत्रित करता है पूरे मध्यप्रदेश में उससे 2 गुना से 3 गुना बेचता है। आखिर कहां से आ रहा है इतना दूध? जब इतने दुधारू जानवर ही नहीं। दूसरी तरफ सांची सहकारी संस्थाएं जो शासन के सहकारिता विभाग के अंतर्गत चलती हैं। वहां बैठे घोर भ्रष्टाचार और जाल साज जो दूध खरीदते हैं। वह भी नकली रसायनों से बना ही होता है। उस नकली दूध का भरा हुआ टैंकर 2 साल पहले इंदौर के मांगलिया में पकड़ा गया था।साथ ही जो दूध अच्छा आता है उसको वहां बैठे जाल साज दूध की क्रीम निकाल कर और सुखा कर पाउडर बना कर बड़ी-बड़ी कंपनियों को ऊंचे भाव में बेंच देते हैं। असली दूध के 250 से 300 लिटर के पैकेट केवल उच्चाधिकारियों नेताओं को ही आपूर्ति किए जाते हैं।

जबकि आम जनता को विदेशों से आयातित सस्ते पाउडर का दूध बनाकर ही, खिलाया पिलाया जाता है। सांची गोल्ड में जो ताजा फुल क्रीम मिल्क के नाम से बेंचा जाता है। 6 से 8% वसा या फेट की बात की जाती है। पूर्णतः बकवास है। उसमें वसा मात्र 2 से 3% जो कि आयातित बटर आइल मिलाया जाता है। की होती है। सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर वहां बैठे हरामखोर जाल साज बहुत ही बदतमीजी से पेश आते हैं। और जानकारी देने से सहकारिता के अंतर्गत साफ मना कर देते हैं।

इस खाद्य विभाग से अमूल और सांची के अलग-अलग दूधों के नमूने लेने की जानकारी मांगी गई तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हमारे पास वहां के नमूने लेने की क्षमता नहीं है। यदि हम दूध के सेंपल लेने जाते हैं। साची या अमूल के तो सीधा फोन कलेक्टर का पहुंचता है कि तुम्हें यहां नौकरी करनी है या नहीं क्योंकि कलेक्टर सभी सहकारी संस्थाओं का अध्यक्ष होता है। हर जिले का। जब इस बात को मैंने कुछ विधायकों के माध्यम से ही विधानसभा में लगवाया तो सरकार ने स्वीकार किया कि 1985 से ही साची और अमूल की कोई नमूने नहीं लिए गए। यह सारा गोरखधंधा कभी बंद होने वाला नहीं क्योंकि जब दुधारू गाय भैंस ही नहीं तो 7.5 करोड़ की मध्य प्रदेश की आबादी को दूध कहां से मिलेगा? फिर सांची के मामले में तो डॉक्टर भी दूध मुंहे बच्चों को सांची का दूध पिलाने से मना करते हैं। यह सच है सांची का। वर्तमान हालात यह हैं कि लगभग साढे सात करोड़ की आबादी पर पूरे मध्यप्रदेश में एक करोड़ दूध देने वाली गाय भैंस भी नहीं है। फिर कुल दुधारू पशुओं की संख्या के 40ढ पशु ही दूध देते हैं औसतन 3 लीटर सुबह शाम। अर्थात मुख्यमंत्री कमलनाथ और स्वास्थ्य मंत्री इंदौर के तुलसी सिलावट केवल यह नौटंकी मोटी वसूली के लिए कर रहे हैं।

विधानसभा में नकली दूध वा दूध से बने दही घी पनीर मावा मक्खन मिठाइयां मिल्क केक आइसक्रीम के साथ अन्य खाद्य पदार्थों के मामले को उठाकर पटल पर रखने का कोई औचित्य नहीं है। उल्टे ही यह इनकी मोटी कमाई का साधन बन गया जबकि यह बात हर मंत्री और मुख्यमंत्री भी जानता है परंतु कार्यवाही की अपेक्षा यह भय फैलाकर पूरे प्रदेश के व्यापारियों से मोटी वसूली ही की जाएगी जबकि

कांग्रेस सरकार के आने के बाद मध्य प्रदेश की जनता को यह उम्मीद थी कि 15 साल से पूरे प्रदेश में हो रहा भ्रष्टाचार का तांडव कुछ कम होगा और जनता को कुछ राहत मिलेगी। इसके विपरीत कांग्रेसी जो 15 साल से भूखे बैठे हुए थे उन्होंने भी आते ही भ्रष्टाचार का तांडव शुरू कर दिया स्वास्थ्य विभाग को मिले जिसके अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं औषध विभाग आता है जहां पर 10 से 15 सालों से खाद्य निरीक्षक एवं औषधि निरीक्षक मोटा महीना बांटकर एक ही जिले में जमा हुए हैं। बदले में जनता को 80% मिलावटी नकली रसायनों से बना हुआ दूध दही घी पनीर मावा मिठाइयां पिछले 15 सालों से बिक रही है और जिम्मेदार खाद्य निरीक्षक हाथों से वसूली करते हुए रुपए 25 से 50लाख प्रतिवर्ष बांटकर आराम से ही मिलावटी ओं और दूषित खाद्य पदार्थ बेचने वालों को संरक्षण डेकर जनता को प्रदेश में बने 5000 से ज्यादा अस्पतालों नर्सिंग होम आदि की मोटी कमाई करवा रहे हैं। इंदौर में ही बैठे स्वामी और खेड़कर जो पिछले 10 11 सालों से ज्यादा समय से ही इंदौर में ही कुंडली मारे बैठे हैं। लगभग 5000 दुकानों सही मोटी वसूली कर शहर में 80% नकली दूध दही घी पनीर मावा मिठाइयां, मिल्क किक आइसक्रीम अन्य खाद्य सामग्री खुले में बिकवा रहे हैं जिसमें उनका साथ देते हैं संबंधित क्षेत्र का एसडीएम और भोपाल स्थित खाद्य प्रयोगशाला जहां विश्लेषक भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र और डिग्री के दम पर नौकरी करते हुए मोटी वसूली कर सारी नकली और मिलावटी खाद्य वस्तुओं के नमूने पास कर ऐसे व्यापारियों दुकान उद्योगपतियों को जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की खुली छूट देते हैं यह बात समय माया अपनी समाचार पत्र में लगातार पिछले कई वर्षों से उठाने के बाद और व्हाट्सएप पर संदेश भेजने के बाद भी प्रदेश के नए स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट सुनने और ध्यान देने को तैयार नहीं क्योंकि वह केवल खाद्य एवं औषधि विभाग से ही करोड़ो की वसूली कर चुका है। साकेत नगर चौराहे पर आनंद बाजार में महावीर डेयरी का पनीर का नमूना लिया गया। उसके बाजू में गीता डेयरी का नमूना नहीं लिया गया। उससे वसूली करके खाद्य निरीक्षक स्वामी, खेड़कर, सुधाकर व उनकी टीम का विरोध था। मैं पोलो ग्राउंड में भारत चिलिंग सेंटर जहां पर नकली दूध एवं नकली मावे का निर्माण किया जा रहा है। शर्मा दुध व मावा मावे की फैक्ट्री है। जिस पर आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की गई आरएनटी मार्ग पर राधा कृष्ण दुध दही व मावा भंडार जो जो नकली मिल्क केक व नकली पनीर बनाता है। उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं की पिछले 10 सालों में इन तीनों के इन सब के मोबाइल कॉल डिटेल निकाली जाए तो उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी इन तीनों की जांच एसटीएफ को दे दी जाए उनकी सच्चाई सामने आएगी 11 सालों,2008 से इंदौर में हुए हैं स्वास्थ्य मंत्री को धन देकर और कमिश्नर से सेटिंग करके, सब आराम से वसूली में व्यस्त हैं। इन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।

इंदौर की राजमोहल्ला में 11 डेरियां जिन पर पूरा नकली दूध बिकता है उन पर आज तक कार्रवाई नहीं की गई है। माल गंज चौराहे पर राजकुमार दूधवाला पूरा मिलावटी दूध ऊंचे दामों पर बेचा जाता है बाबा वाले के यहां चंदू खेड़ी और मुच्छु खेड़ी से नकली मावा आता है जो सुबह 9:00 बजे इनकी दुकान पर विक्रय हेतु उपलब्ध होता है।

नकली मावा और नकली दूध बनाने का बहुत बड़ा गढ़ है। जहां से स्वामी और खेड़कर मोटी वसूली करते हैं। यही कारण है कि विगत 10 वर्षों से कार्यरत स्वामी, खेड़कर एवं सभी अन्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी इंदौर में जमे हुए हैं।

पिछली बार राखी पर गौरी नगर में 180 किलो नकली मिठाई जप्त की गई थी स्वामी और राणा के द्वारा उस प्रकरण में मोटा लेनदेन करके पूरा प्रकरण साफ कर दिया गया। इतने सारे कर्मकांड करने के बाद भी इनके स्थानांतरण नहीं हो रहे हैं। उज्जैन रतलाम ग्वालियर भोपाल जबलपुर रीवा मिलावटी दूध के नाम पर जो कि पूरे प्रदेश में व पूरे देश में बन रहा है। यह मामला उठाकर जानबूझकर मोटी कमाई और वसूली का रास्ता सरकार ने खोल दिया है। जबकि सरकार स्वयं जानती है और यह बात संयुक्त राष्ट्र संघ में व अमेरिका में भी उठ चुकी है कि भारत में 80% दूध नकली बिक रहा है। पर यहां की सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती बदले में सभी खाद्य निरीक्षकों से मोटी वसूली करके उन्हें 10 साल 15 साल तक एक ही जगह पर दोनो हाथ से लूटने और जमा कर रखती है। इसकी दूसरी तरफ भोपाल में बैठे खाद्य जांच प्रयोगशाला में जितने भी खाद्य विशेषज्ञ हैं। उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती यहां तक कि उनके पास पर्याप्त योग्य स्टाफ होने के बावजूद भी उन्हें दलों में बिठा के रखा गया है। जानबूझकर नमूने पास करते हैं और मोटी वसूली करते रहते हैं बदले में सरकार उसमें बैठे हुए आयुक्त संयुक्त आयुक्त और स्वास्थ्य मंत्री मोटी वसूली करते रहते हैं।

वन विभाग में वनेलों का राज

कांग्रेस के शासन में कमलनाथ उसके 15 साल से भूखे घोर भ्रष्ट मंत्री अच्छी तरह से जानते हैं, कि अपनी सरकार का कोई भरोसा नहीं कि कब तक चलेगी।

लूट सके तो लूट अंत काल पछतायेगा मंत्री पद और गद्दी जाएगी छूट

इसलिए कांग्रेसी सरकार का हर मंत्री अपने-अपने विभागों में उल्टी-सीधी पदस्थापनाएं और अपने भाई भतीजे व मोटा धन देने वालों को चाहे वह कितना भी भ्रष्ट, जाल साज, उस पर कितनी भी जांचे क्यों न लंबित हों, कामचोर और मूर्ख ही क्यों ना हो। खास खास जगह पर जमाने में जुटे हुए हैं।अब वन विभाग में ही लीजिए। उमंग सिंघार ने हाल ही में इंदौर के गुरुनानक टिंबर मार्केट इंदौर जो प्रदेश का सबसे बड़ा अवैध वृक्षों की काष्ठ कटाई चिराई और बिक्री का बड़ा अड्डा है। समय माया की लंबी वर्षों की मेहनत के बाद 53 प्रजातियों के पेड़ों की कटाई को उच्च न्यायालय ने रोक दिया। बेशक उच्च न्यायालय में प्रकरण दूसरों ने लगाये थे। और जिनके पास वह 53 पेड़ों की लकड़ी है। उसको जप्त करने का आदेश दिया।उस आदेश के पालन की अपेक्षा वन मंत्री उमंग सिंघार ने जो दूसरों पर बड़े आरोप लगाते हैं। ने उस बाजार के अध्यक्ष दानवीर सिंह छाबड़ा के साथ मिलकर लगभग पिछले चार-पांच दिनों में, 300 से ज्यादा व्यापारियों से एक करोड़ रुपए की वसूली कर उस लकड़ी को खपाने और रफा-दफा करने के लिए पूर्ण संरक्षण देने का वादा कर दिया।दूसरी तरफ अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अपने खास भारतीय वन लूटो खाओ सेवा के अधिकारियों जिसमें मुख्य वन संरक्षक सीएस निनामा को एक साथ 3 पदों के प्रभार सौंप दिए। जिसमें इंदौर उज्जैन और रतलाम वन वृत्त हैं। जिसके अंतर्गत करीबन 10 से ज्यादा वन मंडल हैं सबको रुपए 10-10 लाख हर महीने देने का आदेश दे दिया गया है। इसी प्रकार वन मंडल अधिकारी एम एल हरित को झाबुआ और इंदौर का प्रभार सौंप दिया गया। जबकि दोनों ही पद वन संरक्षक के हैं। इसी प्रकार वन मंडल अधिकारी उइके को धार और बड़वानी का प्रभार सौंप दिया गया है। इंदौर के उप वन मंडल अधिकारी एल्विन बर्मन के पास इंदौर और महू उपवन मंडलों का प्रभार है। जबकि बर्मन पर लोकायुक्त जांच लंबित है। जानबूझकर इन पदों पर अन्य पात्र अधिकारियों की अपेक्षा मोटा धन लेकर पूरे मध्यप्रदेश में अनेकों अपने खास जाति भाई अधिकारियों के पास दो से तीन जगह के प्रभार सौंप रखें हैं। ताकि मोटी वसूली आसानी से बिना हो हल्ले के की जा सके। अंदाज लगाया जा सकता है कि जब 1-1 वन मंडल अधिकारी दस2 लाख रुपए महीने अपने वरिष्ठ को देगा तो स्वाभाविक है काफी काला पीला भ्रष्टाचार और जालसाजी करेगा। शिवराज सिंह सरकार ने सन 2006 में आते ही 55 पेड़ों की कटाई की छूट दे दी थी। इसके चलते उसकी आड़ में अवैध रूप से पूरे प्रदेश में प्रति वर्ष 3 से 5 करोड़ वृक्षों के जंगलों को काटने रास्ता साफ हो गया था। यही कारण था कि पूरे प्रदेश के सारे फर्नीचर बनाने वाले लकड़ी के बाजार में आसानी से लकड़ी बिक रही थी। अकेले इंदौर के गुरु नानक टिंबर मार्केट में औसतन प्रतिदिन 300 ट्रैक्टर ट्रॉली बड़े वृक्षों की हरी लकड़ी लाकर बेची जाती है। मेरे द्वारा अपने समय में आज समाचार पत्र में और ँर्‍र्ङ्क्रष्ठ्य की साइट पर इस बात को पिछले 12-13 सालों से लगातार उठाया गया। हर बार उस पत्र को जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय से जारी हुआ था। बार-बार झूठा बता कर लकड़ी कटाई को अवैध बताकर बंद करना बताया जाता था। इसके विपरीत स्वयं वन विभाग पूरे प्रदेश का उस 55 प्रजाति के बड़े वृक्षों की लकड़ी को खुले में कटवा कर बिकवाता रहता है। और सब के बारे न्यारे करोड़ों रुपए में जो वन मंत्री प्रधान मुख्य वन संरक्षक तक को दोनों हाथों से चारों तरफ से पहुंचते और मिलते हैं। बाद में शिकायत करने पर इस महत्वपूर्ण तथ्य को यह कहकर झुठलाया जाता था, कि वह सागौन के पेड़ नहीं है। हमारा वन विभाग केवल सागौन के पेड़ों की कटाई के लिए जिम्मेदार होता है। जबकि वहीं वन विभाग पिछले कई सालों से जिसमें सन 16, 17, 18 में 2, 6, 8 करोड़ पेड़ लगाने का जिस में सागौन नहीं होती थी दावा करता था और उसमें अरबों रुपए की धनराशि जनता से विक्रय कर पेट्रोल-डीजल शराब स्टैंप ड्यूटी परिवहन शुल्क आदि में मनमानी तरीके से थोपे गए करों मे वसूली गई। बर्बाद की जाती थी। जबकि पिछले 13 वर्षों में वर्षा ऋतु में लगाए गए वृक्षों की कुल रोपण किए गए वृक्षों का 20 -25% भी अक्टूबर-नवंबर के बाद नहीं बचता था। इसका वन विभाग में इसका 50 से 80ढ तथा लूट में और भ्रष्टाचार में हजम कर लिया जाता है।इसका दूसरा पहलू यह है कि वृक्ष कोई सा भी हो। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर ऑक्सीजन उत्सर्जित करता रहता है। इसके साथ ही छाया धरती पर आंधी, तूफान और धूप के प्रभाव को कम करने के साथ धरती की नमी बनाए रखने में बाढ़ और बरसात के पानी को रोकने में अत्यधिक व प्राकृतिक तरीके से प्रकृति में अधिक कारगर होते हैं और जो वृक्ष सड़कों के किनारे लगाए जाते हैं। जैसा कि हर सड़क की डीपी आर में व्यवस्था की जाती है और फोर लेन सड़कों में तो जानबूझकर 10 से 20 फुट चौड़ी जगह इसीलिए बीच में छोड़ी जाती है और दोनों तरफ 30-30 फुट जमीन केवल वृक्षारोपण के लिए ही छोड़ी जाती है। ताकि वहां वृक्ष लगाकर सामने से आने वाली वाहनों के तीखे प्रकाश और ध्वनि को कम करने के साथ सड़कों पर धूप, बाढ़ और वर्षा के पानी के प्रभाव को कम किया जा सके। साथ ही दोनों तरफ वृक्ष होने से हरियाली से चालक को आंखों और मस्तिष्क पर ठंडकता का प्रभाव महसूस होता रहे और दुर्घटनाएं कम से कम हों। उच्च न्यायालय की इंदौर शाखा ने जो निर्णय देकर वृक्ष काटने से प्रतिबंधित किया है। जिसकी प्रति जो समाचार पत्र में छपी है ऊपर दी गई है। उससे वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों से लेकर भू माफिया, वृक्ष माफिया, अवैध लकड़ी माफिया को काफी तकलीफ महसूस हो रही होगी। पर राजस्व क्षेत्रों में भी पटवारी और तहसीलदार की जिसमें वह मोटी वसूली कर ही आज्ञा से वृक्ष काटने को रोका जाना चाहिए।

साप्ताहिक समय माया

सूचना अधिकार अधिनियम को बना रहे भोथरा अपने परिपत्रों से

पेज 1 का शेष

इसलिए यहां बैठा हुआ भारती प्रताणना सेवा का अधिकारी किसी को भी सूचना के अधिकार में जानकारी नहीं देता और यह जालसाज अपनी अपील स्वयं सुनने का पात्र होता है। इसलिए वह अपील रद्द कर दी जाती हैं। मध्यप्रदेश का सामान्य प्रशासन विभाग जो सारे प्रदेश के भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारियों की उंगलियों और इशारों पर उनके टुकड़ों पर पलता है। वहां बैठे गिद्धों की फौज, टुकड़ी खाकर नए-नए परिपत्र जारी करती है जिसमें इन हरामखोर सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जो कि लोक सूचना अधिकारी है धारा 19 सूचना के अधिकार अधिनियम की को ही जिसे संसद में पास किया गया था उसकी धज्जियां बिखेरते हुए इन हराम खोरो, अपने मन से ही अपनी जालसाजीयों व भ्रष्टाचार को छुपाने परिपत्र जारी कर दिए। इन जालसाजों ने परिपत्र जारी कर उसको उसका अपीलीय अधिकारी बना दिया ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री जो कि लोक सूचना अधिकारी है। वहां उपयंत्री सहायक यंत्री को लोक सूचना अधिकारी और कार्यपालन यंत्री को उसका अपीलीय अधिकारी बना दिया। यही हाल इन हरामखोर सामान्य प्रशासन विभाग के लोगों ने उप संचालक कृषि को उसका अपीलीय अधिकारी बना दिया। साथ में उप संचालक उद्यानिकी का, शिक्षा विभाग का अपीलीय अधिकारी भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को बना दिया गया। जबकि कानूनन उसी विभाग का वरिष्ठ अधिकारी लोक सूचना अधिकारी होना चाहिए था जिसमें गले के उद्यान की के उपसंचालक का अपीलीय अधिकारी संयुक्त संचालक होना चाहिए था वही हाल शिक्षा विभाग में उनका वरिष्ठ अधिकारी संभागीय स्तर का संयुक्त संचालक होना चाहिए था उसी प्रकार कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी का वरिष्ठ अधिकारी अधीक्षण यंत्री होना चाहिए था खनिज विभाग का, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, महिला बाल विकास का, कोष एवं लेखा का, परिवहन का भी अपीलीय अधिकारी जिलाधीश को बना दिया गया है। जबकि उनका वरिष्ठ संयुक्त संचालक या क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी होना चाहिए था। जिलाधीशों को जिनमें अपीलीय अधिकारी बनाया गया है। वह हरामखोर भी अपने आपको जिले का मालिक समझते हुए अपील जैसे छोटे से काम को जिसमें कोई कमाई नहीं होना है। छोटे जिलों में सहायक जिलाधीश को सौंप देते हैं और वह सहायक जिलाधीश आराम से उन अधिकारियों से महीना खाता है। इसलिए वह जालसाअ मक्कार वह सारी अपीलें रद्द कर देता है। इस प्रकार से सामान्य प्रशासन विभाग पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार को पालता पोसता और जालसाजियों को फैलाने में मदद करता है। हाल ही में सामान्य प्रशासन विभाग ने जालसाजी पूर्ण तरीके से धारा 6(3) को भोथरा बना दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने एक परिपत्र क्रमांक/ 667/1056/2016 दिनांक 08:09:19 जारी किया है। यथार्थ में सत्ताधीशों जो अपने आप को खुदा मान लेते हैं। जबकि यह सूकरों की फौज भी कानून से कानून का पालन करने के लिए जन धन से वेतन लेते हैं। पर यह गिद्धों की फौज अपनी लूट खसोंट भ्रष्टाचार और जल साजियों को बरकरार रखने अपने मन से ही कानून की धज्जियां बिखेरते हुए परिपत्र जारी करते रहते हैं और यही कारण है की पंचायत का एक अदना सा सचिव भी इन चुरकटों की सह पर चुरकटों को टुकड़े डालकर करोड़पति हो जाता है। बदले में जनता से नेता अधिकारी करों से, शासकीय सेवाओं की शुल्क वृद्धि से दोनों हाथ से लूटकर अपनी लूट का तांडव करते रहते हैं।

विनाश पुरुष मोदी ने देश की कबाड़ कर दी अर्थव्यवस्था

पेज 1 का शेष

इसी प्रकार अमेरिका में इसने पहले मैजिक मोदी का कार्यक्रम जिसमें भारत के लगभग रुपए 60 लाख करोड़ बर्बाद किए मात्र वहां अपनी पाखंड पूर्ण नौटंकी और प्रशंसा के लिए बर्बाद कर दिए गए। जिसमें वहां के मीडिया को 4 महीने पूर्व खरीदने मैं अपनी तारीफ में छपवाने जनता की भीड़ लाने मैं बर्बाद किया। दूसरी बार जीतने के बाद पुनः हाउडी मोदी का कार्यक्रम किया ट्रंप की अगली चुनावी जीत को पक्का करने भारतीयों को वोट दिलवाने और अपनी पाखंड पूर्ण नौटंकी दिखाने के लिए जिसमें डेढ़ लाख करोड़ डॉलर जो भारतीय रुपए में 108 लाख करोड़ रुपए होते हैं बर्बाद किए। जबकि ट्रंप मंच से हटते ही इसका मजाक पाकिस्तान के साथ काश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की बात कर उड़ाता था। जिसके बारे में राहुल गांधी ने भी एक बार पूछा था कि आखिर डेढ़ लाख करोड डॉलर मोदी जी बैंक से लूटकर अमेरिका में बर्बाद कर कर आए। परंतु उसे पप्पू कहकर यह भेड़िया झुंड पार्टी के लोग उसका मुंह बंद कर देते हैं। परंतु सच सामने ही दिखता है।

इसने फ्रांस से 10-20 करोड़ डॉलर के कबाड़ा राफेल लड़ाकू विमान प्रति विमान 1650 करोड़ में 36 विमान जिसमें 59700 करोड़ डॉलर अपने पूंजीपति आका अंबानी के माध्यम से खरीदें। इस कबाड़ की वास्तविक कीमत कबाड़ी के हिसाब से $10लाख भी नहीं थी। जबकि अमेरिका ने दूसरी तरफ पाकिस्तान को $860 करोड़ में अट्ठारह f-16 लडाकू विमान उधारी में दिए। जैसा कि मैंने पूर्व में लिखा था की है 10-20 लाख डालर से ज्यादा का नहीं। पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा 860 करोड डॉलर में अट्ठारह विमान देने की घटना ने इसको पुष्ट कर दिया। अमेरिका और रूस की बार-बार अपनी मौज मस्ती के लिए यात्राएं देश की अर्थव्यवस्था पर और 132 करोड जनता पर कितनी भारी पड़ रही है।यह इसके सत्ता से हटने के बाद मालूम पड़ेगा। बदले में रिजर्व बैंक जिसकी रिजर्व को कभी इंदिरा गांधी ने 1971 के युद्ध में भी हाथ नहीं लगाया था। मोदी ने उसके रु41लाख करोड़ की आरक्षित निधि से साडे 39 लाख करोड़ निकाल लिए 1.76 लाख करोड़ बैंकों द्वारा दिया गया लाभ के नाम पर कभी बैंकों को देने के लिए कभी योजनाओं के लिए कभी विकास के नाम पर पर इस हरामखोर विनाशकारी जालसाज ने यथार्थ में वह सारा पैसा अपनी विदेश यात्राओं में और हथियारों का कबाड़ा पाकिस्तान का भय दिखाकर अपने आकाओं के माध्यम से उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए खरीदने में बर्बाद किया। लोकसभा चुनाव से पूर्व रिजर्व बैंक का 280टन सोना गिरवी कर दिया। बेशक इस पैसे को निकालने के लिए उसने दो रिजर्व बैंक के गवर्नर को बदला। कहानी यहीं खत्म नहीं होती उसने सरकारी तेल कंपनियों को जिसमें सरकार की भागीदारी 53.6% है के सार्वजनिक शेयर बाजार में बैचकर लगभग 3लाख करोड रुपए इकट्ठे करने की नीति पर काम चल रहा है।

अपने आका अंबानी के चरणों में लोट लगाने के कारण इसने बीएसएनल को, तेल कंपनियों, जिसमें बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, ओएनजीसी, गैल व अन्य सरकारी कंपनियां इसमें विद्युत उत्पादन की एनटीपीसी स्टेट बैंक व अन्य बैंकों को उनके लाभ के लिए बर्बाद किया।

बैंकों को जिसमें स्टेट बैंक को रिलायंस के हवाले कर दिया। बड़ी 29 सरकारी बैंकों को विलय कर 12 बैंकों में बदलने की साजिश के पीछे इसका मूल उद्देश्य गरीब जनता की कमाई की जमाओं को काले धन के नाम पर हड़पना ही है। जबकि काले धन के नाम पर नोट बंदी की गई थी। जिसमें काला धन तो नहीं आया बल्कि 1000 के नोट को खत्म कर 2000 के नोट को चलाने से बड़े जाल साज पूंजी पतियों उद्योगपतियों जो से चंदा देते थे और नेताओं अधिकारियों को काला धन इकट्ठा करने में ज्यादा सुविधाजनक हो गया। इसके विपरीत नोटबंदी में गरीबों का धन निकालने और उसको सुरक्षित रखने के नाम पर जो जनधन खाते खुलवाए थे। उन 20 करोड़ खातों का साडे चार लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों को दिए गए ऋणों से डूबती बैंकों को न्यूनतम शेष के नाम पर गरीब 50 करोड़ जनता के हजम करने का मौका अवश्य मिल गया। गरीब जनता हाथ मलती रह गई। इस चुरकट ने जनता को कंगाल बना कर उसके खास पूंजीपतियों और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का गुलाम बनाने के षडयंत्र अभी खत्म नहीं हुए हैं। यह जानकर भी की 132 करोड़ जनता के सर्वोच्च न्यायालय के रोक के आदेश के बाद भी आधार कार्ड के डाटा के साथ, देश की केंद्र व सभी राज्यों की सरकारों के सभी मंत्रालयों का, बैंकों, बीमा कंपनियों, यहां तक कि रक्षा मंत्रालय और पुलिस की साइट तक सुरक्षित नहीं है। और डाटा सारा भारत में रोकने सुरक्षित करने की व्यवस्था नहीं होने के बाद में भी जनता के आधार कार्ड के साथ सभी बैंकों के 200 करोड से ज्यादा खातों जिसमें हर सेकेंड 5 हैकर्स आक्रमण करके जनता को लूट रहे हैं। देश में पिछले साल 60 लाख ऐसे बैंक खातों पर साइबर अपराधियों ने आक्रमण कर चुपचाप लगभग तीन लाख करोड़ से ज्यादा की डकैती डाली। ना सरकार कुछ कर पाई और ना ही उसकी साइबर पुलिस। इसके विपरीत यह गिद्ध जनता को उसका आधार कार्ड बनवाने, उसे पैन कार्ड से, संपत्तियों, वाहनों, बैंकों से लेकर राशन कार्ड, स्कूल की फीस, तक को जोड़ने पर तुला हुआ है। जबकि इसके विपरीत यह सारी जानकारियां पूरी दुनिया के साइबर अपराधियों के हाथ में पहुंच चुकी हैं। उससे सुरक्षा के लिए इन जालसाजों के पास कोई उपाय नहीं। सारा डाटा माइक्रोसाफ्ट गूगल के पास इकट्ठा होता है। परंतु इन्हें अपनी डकैती डालनी है इसलिए सब को जोड़ने पर और सब का डाटा इकट्ठा करने पर तुले हुए हैं। ताकि जन-धन को उसकी संपत्तियों को लूट सके और अपनी विदेशों में मौज मस्ती कर सकें।

बेशक 70 साल से उलझी हुई कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने और उसको संविधान लागू ना होने की धारा 370 को उन्होंने खत्म कर दिया परंतु यहां उनका पावन उद्देश्य वहां की जनता को राहत पहुंचाना नहीं बल्कि वहां कश्मीर जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है की भूमि पर कब्जा कर उद्योग लगाना बड़ी होटलों और बड़े शॉपिंग मॉल लगाना था जिसे मैंने 370 हटाने के बाद अपने व्हाट्सएप से जनता को भेजा था। उस समय मेरी काफी आलोचना हुई थी। पर अब यह सच सामने आ रहा है कि उसके बड़े पूंजीपति होटल व अन्य उद्योग लगाने के लिए जिसमें अमित शाह का बड़ा हिस्सा होगा जा रहे हैं। इसी प्रकार राम मंदिर के मुद्दे को भी जो पिछले 70 साल से अटका हुआ था सर्वोच्च न्यायालय पर जाएं। उन्होंने अपनी मनमर्जी के इच्छा के अनुसार न्यायधीश बैठा दिए हैं। फैसला अपने पक्ष में करवा लिया। इन 2 उपलब्धियों की आड़ में जनता देश की पूरी अर्थव्यवस्था की और स्वयं की तबाही बेरोजगारी भूल जाएगी और उनके पापों को क्षमा कर देगी यह संभव नहीं।

बेशक इसने भारत के मुद्रित और दृश्य प्रसार माध्यमों को धन बल से खरीद और डरा धमका कर केवल मोदी की प्रशंसा के राग अलापने पाकिस्तान का भय फैलाने और जनता को भ्रमित करते रहने के लिए बाध्य कर दिया। इस चक्कर में आज तक तेज व अन्य अनेकों चैनल्स ने समाचार दिखाना छोड़कर अब गीत संगीत और नाच गानों भोंडे उल्टे सीधे अश्लीलता फैलाकर भारतीय संस्कृति को नष्ट करने वाले धार्मिक देश-विदेश जानवरों के कार्यक्रम दिखाना शुरू कर दिए। ताकि इन धूर्त भेड़िया झुंड पार्टी के जाल साज डकैत मोदी और अमित शाह की सच्चाई सामने ना आ सके।

लोक निर्माण भ्रष्टाचारमंत्री इंजीनियर चारों तरफ से वसूली में मस्त

प्रदेश की सड़कें पुल पुलिया ध्वस्त मंत्री अधिकारी वसूली में व्यस्त

मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग मेंजबसे कांग्रेस की सरकार आई है। मुख्यमंत्री कमल नाथ से लेकर सभी मंत्री चारों तरफ से दोनों हाथ से वसूली करने के सभी दांव पेंच अपना कर चाहे वह स्थानांतरण हो। पदस्थापना हो या वरिष्ठ पद पर मोटी भेंट पूजा चढ़ाकर मासिक रॉयल्टी पर पद ग्रहण करना हो। सभी से यह मंत्री प्रधान सचिव प्रमुख अभियंता अधिकारी येन केन प्रकारेण वसूली में मस्त है। प्रदेश की सड़कें भवन पुल पुलिया भारी बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। जिनका धन के अभाव में तरीके से संधारण भी नहीं हो पा रहा और जनता भारी परेशान हो रही है। वैसे भी मंत्री सज्जन वर्मा ने जो 15 साल से सत्ता हीन हो भूखे बैठे थे। 1 सूत्री कार्यक्रम केवल बसूली का चला रखा है। क्योंकि जो धन भारी करारोपण पेट्रोल डीजल गैस शराब पर लादकर किया जा रहा है। वह पैसा तो सारा मुख्यमंत्री कमलनाथ केवल अपने पिछले 40 साल के चुनाव क्षेत्र जहां उनकी अनेकों फैक्ट्रियां और उसके मजदूर अधिकारीगण रहते हैं। उनके विकास में लगा रहा है। बेशक उनकी यह बदतमीजी अति शीघ्र उन पर पर भारी पड़ने वाली है। उनका सारा ध्यान केवल छिंदवाड़ा के विकास पर लगा हुआ है। बदले में दूसरे मंत्री धन अभाव के कारण अपने आवंटित विभागों के चुन-चुन कर भ्रष्ट इंजीनियरों अधिकारियों कर्मचारियों की पदस्थापना स्थानांतरण अगले वरिष्ठ पद पर स्थापित कर करोड़ों में राशि वसूल रहे हैं। क्योंकि उनके पास वसूली का इसके अतिरिक्त कोई चारा ही नहीं बचा हुआ है। दूसरी तरफ जो वरिष्ठ इंजीनियर उन पदों पर थे, पद से उन्हें मात्र वसूली के लिए हटाकर वरिष्ठ कार्यालयों में संलग्नक अधिकारी बना कर बैठा दिया गया है क्योंकि वह मंत्री की मांग पूरा करने में सक्षम नहीं है। ऐसे अनेकों इंजीनियर जो वरिष्ठ और कार्य कुशल सक्षम अनुभवी हैं उन्हें कार्यालयों में इसीलिए अटैच कर दिया गया है। और यही कारण है कि प्रमुख अभियंता कार्यालय से लेकर नीचे उप संभागीय कार्यालयों में पूरे मध्यप्रदेश के राजधानी भोपाल से लेकर 52 जिलों में चारों तरफ यही हाल है। धना भाव के कारण ठेकेदारों ने काम बंद कर दिए हैं नए काम केवल छिंदवाड़ा में संपन्न किए जा रहे हैं क्योंकि कमलनाथ को भी भय है कि वह कल मुख्यमंत्री रहे ना रहे कम से कम उनका क्षेत्र विकसित हो जाएगा तो अगले 50 सालों तक उनके बेटे के और उनकी खुद की निजी कंपनियों के कर्मचारियों की सुविधा के साथ उनके 40 साल पुरानी लोकसभा क्षेत्र में वहां की जनता के लिए काम आएगा। भारी बरसात से ना केवल लोक निर्माण विभाग की वरन ग्रामीण सड़क विकास मध्य प्रदेश रोड डकैत कारपोरेशन की बीओटी की सड़केंभी ठेकेदारों द्वारा क्योंकि सबको महीना बांटता है। इसलिए कामचलाऊ थिगड़े लगाकर और पैच वर्क करके छोड़ दी गई है परंतु वसूली दोनों हाथ से जारी है इसके साथ ही जो अन्य सड़कें हैं उन पर भी धना भाव का बहाना बनाकर सुधार कार्य नहीं किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अधिकांश कार्यपालन यंत्री जो प्रभाव में बैठा ले गए हैं। उन्हें छोटे-मोटे कामों में जो आवंटन प्राप्त हो रहा है उसका मात्र 20 से 30% तक का ही काम हो रहा है। क्योंकि उन्होंने प्रभारी कार्यपालन यंत्री बनने के लिए मोटी रकम का भुगतान मंत्री को करने के साथ उन्हें मासिक रॉयल्टी मंत्री के साथ प्रधान सचिव और प्रमुख अभियंता को भी चुकाना पड़ रही है बेशक इसकी आड़ में जो घोर भ्रष्ट थे जिसमें प्रभारी कार्यपालन यंत्री दीपेश गुप्ता जो पहले देवास में था भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच के चलते हैं देवास से हटाकर खंडवा के वृत कार्यालय में पदस्थ कर दिया गया था परंतु मोटी रिश्वत के चलते पांच छे महीने में ही उसको वहां से हटाकर रतलाम संभाग में पदस्थ कर दिया गया। ऐसे ही प्रभारी कार्यपालन यंत्री धर्मेंद्र जायसवाल जोपूर्वमें बड़वाह में एसडीओ रहते हुए झाबुआ संभाग में कार्यपालन यंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार के आने को शिकायतें लंबित थी उससे मोटी रुपए 35 लाख कि जैसा कि विभागीय सूचना से प्राप्त हुआ रकम लेकर इंदौर संभाग 1 का कार्यपालन यंत्री का प्रभार सौंप दिया गया था, परंतु भारी भ्रष्टाचार के चलते उसे लोकायुक्त ने रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ लिया। उसको तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए था परंतु मोटे धन के चलते उसके निलंबन के विपरीत उसे सागर मुख्य अभियंता कार्यालय में संलग्न कर दिया गया। इसी प्रकाश इंदौर से भाग 2 में प्रभारी कार्यपालन यंत्री बंसल जो भारी भ्रष्ट होने के साथ भारी जालसाज भी है। उसे भी इंदौर में मोटा धान लेकर पदस्थ कर दिया गया। यह हाल पूरे मध्यप्रदेश में भवन एवं पथ के सभी संभागों का होने के साथ ही अनेकों सेतु संभागों में पुल पुलिया ध्वस्त हो जाने के बाद में भी अधीक्षण यंत्री और मुख्य अभियंता भी जो कि कार्य क्षम ना होने के कारण उनके समय में बनाई गई पुलिस और पुलों का डिजाइन ही भारी त्रुटि पूर्ण होने के कारण मोटे धन के चलते इस तरह तरीके से बनाने कारण पिछले बरसाती मौसम में ध्वस्त हो गई थी। और सारा यातायात भी अनेकों मुख्य मार्गों का ध्वस्त रहा इसके बावजूद सेतु संभाग में भी बैठे अनेकों प्रभारी इंजीनियरों से लेकर मुख्य अभियंता तक को निलंबित तक भी नहीं किया गया और सारे मामले की लीपापोती कर दी गई।

नघाविप्रा की साइट पर 15 वर्ष बाद भी धारा 4 की पूरी जानकारी नहीं

10 हजार करोड की उद्वहन सिंचाई परियोजनाओं में हो रहा काम चलाऊ निर्माण

चुन-चुन कर भ्रष्ट पदस्थ किये जाते हैं। पूरे विकास प्राधिकरण में 20-20 साल से जमे एडीएम, एसडीएम स्तर के अधिकारी आयुक्त पुनर्वास में जो दलाली और सैकड़ों करोड़ के भू अधिग्रहण घोटाले में है लिप्त।

नर्मदा पर वर्तमान में लगभग 15 से ज्यादा उद्वहन सिंचाई परियोजना चल रही है। इन सभी परियोजनाओं में जो अनुमानित सिंचाई क्षमताएं बताई नियोजित कर डीपीआर में दिखाई गई हैं। स्वाभाविक सी बात है उसका 25% से कम ही सिंचाई होगी। जैसा कि मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग और नर्मदा घाटी विकास विभाग का 40 वर्ष पुराना इतिहास रहा है। दूसरी जितनी भी सिंचाई उद्वहन परियोजनाएं शुरू की गई है। सन 70,80,90, में बनी सारी सिंचाई की उद्वाहन परियोजनाएं बिजली के भारी खर्च और उचित संधारण ना होने के कारण जिनमें शासन का करोडों रु लगा, बंद पड़ी हुई है। उसमें सिंचाई के आंकड़े सदा से ही 30 से 40ज्ञ अधिक दिखाये जाते हैं। वास्तविकता में जब सिंचाई होती है तो पहले साल 60%, 70% दूसरे साल 60% और 5-7 साल तक पहुंचते-पहुंचते 20-25% पर आ जाती है। दूसरी तरफ जैसा कि 32 नंबर संभाग में निर्माण की गई उज्जैनी परियोजनाओं में 2 मीटर के पाइप की खरीदी और बिल का भुगतान किए जाने के बाद जब समय माया के श्री अजमेरा ने साइट पर पाइप की परिधि नापी तो 550 पाइप वह 1.8 मीटर ही निकले।यही कारण था कि जब सूचना के अधिकार में उज्जैन से उज्जैनी तक डालने वाली पाइप लाइन के बिलों की कॉपियां मांगी गई। तो साफ मना कर दिया गया। यही हाल प्रथम चरण की 32 नंबर संभाग में बनने वाली नर्मदा कालीसिंध परियोजना में भी हो रहा है। इसके साथ ही सभी उदवहन परियोजनाओं में जो बिजली का खर्च आएगा उदवहन परियोजनाओं के निर्माण के बाद उसके भुगतान की सबसे बड़ी समस्या आती है।ठीक है, सन् 2024 के पहले आपको नर्मदा के पानी का अधिकतम सदुपयोग कर अधिकतम पानी प्रदेश के सिंचाई व अन्य कार्यों में उपयोग में लाना है। इसका मतलब यह तो नहीं की रूंघन का तेल लेने खोपड़ी में नही लगा पाए।तो जूते में डाल दें। मध्यम और बड़ी बांध परियोजनाओं के माध्यम से पिछले 30-40 सालों से लगातार नर्मदा घाटी में यही हो रहा है।इंद्रा सागर नहर की अभी तक21 नंबर संभाग में चलने वाले करोड़ों रुपए के काम बरसों के बाद में भी पूरा नहीं किया जा सका और अधिकतम ठेकों में समय विस्तार और लागत वृद्धि के नाम पर 3 से 5 गुना भुगतान कर दिया गया। यह भ्रष्टाचार की बहुत छोटी साधारण घटना है यही हाल पूरे मध्यप्रदेश में जबलपुर की रानी अवंती बाई सागर बांध और उससे निकलने वाली नहरों का भी हुआ। जहां पर अनेकों ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान कर दिया गया। परंतु नहरों का कार्य पूर्ण नहीं हुआ।करोड़ों रुपए के अग्रिम सतना संभाग में नहर की गुफा के लिए बांटे गए।परंतु वह नहर की गुफा नहीं बनी और वह ठेकेदार आराम से नहर का दिया हुआ 15ज्ञ का अग्रिम लेकर फरार हो गया। उसके ऊपर अधीक्षण यंत्री सतना ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। ऐसे 20 से ज्यादा ठेकेदार जिसमें सोमदत्त, करण सिंह, बीकेबिहानी, मधुकान, जिन्होंने काम कम किया और वहां बैठे घोर भ्रष्ट बाबूओं से लेकर सहायक, कार्यपालन, अधीक्षण यंत्रीयों, मुख्य अभियंता से लेकर सदस्य अभियांत्रिकी ने मोटा धन कमाकर सारे मामलों को ठंडा कर दिया। यहां पर सदस्य अभियांत्रिकी के रूप में वही भ्रष्ट

इंजीनियर को बैठाया जाता है।जिसका इतिहास घोर जालसाजी भ्रष्टाचार और लूट के मंत्री मुख्यमंत्री, आयुक्त, प्रधान सचिव को मुक्त हस्त से लुटाने से भरा होता है। वर्तमान में भी नर्मदा घाटी में बैठा सदस्य अभियांत्रिकी राजीव सुक्लीकरजो मप्र जल संसाधन विभाग में रहकर अपने सहायक से कार्यपालन, अधीक्षण यंत्री और मुख्य अभियंता के साथ प्रमुख अभियंता बनने के इतिहास में लूटो और लुटाओ के दम तक पहुंच गए थे। परंतु वहां पर भ्रष्टाचार, जालसाजी के अनेकों प्रकरण जब जांच का हिस्सा बनने लगे और उनकी संभावना आपराधिक प्रकरणों में दर्ज होने लगी! तो चुपचाप वहां से खिसक कर नर्मदा भ्रष्टाचार घाटी विकास में भ्रष्ट मुख्यमंत्री जल संसाधन मंत्री की कृपा से बैठा दिया गए। ताकि जल संसाधन विभाग के सारे भ्रष्टाचार में शुरू हुई जांचों की फाइलों में दबाया जा सके। स्वाभाविक था नर्मदा घाटी जो अपनी जालसाजियों और भ्रष्टाचार के लिए पिछले 40 सालों से राष्ट्रीय स्तर पर कुख्यात रहा है। वहां पर तो छप्पर फाड़ कर पूरा मौका लूटने और लुटाने का दिया गया। यही कारण है की सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर भोपाल के मुख्यालय से लेकर नीचे संभागीय कार्यालयों तक कोई भी जानकारी नहीं देता। इसके साथ ही धारा 4 सूचना के अधिकार की इसमें भी इन हरामखोर जालसाजों ने 15 वर्ष के बाद भी पूरी जानकारी अपनी साइट पर इसीलिए लोड नहीं की ताकि इनके कुकर्मों के बारे में आम आदमी को कुछ भी मालूम ना पढ़ सके। दूसरी ओर इंदिरा सागर की सभी मुख्य नहर से उप नहरों मुख्य वितरणियों से उप और लघु वितरणियों तक जल सिंचाई के लिए मुख्य नहर से 5-5 की मीटर दूर तक खेत तक पहुंच जाना चाहिए था। परंतु 20 वर्ष ज्यादा हो जाने के बाद में भी अभी तक मुख्य नहर से उप नहरो, उप और लघु वितरणियों तक सिंचाई के लिए जल खेतों तक नहीं पहुंच सका। इन सब के बाद भी हर वर्ष सूक्ष्म जल सिंचाई परियोजनाओं में भी हजारों करोड़ स्वीकृत किये जा रहे हैं। उसके पीछे सबसे मूल कारण भ्रष्टाचार ही हैं। जबकि काम कुछ भी नहीं हो रहा। यहां पर भी प्रमुख अभिनेता रूपी सदस्य अभियांत्रिकी को मोटा धन लेकर बैठाने से लेकर जिन ऊपरी नर्मदा परियोजनाओं, निचली नर्मदा परियोजनाओं और इंदिरा सागर नहर परियोजनाओं के संभागो में जहां ज्यादा काम होता है। बाकायदा सहायक यंत्री कार्यपालन यंत्री अधीक्षण यंत्री यहां तक कि मुख्य अभियंता को भी बोली लगाकर मोटा धन लेकर ही पदस्थ किया जाता है स्वाभाविक है जो धन लेकर बैठाया जाएगा वह भ्रष्टाचार से धन कम आएगा भी यही कारण है। कि मुख्यालय में बैठे हैं मुख्य अभियंता नर्मदा परियोजना निर्माण कार्य विद्युत व यांत्रिकीय, विद्युत उत्पादन, वन एवं पर्यावरण, कृषि, पुनर्वास आदि में चुन-चुन कर घोर भ्रष्ट और जाल साजों को बैठाया जाता है। इसलिये कोई भी हरामखोर जालसाज सूचना के अधिकार में कोई जानकारी देने के साथ उनके अंतर्गत संभागीय कार्यालयों को धारा 6(3) में पत्र आंतरित भी नहीं करता है।क्योंकि धन वितरण और आहरण का काम उनको धन वितरण करने वाले संभागीय कार्यालयों के पास ही होता है। दूसरी ओर भोपाल में स्थित 23 नंबर संभाग जिसका अधीक्षण यंत्री 8 नंबर सनावद में बैठता है।मुख्यालय में बैठकर लगभग एक अरब रुपए साल का भ्रष्टाचार करता है।मुख्यालय में संलग्न 100 से ज्यादा गाड़ियों के रखरखाव पेट्रोल, डीजल व तेल के नाम से लेकर, दिल्ली स्थित नर्मदा भवन के विश्राम गृह में जहां मध्य प्रदेश से पहुंचने वाले मंत्री संत्री और अभियंता आते जाते और उपयोग करते हैं। उनके भोजन के बिलों से लेकर धुलाई के,प्रोटोकॉल के, खर्चेके बिलों में ही हर महीने 50लाखसे एक करोड़ पर महीने तक का आसानी से भ्रष्टाचार किया जाता है।यहां तक की वहां बैठा उपयंत्री, सहायक यंत्री भोपाल भी वायु मार्ग से आते जाते हैं।इसलिए सब भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण कोई जानकारी कैसे दे दी जाए। जनता से लूटा धन फर्जी बिलों के माध्यम से कैसे लूटा और लुटाया जाए।इसकी नीतियां 24 घंटे 12 महीने चलती रहती हैं। अब ऐसी जानकारी आम जनता के हाथ कैसे सौंपी जा सकती हैं।इस नर्मदा घाटी विकास विभाग में कृषि वन एवं पर्यावरण के कुछ कार्यालय तो वर्षों तक कागजों पर चलकर सारा पैसा भ्रष्टाचार में हजम किया जाता रहा। जिसमें उपसंचालक से लेकर करीबन 15-20 का स्टाफ भी था जब इसकी जांच महालेखाकार ने की और कार्यालयों के पते को नहीं देखा तो उसने इस बात की सूचना अपने मुख्यालय को दी! तब 1998 में कृषि विभाग के उपसंचालक कार्यालय और भूमि संरक्षण अधिकारी के कार्यालय उच्च व निचली नर्मदा परियोजनाओं के जबलपुर व इंदौर संभाग में उपसंचालक कृषि के भूमि संरक्षण अधिकारी के कार्यालय जबलपुर, सतना, कटनी, कुक्षी धार खंडवा आदि में खोले गए अन्यथा तब तक सारा पैसा का क्यों पर जो उस वक्त भी करोड़ों रुपए में था हजम किया जाता रहा। इस कारण से नर्मदा घाटी भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण की संज्ञा देनी पड़ती है।

आने वाली पीढ़ी के लिए बचना नहीं चाहिए नदी तालाब पहाड़ और जंगल

खनन से खनका रहे माफिया के साथ मुख्यमंत्री मंत्री और अधिकारी

पूरे प्रदेश में चारों तरफ अवैध खनन कोमाफियाओं के साथ प्रश्रय दे रहे। जिलाधीश एवं सहायक के साथ जिला खनन अधिकारी अकेले इंदौर में ही चारों तरफ इंदौर के बाहर की पहाड़ियों को खोदकर बड़े नेता जिसमें शुक्ला बंधु सबसे आगे हैं रेवती रेंज की पहाड़ियों को खोदकर अधिकांश को साफ कर दिया गया.यही हाल जवाहर टेकरी से लेकर धार रोड पर, नेमावर रोड पर,ट्रेंचिंग ग्राउंड के पीछे की पहाड़ियों पर खुदाई करके कई स्थानों पर पूरी पहाड़ियां गायब कर दी गई। कई स्थानों पर नेमावर रोड पर सौ 100 फुट ऊंची पहाड़ियों को काटकर आधा कर दिया गया। इंदौर के खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना जो बरसों से यहां जमे हुए हैं बार-बार जांच की बातें कही गई। पर पिछले चार-पांच सालों में कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि उन्हें आने वाले सभी जिलाधीश हो और उप जिलाधीश का भी उन माफियाओं के साथ मिलकर अवैध खनन में भारी मोटी कमाई का हिस्सा रहता है। इसलिए पूर्ण संरक्षण मिला रहता है। वहां पर बैठे बाबू बा कर्मचारी भी क्यों के इशारे पर न केवल नाचते हैं वरन सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर वे हर बार टरका देते हैं और अपील लगाने पर वहां बैठे उनके संरक्षणता हरामखोर जिलाधीश भी उन अपीलों को आसानी से खारीज कर देते हैं बार-बार कहा जाता है सारी जानकारियां साइट पर अपलोड है। परंतु सच तो यह है कि निरीक्षक से लेकर जिला खनन अधिकारी से जिलाधीश तक सभी बड़े खनन माफियाओं जिसमें दोनों ही पार्टियों के नेता शामिल रहते हैं पूरी तरह सही पूर्ण संरक्षण के साथ जल जंगल जमीन नदी तालाब पहाड़ उजाड़ अपनी मोटी कमाई में लगे हुए हैं यह हाल पूरे मध्यप्रदेश का है पूर्व के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहानउनके भाई भतीजे वाह रिश्तेदार के 700ज्यादा डंफरों से लगातार 15 वर्ष तकहोशंगाबाद के आसपास नर्मदा से अवैध बालू खनन करने और की राजधानी भोपाल में बैचकर भारी मोटी कमाई करते रहे जिसे होशंगाबाद कलेक्टर से लेकर भोपाल कलेक्टर रायसेन कलेक्टर विदिशा कलेक्टर तक का पूर्ण संरक्षण उस अवैध कार्य में मिला हुआ था क्योंकिक्योंकि वह मुख्यमंत्री और उनके रिश्तेदारों के थे दूसरी तरफरीवा का बड़ा भूमाफिया और खनन माफिया राजेंद्र शुक्ला को चिकन का खनिज मंत्री का प्रभार दे रखा था जब डकैत को ही कोठार दे दिया जाए। सुहाग दिखाएं कि वह और उसका ग्रुप पूरे प्रदेश में ना केवल गोरखनिजो वरन मूल्यवान खनिजों में माइका, जिप्सम से लेकर मासूम खनिजों और रत्नों जो छतरपुर पन्ना आदि में पाए जाते हैं की भी भारी भारी अवैध खनन से मोटी कमाई नेता मंत्री अधिकारी आंख मीच कर करने में लगे हुए है फिर कमलनाथ ने आते ही खनन माफिया पर शिकंजा कसने के लिए कोई अच्छे काम की है तो कुछ अपने ही पार्टी के खनन माफियाओं को कमाई के लिए व्यवस्था भी की जैसे कि नदियों बांधोंसेरेट निकालने के लिए ठेके दिए जाएंगे उनमें उनके ही खास आदमियों को मोटे थे के मिलेंगे जो और रिति पर अपना एकाधिकार जमा कर अपने मनमाने भाव पर पूरे प्रदेश के सरकारी ठेकेदारों से लेकर आम जनता को बैठेंगे बेचेंगे खनन से धन खनकानासत्ता में बैठे शासकीय अधिकारी कर्मचारियों से लेकर सत्ताधीशहर नेता मंत्रीसे लेकर गांव की सरपंच पंचू तक का पहला परम पावन कर्तव्य होता है आखिर सत्ता में बैठे का मतलब क्या है बड़े बड़े गुंडे माफिया भू माफिया खनन माफिया आखिर राजनीति में घुसते ही क्यों हैं ताकि उनके ऐसे सारे अवैध खनन को चाहे वो गौण खनिज हो या महत्वपूर्ण बहुमूल्य खनिज हो लूटने के लिए लूटने और सत्ता में बैठे अधिकारियों कर्मचारियों को टुकड़े डालकर खरीद कर आसानी से अपने कार्य को संपन्न किया जाता है जहां जिलाधीश उप जिलाधीश सहायक जिलाधीश से लेकर खनन का जिलाधिकारी और वहां बैठे बाबू चपरासी तक सब माफियाओं केटुकड़ खोर हों।अकेले इंदौर में ही बैठे खनन माफियाओं को पालने वाले खनन सरगना के खनिज के जिलाधिकारी खन्ना के ऊपर जिलाधीश से लेकर मंत्री तक उसे बचाने में क्यों लगे हुए हैं क्योंकि सबको उससे मोटा टुकड़ा मिलता है और दूध देती गाय को चाहे वो कितनी भी लात मारे कोई हटाना भगाना तो नहीं चाहेगा फिर हमारे प्रदेश में तो तांबा अभ्रक मैग्नीज से लेकर बहुमूल्य खनिजों में छतरपुर और पन्ना की खदानों में हीरे तक पाए जाते हैं स्वाभाविक है 15 वर्ष सत्ता से दूर बैठी कांग्रेस डगमग आती सत्ता में भरपूर लूट कर धन संग्रहण करना चाहती है इसलिए मैं माफिया को भी सरंक्षण देती है और उन्हें पालने वाले अधिकारियों को भी।

साप्ताहिक समय माया

मध्य प्रदेश वाणिज्य कर में माल एवं सेवा कर से वसूली में चारों तरफ गिरावट

मुख्यालय से नीचे वृत्तों में अधिकारियों की नहीं बदली भ्रष्ट मानसिकता

सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला प्रदेश के विभाग के पास खुद का भवन जमीन होने के बाद भी नहीं। जब कराधिकारी सहायक आयुक्त उपायुक्त कर संग्रहण के लिए क्षेत्र में नहीं घूमते तो अनावश्यक वाहनों पर खर्च क्यों? भत्ता दें और खर्च बचाएं।सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर मुख्यालय से व्रतों तक बहानेबाजी, और उड़ाया जाता मजाक।

मध्यप्रदेश में प्रदेश की सरकार की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में मध्यप्रदेश के वाणिज्य कर विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। बेशक जीएसटी लगने से विभाग के कर्मचारी अधिकारियों के पास काम का अप्रत्यक्ष भार बढ़ा। परंतु प्रत्यक्ष भूमिका घटी क्योंकि अधिकांश कर संग्रह ऑनलाइन जमा होने के कारण प्रत्यक्ष भूमिका और कार्य घटा हुआ है। स्वाभाविक है जब वाणिज्य कर अधिकारी, सहायक आयुक्त और उपायुक्त प्रत्यक्ष तौर पर किसी भी व्यापारी उत्पादक आदि से कर वसूली के लिए क्षेत्र में नहीं जाते हैं तो उन्हें वाहन सुविधा देना अब निरर्थक हो चुका है। दूसरी तरफ जब सरकार अधिकारियों को और कर्मचारियों को वाहन बता देता ही है तो अनावश्यक वाहनों पर किए जाने वाला खर्च बचाया जाना चाहिए अब वाहन केवल संयुक्त आयुक्त अपर आयुक्त और आयुक्त महोदय को ही दिया जाना चाहिए दूसरी तरफ प्रदेश में कार्य कर रही एंटीविजन यूनिट वाहन किराए पर लेता ही है जिसे यथार्थ में वाहनों की आवश्यकता होती भी है। फील्ड में दूर तक जाने के लिए और कर चोरी रोकने के लिए ट्रकों को पकड़ना दिन रात मार्गों पर वसूली के लिए पेट्रोलिंग करना आवश्यक है। वहां वाहन की सुविधा दिया जाना उचित है परंतु वाणिज्य कर अधिकारी से सहायक आयुक्त उपायुक्तों को वाहन पर अनावश्यक खर्च करना अब उचित प्रतीत नहीं होता। जिसे तत्काल बंद किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश वाणिज्य कर विभाग पिछले लगभग 20 सालों से चेतक चेंबर में प्रतिवर्ष 4 से 5 करोड़ रुपए किराया जमा करता है, जबकि अफीम गोदाम की जमीन जो लगभग 5 एकड़ है जानबूझकर खुल जा कर रखा हुआ है शासन जिलाधीश और आयुक्त जमाने की जमीन खाली करवा कर उस पर कब्जा कर देते लेते हैं और सार्वजनिक निर्माण करवा देते हैं। अफीम गोदाम की जमीन को उसके सारे कागजात पूरे कर तरीके से उस पर आधे हिस्से में 5-6 मंजिला भवन बनाकर पूरा मुख्यालय के साथ सभी व्रत कार्यालयों को उसमें लगाया जा सकता। है क्योंकि चेतक चेंबर में मोटा कमीशन संयुक्त आयुक्त संभाग 3 से लेकर आयुक्त और मंत्री तक पहुंच रहा है इसलिए अफीम गोदाम की जमीन के सारे दस्तावेजों की कागजी कार्रवाई को पूरा कर वहां पर भवन निर्माण की कोई योजना नहीं है जबकि पिछले 40 सालों से वह जमीन पूर्ण रूप से वाणिज्य कर विभाग के अधीन और कब्जे में है उस जमीन पर आजू बाजू अनेकों भवन मालिकों ने अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है और सामने भी उसकी बाउंड्रीवॉल ना होने के कारण दुकानों का कब्जा जमा हुआ है जिसे तत्काल कांगरे सरकार को सारे अतिक्रमण हटाकर कब्जे में लेकर पहले बाउंड्रीवॉल बनाई जाए और वहां विभाग को अपना शीघ्र 5-6 मंजिला भवन बना लेना चाहिए कर्मचारी संगठन पिछले 15 सालों से लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं पर मोटे कमीशन के चलते उनकी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा। बेशक पूरे मुख्यालय वाणिज्य कर को शहर से बाहर स्थानांतरित कर वहां जमीन लेकर भवन बनाने की योजना कई बार कागजों पर बनी और खत्म हुई परंतु कर्मचारी संगठनों का शहर से बाहर जाने आने में भारी परेशानी होने के कारण उन्होंने उसका विरोध किया। वर्ष के बाद कांग्रेस को सत्ता हाथ में आने के कारण इस विभाग में भी के मंत्री ने भी वही वसूली के लिए ऊटी छठ पूजा की उसे उनके मन चाहे एंटीवर्जन ब्यूरो में बैठा दिया गया, क्योंकि अब वाणिज्य कर में कमाई केबल ईवीजन ब्यूरो में रह गई है। वहां कर सहायकों से लेकर निरीक्षक सहायक करा अधिकारी सहायक आयुक्त उपायुक्त और संयुक्त आयुक्तों की पदस्थापना मोट धन वसूली के बाद ही की गई।

वाणिज्य कर में मुख्यालय में बैठे सूचना अधिकारी से लेकर नीचे व्रतों में भी बैठे घोर धूर्त और मक्कार अधिकारी जानकारी देने की अपेक्षा एक तरफ हर जानकारी को मैडम/सर को बता देते हैं। तो दूसरी तरफ मुख्यालय ने अपनी साइट पर उपायुक्त का अपीलीय अधिकारी अपर आयुक्त नियुक्त कर रखा है, परंतु वास्तविकता में मुख्यालय ने धारा 19 का उल्लंघन करते हुए जिसमें सब डिविजनल ऑफीसर कोर्स का एपीआईओ और संभागीय अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया हुआ है उसका वरिष्ठ अधिकारी ही उसकी अपील सुन सकता है। जो पूर्व में उपायुक्त था। जीएसटी में उसे संयुक्त आयुक्त का नाम दे दिया गया है। उसका अपनी अधिकारी अपर आयुक्त ही होना चाहिए। कौन धूर्तों ने अपने कुकर्मों को बचाने अपने सहायक आयुक्त को अपना लोक सूचना अधिकारी और स्वयं को अपीलीय अधिकारी घोषित करवा लिया है। अब यह हरामखोर और जालसाजों की डरपोक फौज अपने कुकर्मों को छुपाने, अपने कराधिकारियों द्वारा जो जालसाजियां उन्होंने कर निर्धारण में की थी और करते हैं। और बदले में शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा कर अपनी लाखों रुपए की कमाई करते हैं। तरीके से जानकारी देने का जवाब और अपील के निर्णय की अपेक्षा वकील बनकर 10-10, 20-20 पन्नों के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की जानकारियां भेजते हैं। निर्णय के बदले में ऐसे ही एक घूंट भ्रष्ट जो अभी संभाग दो में पदस्थ है। जिन्होंने अपने कराधिकारी रहते हुए करोड़ों रुपए की कमाई की और शासन को अरबों रुपए का चूना लगाया और राजस्व की हानि कीपहुंचा मोटा धन कमाया था। जिसे समय माया सन 2002-03 से लेकर 2008 तक छाप रहा है। इसलिए मोटा धन बांटकर अच्छे-अच्छे पदों पर स्थापना लेते रहे हैं और काफी लंबे समय से इंदौर में ही जमे हुए हैं। धारा 6(3) में आवेदन को अपने वृत्तों में अंतरण की अपेक्षा वहां भी पिछले निर्णयों की दलील देते हैं। इस पदस्थापना के पूर्व में यह उपायुक्त डीपी शर्मा एंटी इवेजन ब्यूरो में थे। वहां पर भी इन्होंने हजारों माल वाहकों वे ऊकर अपवंचन में वाले वाले ही ऊपर धन वसूल कर छोड़ा करते थे। कांग्रेस सरकार के आने के बाद उम्मीद थी कि 5 साल से ज्यादा समय से कुंडली मारे भ्रष्ट अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाएगा, परंतु यह सवा युग से भूखे बैठे कांग्रेसियों ने सबसे मोटी वसूली कर उन्हें वहीं पर अपनी मोटी रॉयल्टी की वसूली के चलते जमे रहने दिया गया। जिसमें लगभग 50 से ज्यादा अधिकारी पूरे मध्यप्रदेश में पांच 5 वर्षों से ज्यादा समय से एक ही स्थान पर बैठे हुए हैं सबसे ज्यादा इंदौर वाणिज्य कर में है जिसमें संभाग 3 केउपायुक्तअब्दुलमजीद को तो यहां 8 साल से ज्यादा हो गया परंतु घोर भ्रष्ट प्रधान सचिव और मंत्री ने मोटी वसूली करने के बाद 20 से ज्यादा सहायक आयुक्त 5 से ज्यादा उपायुक्त काफी लंबे समय से दौर में ही जमे हुए हैं। पूरे मध्यप्रदेश से भी करा अधिकारी सहायक आयुक्त, उपायुक्त, इंदौर आने के लिए वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं इस प्रकार वर्षों से जमे अधिकारियों को हटाकर प्रशासनिक कार्य कुशलता बढ़ाई जानी चाहिए।

आजादी के बाद से अभी तक सामाजिक, आर्थिक सबसे ज्यादा दोहन हुआ

छद्म श्रेष्ठता, धन के अहंकार में बिखरे हुए सवर्णों जागो

70 वर्षों में, खून पसीने की कमाई का सबसे ज्यादा लूटा गये सवर्ण मध्यमवर्गीयों से

भारत में सभी राजनीतिक दलों ने चाहे वह कांग्रेस हो, जनसंघ, भाजपा, बसपा, सपा, या अन्य राजनीतिक दल, सभी ने अपने वोट बैंक के लिए करों के बहाने, लूटा आयकर, विक्रीकर, संपत्ति कर, कस्टम व एक्साइज, स्टैंप ड्यूटी आदि के बाद भी, सभी राजनीतिक दलों की भी चंदा वसूली भी सभी मध्यमवर्गीय सवर्णों से ही की जाती है। बदले में क्या मिलता है? सभी राजनीतिक दलों द्वारा मंचो से घोर गालियां, सरकारी नौकरियों में, उच्चतम अंक लाने पर, मुश्किल से नौकरियां, दुगना काम करने के बाद भी 30-30 साल तक पदोन्नतियां नहीं, बच्चों के विद्यालयों, महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा में, प्रवेश नहीं, छात्रवृत्ति या नहीं, पुस्तके नहीं, सरकारी चिकित्सालयो मुफ्त इलाज नहीं, खेती किसानी और व्यापार में अनुदान, छूट, नहीं जबकि आप से लूटे हुए करों के धन से, करोड़पति आरक्षित वर्ग के लोगों, के बच्चों को विद्यालयों महाविद्यालयों में न्यूनतम अंको पर प्रवेश, 5 साल फेल होने के बाद में भी छात्रवृत्तियां, निशुल्क छात्रावास, साइकिलें, किताबें, लैपटॉप, मोबाइल फोन, सब आपके पैसे से उन सब को मुफ्त में,

आखिर 70 वर्षों से सब कुछ क्यों झेल रहे हो पाखंडी धन के अहंकार में बिखरे हुए सवर्णों, क्योंकि तुम्हारी आदत दूसरे की धोती पकड़कर चलने की है, क्योंकि तुम एकत्रित नहीं हो सकते मेंडको, कब सुधरोगे कब समझोगे कब संभालोगे अपने आप को, परं? वार को, समाज को या तुमने लाते जूते खाए तुम्हारे बच्चों को भी यही खाना चाहिए क्योंकि उनके मां बाप, निहायत कमजोर डब्बू, छद्म श्रेष्ठता के अहंकार में जीने वालों की डरपोक फौज थी।

हिंदुओं तुम्हारा सबसे बड़ा अभिशाप, श्रेष्ठता का और एकात्मकता का अहंकार है।इसलिए बिखरे हुए हो। इकट्ठे हो जाओ और फिर एकता का शंखनाद करो। जिन आदिवासियों और अनुसूचित जाति का पाखंड इस सरकार ने अपनी वोट बैंक के लिए फैला रखा है उस भ्रम को दूर कर इन सब को साथ में लो। यह हमारे अपने ही सहस्त्रों वर्षों से, हमारी जीवन और समाज का अंग होने के साथ हमारे ही समाज बंधु है। इन्हें साथ में लेकर आगे बढ़ो। वैसे भी हमारे शास्त्रों में जाति का निर्धारण जन्म से नहीं उसके कर्मों से हुआ है।

जिसे अंग्रेजों और मुगलों ने जानबूझकर हमसे अलग करने के लिए शूद्रता की क्षुद्रता का पाखंड फैला कर हिंदुओं को हिंदुओं का दुश्मन बना दिया था जिसे पहले कांग्रेस ने और अब भाजपा ने आकर अपने वोट बैंक की खातिर और मजबूत करने कि साजिश कर रही है। दूसरा पुरुष होने के बाद में भी प्राकृतिक आक्रमकता नहीं है। बस यह 2 गुण तुम्हारी जीत का ही नहीं पूरी हिन्दुओं की जीत का परिचायक होंगे।

फिर तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों ने सहस्त्रों वर्षों की ज्ञान विज्ञान भाषा कि जो शास्त्रों में ऋग्वेद से लेकर वर्तमान तक जो संपत्ति सौंपी है। उसका भरपूर सदुपयोग कर एकत्रित होकर अपनी श्रेष्ठता का परिचय देकर विश्व में अपना परचम लहराओ।

आत्मविश्वास जागृत करो।

अपने पूर्वजों को दिया हुआ ज्ञान का सदुपयोग करो एकत्रित होकर अपनी श्रेष्ठता को विश्व पर स्थापित करो। जिस का सदुपयोग जिसमें संस्कृत भाषा से लेकर योग, वैमानिकी, अंतरिक्ष, विज्ञान, रसायन, भौतिकी, स्वास्थ्य आज तक का उपयोग विदेशियों ने भरपूर कर अब हम पर ही रोब ऐंठ रहे हैं।

ईसाइयत ने 2019 साल पहले और मुस्लिमों ने 1441 साल पहले ही धरती पर अपना अस्तित्व स्थापित किया हैं।

जबकि आप की परंपराएं, आपका धर्म, आपका ज्ञान सहस्त्रों शताब्दियों पुराना है। फिर भी आप का सरकारी दोहन व पिछड़ापन आप की गलतियों के कारण है।

मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूं। पर आपका भी सतत हर प्रकार से सहयोग चाहिए।

जो भी कुछ मैं लिख रहा हूं। प्रेषित कर रहा हूं आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित सुद्रढ और समृद्ध बनाने के लिए सदा से प्रयास करने में सहयोग कर भविष्य संवारिये।

प्रदेश के कांग्रेसी मंत्री, सत्ता, बाप की जागीर,

अधिकारियों का कठपुतलियों की तरह उपयोग और वसूली

मध्यप्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है। सारे मंत्री अपने विभाग के अधिकारियों को कठपुतली की तरह नचाते हैं। उन्हें अपने ऑफिस में काम ही नहीं करने देते हैं। और बस अपने पीछे घुमाना अपने पीछे कार्यक्रमों में ले जाना, उनके टेंट तंबू लगवाने से लेकर, उनकी और उनके पट्टों की गाड़ियों में डीजल, पेट्रोल भरवाने से लेकर उनके भोजन पानी, सुरा सुंदरी आदि तक की व्यवस्थाओं के लिए ये घोर बदतमीज विधायक मंत्री अधिकारी कर्मचारियों से दवाब देकर करवाते है। अन्यथा चमकाना, धमकाना। यह हर विभाग में ही देखा जा रहा है। इंदौर संभाग में वन मंत्री उमंग सिंगार, ने पूरे वन विभाग को अपनी जागीर मान, इंदौर वन विभाग के विश्रामगृह के सारे कमरों पर कब्जा कर रखा है। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग के रेजीडेंसी स्थित ओल्ड रेस्ट हाउस के भी 6 में से 3 कमरे उमंग सिंगार ने और तीन कमरे तुलसी सिलावट ने जब से मंत्री बने तब से कब्जे में ले रखे हैं उनके खाने-पीने का सारा भोजन व्यवस्था लोकमान विभाग के अधिकारियों को जेब से करनी पड़ रही है यह उनकी बदतमीजी की पराकाष्ठा का छोटा सा नमूना है। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट शुद्ध वसूली का युद्ध मिलावट के नाम पर यहां के महाधूर्त, मक्कार, 10 सालों से ज्यादा समय से बैठे खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष स्वामी, स्वास्थ्य अधिकारी जडिया के साथ मिलकर करोड़ों की वसूली नकली पान मसाला किशोर वाधवानी के साथ की जा रही है। नमूने भरकर छापे मारे जाते हैं। बाद में मनीष स्वामी सेटिंग करके सरकारी प्रयोगशाला में सारे नमूने बदल बदलवाता है जिसमें सुभाष खेड़कर यह भी 10 साल से बैठा है नमूना सहायक सुधाकर जो पिछले 25 सालों से इंदौर में बैठकर करोड़ों कमा चुका है और बड़ा वसूली का दलाल है। इसके लिए मनीष स्वामी दहशत फैलाने वसूली करने के लिए और बाबू को भी लाख रुपए महीना पत्रकारों को भी बांटता है। लोक निर्माण हो, जल संसाधन हो, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी हो, महिला बाल विकास, परिवहन, स्वास्थ्य आबकारी शिक्षा, आदि सभी विभागों में जिस क्षेत्र का अधिकारी है। वह कठपुतली बनकर आगे आगे पीछे श्वानों की तरह घूमाया जाता रहता है। यह प्रवृत्ति मंत्रियों को त्यागनी होगी। यदि उन्होंने यह सब नहीं छोड़ा। तो भविष्य काफी दुखदाई हो सकता है। यदि उनके पास में विभाग का एक अधिकारी विशेष कार्य कर्तव्य अधिकारी इसीलिए पदस्थ किया जाता है। ताकि उनके सारे कामों को विभागीय स्तर पर देखता रहे। पर शायद मंत्रियों का इससे पेट नहीं भरता। क्षेत्रीय विभागीय कर्मचारी अधिकारियों को अपनी कठपुतली बनाकर अपने खर्चों आदि के लिए उसको मोहरा बनाकर नचाते रहते हैं। इससे जनता में बहुत गलत संदेश जा रहा है। और वह विभागीय अधिकारी अपने पद पर रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाता। उससे भी सरकार की बदनामी होती है।

भेड़ियॉ झुंड पार्टी की सरकार के जनधन के लूट के षड्यंत्र की अनोखी प्रणाली

प्रदेश भर के उचित मूल्य की दुकान में 29 करोड की पीओएस मशीन का किराया डेढ अरब

भोपाल। खाद्य व नागरिक आपूर्ति में राशन की काला बाजारी पर आधार कार्ड और अंगूठे के निशान से रोक लगाने का प्रयास किया गया तो वहां बैठे घोर धूर्त और मक्कार अधिकारियों ने लूट के लिए नई अंगूठा लगाने की मशीनें उसकी कीमत से ज्यादा मोटे किराए पर लेने की प्रणाली विकसित कर डाली। जोकि मंत्री, नेता प्रधान सचिव के रिश्तेदारों से किराए पर ली गई थी। भोपाल- पूरे प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे लोगों को बंटने वाले एक रुपए किलो के गेहूं दूर में किलो के चावल जो भारी कालाबाजारी की जा रही थी। उसे उचित मूल्य की दुकानो में काला बाजारी रोकने बनाई गई थी। पीओएस मशीन की योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 -16 से मध्य-प्रदेश में खाद्यान्न की काला बाजारी रोकने के लिए ई-पीओएस मशीन प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान में दुकानदारों को उपलब्ध कराया गया। जहां पीओएस मशीन की कीमत लगभग 12 हजार रूपए होने के बाद भी खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल द्वारा पीओएस मशीन खरीदने की जगह एक निजी कंपनी से किराए पर ले लिया। जहां वर्ष 2015-16 से अब तक विभाग 30 करोड अनुमानित कीमत की पीओएस मशीन के बदले अब तक 4 वर्षो में डेढ अरब की अनुमानित राशि का भुगतान कर दिया है। जिसे कांग्रेस सरकार को तत्काल रोकना चाहिए।

30 करोड की पीओएस मशीन का किराया डेढ़ अरब

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मध्य प्रदेश के 52 जिलो में 24 हजार 931 उचित मूल्य की दुकानो में 1 करोड 17 लाख 38 हजार 445 लाभार्थी परिवार दर्ज है। प्रदेश भर के उचित मूल्य की दुकानो में पीओएस मशीन प्रतिमाह 1 हजार 400 रूपए की दर से किराए में लेकर भुगतान किया जा रहा है। जहां 12 हजार की मशीन की कीमतो के अनुमानित आंकडो के हिसाब से 29 करोड 91 लाख 84 हजार की पीओएस मशीन को विभाग ने क्रय करने की जगह प्रतिमाह 1 हजार 400 रूपए की दर से किराए में ले लिया। जिसके आधार पर विभाग कंपनी को प्रतिमाह लगभग 3 करोड 49 लाख 800 रूपए किराया का भुगतान कर रही है। वहीं बीते 4 वर्षो में अब तक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल द्वारा कंपनी को 1 अरब 67 करोड 54 लाख 30 हजार 400 रूपए के अनुमानित राशि का भुगतान किया जा चुका है।

इन कंपनियों से हुआ 5 वर्षो का अनुबंध

नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल द्वारा वर्ष 2015-16 में विजेनटेक लिंकवेल टेली सिस्टम प्राईवेट कंपनी को चार संभाग एवं डीएसके कंपनी को छः संभाग के उचित मूल्य की दुकानो में पीओएस मशीन किराए से देने एवं मेंटनेंस का कार्य 5 वर्षो तक किए जाने का अनुबंध किया गया, जहां पर डीएसके कंपनी द्वारा कार्य नही किए जाने पर विभाग ने उसे ब्लैक लिस्टेड करते हुए प्रदेश के 52 जिलो में विजेनटेक लिंकवेल टेली सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड को अनुबंध कर दे दिया। जहां आज यह कंपनी मध्यप्रदेश के 24 हजार 931 उचित मूल्य की दुकानो में किराए से पीओएस मशीन चला रही है।

4 जी के जमाने में लगी 2जी सिम

मामले में एक और नई बात सामने आई है, जहां विजेनटेक कंपनी द्वारा किराए से दी गई पीओएस मशीन में लगी सिम 4 जी की जगह 2 जी लगाई गई है, जहां इस सिम का प्रत्येक माह का रिचार्ज एवं पेपर रोल का खर्च सेल्समैनो द्वारा दिया जा रहा है। वहीं 2 जी सिम लगे होने के कारण सर्वर की धीमी गति और सेल्समैन को खाद्यान्न वितरण में लगातार हो रही परेशानी बढ़ती जा रही है। जब इस मुद्दे में अनूपपुर जिले के कई सेल्समैनो से जानकारी ली गई तो उन्होने बताया की सर्वर की धीमी गति के कारण लाभार्थी परिवार को प्रदाय की जाने वाली खाद्यान्न का डेटा मशीन के फिंगर में नही लिए जाने के कारण नही मिल पाता है। एक तरह 4जी के जमाने में कंपनी द्वारा 2 जी सिम उपयोग में ला रही है, वहीं बहुत से सेल्समैनो ने बताया की वे मशीन को वाई-फाई के माध्यम से अपने मोबाइल फोन से लकर खाद्यान्न वितरण कर रहे है।

वैसे ऐसा नहीं है। कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण भाग में ऊपर की कमाई का अकाल पड़ गया हो। या मशीनें लग जाने से स्कूल की दुकानों से मिलने वाले गेहूं चावल की कालाबाजारी नहीं हो रही हो । बेशक अब लूट की थोड़ी सी उच्च तकनीकी हो गई है। खाद्य नागरिक आपूर्ति के निरीक्षकों से लेकर जिला खाद्य अधिकारी संभागीय खाद्य नियंत्रक आदि की कमाई के तरीके बदल चुके हैं पेट्रोल पंपो अब महीना मिलना कम हो गया है बस अब कमाई जो इंधन गैस आपूर्ति कर्ता वितरक हैं। जो गैस के ऊपर मिलने वाला अनुदान जो सीधे उपभोक्ता के खाते में जमा होना चाहिए। 90ञ मामलों में यह गैस वितरक उपभोक्ता के खाते में अंतरित नहीं कर रहे हैं। जिसमें अकेले प्रदेश में हर माह में लगभग 50लाख कनेक्शन में से मुश्किल से 5लाख को भी पिछले कई महीनों व सालों से खाते में नहीं आया है। जो हर महीने लगभग डेढ़ हजार करोड़ रुपए होता है उसमें से ही मोटी बंदरबांट कर जिला खाद्य अधिकारी खाद्य नियंत्रक से मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंच रहा है।

विधानसभा में उठाएगे प्रश्न

पूर्व मंत्री एवं विधायक अनूपपुर बिसाहूलाल सिंह से जब इस संबंध में चर्चा की गई तो उन्होने आश्चर्य व्यक्त करते हुए भाजपा सरकार के कार्यकाल पर अपने लोगो को लाभ पहुंचाने का अनोखा तरीका है। निश्चित ही इससे शासन की राशि का दुरूपयोग हो रहा है। इस पूरे मामले को मेरे द्वारा विधानसभा सत्र में पटल में उठाया जाएगा और जो यह खेल खेला गया है, उसको विधानसभा के माध्यम से प्रदेश की जनता को बताते हुए इस खेल को बंद कराया जाएगा।

पंचायत विभाग मैं प्रधान सचिव और मंत्री से लेकर सरपंच और सचिव सबसे ज्यादा और सबसे बड़े भ्रष्टाचारी

मेरी यह बात और लेखन जो पिछले 20 वर्षों से पंचायतों के बारे में लिख रहा हूं, जिसे मैंने काफी निकट से समझा और देखा है। देपालपुर में पड़े सचिव दुबे के ऊपर लोकायुक्त छापे ने सिद्ध कर दी।यहां पर भी ग्राम पंचायतों से लेकर जनपदों, जिला पंचायतों जहां संविदा कर्मियों में महिलाओं का खुलकर यौन शोषण किया जाता है। खुलकर हनी ट्रैपिंग होती है। तब ही महिलाओं की समयवृध्दि और वेतन मिलता है। यहां पर भी 20 -20, 25- 25 साल तक बैठे रहने वाले बाबू सहायकों लेखाकार व अन्य सभी स्टाफ भारी भ्रष्ट और जाल साज होते हैं हर योजनाओं में धन वितरण अनुदान आदि में खुलकर भ्रष्टाचार का तांडव होता है। इसलिए यहां बैठा हुआ भारती प्रताणना सेवा का अधिकारी किसी को भी सूचना के अधिकार में जानकारी नहीं देता और यह जालसाज अपनी अपील स्वयं सुनने का पात्र होता है। इसलिए वह अपील रद्द कर दी जाती हैं।

मध्यप्रदेश का सामान्य प्रशासन विभाग जो सारे प्रदेश के भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारियों की उंगलियों और इशारों पर उनके टुकड़ों पर पलता है। वहां बैठे गिद्धों की फौज, टुकड़ी खाकर नए-नए परिपत्र जारी करती है जिसमें इन हरामखोर सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जो कि लोक सूचना अधिकारी है धारा 19 सूचना के अधिकार अधिनियम की को ही जिसे संसद में पास किया गया था उसकी धज्जियां बिखेरते हुए इन हराम खोरो, अपने मन से ही अपनी जालसाजीयों व भ्रष्टाचार को छुपाने परिपत्र जारी कर दिए। इन जालसाजों ने परिपत्र जारी कर उसको उसका अपीलीय अधिकारी बना दिया ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री जो कि लोक सूचना अधिकारी है। वहां उपयंत्री सहायक यंत्री को लोक सूचना अधिकारी और कार्यपालन यंत्री को उसका अपीलीय अधिकारी बना दिया। यही हाल इन हरामखोर सामान्य प्रशासन विभाग के लोगों ने उप संचालक कृषि को उसका अपीलीय अधिकारी बना दिया। साथ में उप संचालक उद्यानिकी का, शिक्षा विभाग का अपीलीय अधिकारी भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को बना दिया गया। जबकि कानूनन उसी विभाग का वरिष्ठ अधिकारी लोक सूचना अधिकारी होना चाहिए था जिसमें गले के उद्यान की के उपसंचालक का अपीलीय अधिकारी संयुक्त संचालक होना चाहिए था वही हाल शिक्षा विभाग में उनका वरिष्ठ अधिकारी संभागीय स्तर का संयुक्त संचालक होना चाहिए था उसी प्रकार कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी का वरिष्ठ अधिकारी अधीक्षण यंत्री होना चाहिए था खनिज विभाग का, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, महिला बाल विकास का, कोष एवं लेखा का, परिवहन का भी अपीलीय अधिकारी जिलाधीश को बना दिया गया है। जबकि उनका वरिष्ठ संयुक्त संचालक या क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी होना चाहिए था। जिलाधीशों को जिनमें अपीलीय अधिकारी बनाया गया है।

वह हरामखोर भी अपने आपको जिले का मालिक समझते हुए अपील जैसे छोटे से काम को जिसमें कोई कमाई नहीं होना है। छोटे जिलों में सहायक जिलाधीश को सौंप देते हैं और वह सहायक जिलाधीश आराम से उन अधिकारियों से महीना खाता है। इसलिए वह जालसाअ मक्कार वह सारी अपीलें रद्द कर देता है। इस प्रकार से सामान्य प्रशासन विभाग पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार को पालता पोसता और जालसाजियों को फैलाने में मदद करता है।हाल ही में सामान्य प्रशासन विभाग ने जालसाजी पूर्ण तरीके से धारा 6(3) को भोथरा बना दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने एक परिपत्र क्रमांक/ 667/1056/2016 दिनांक 08:09:19 जारी किया है। यथार्थ में सत्ताधीशों जो अपने आप को खुदा मान लेते हैं। जबकि यह सूकरों की फौज भी कानून से कानून का पालन करने के लिए जन धन से वेतन लेते हैं। पर यह गिद्धों की फौज अपनी लूट खसोंट भ्रष्टाचार और जल साजियों को बरकरार रखने अपने मन से ही कानून की धज्जियां बिखेरते हुए परिपत्र जारी करते रहते हैं और यही कारण है की पंचायत का एक अदना सा सचिव भी इन चुरकटों की सह पर चुरकटों को टुकड़े डालकर करोड़पति हो जाता है। बदले में जनता से नेता अधिकारी करों से, शासकीय सेवाओं की शुल्क वृद्धि से दोनों हाथ से लूटकर अपनी लूट का तांडव करते रहते।

प्लास्टिक को बढ़ावा देने सबसे ज्यादा उपयोग करने वाली विषैली बहुराष्ट्रीय कंपनियों का

हल्ला मचाने का षड्यंत्र, छोटे व्यापारियों को खत्म करने

चारों तरफ नगर प्रदेश देश और दुनिया में पिछले 50 सालों में बढ़ते प्लास्टिक के उपयोग से हुई बर्बादी के बारे में चारों तरफ हाय तोबा मचाई जा रही है।

प्लास्टिक और उसकी मूल पॉलीथिन की थैलियों खाद्य व अन्य वस्तुओं कीपैकेजिंग मेंउपयोग किए जाने से उसके नष्ट ना होने के कारण बढ़ते प्रदूषण और फैलती दुष्प्रभावों के नाम पर बेशक पूरी दुनिया में हल्ला मचा हुआ है, परंतु यह हल्ला केवल छोटे मझोले व्यापारियों को परेशान करने उनसे नगर निगम पालिकाओं प्रदूषण मंडल के कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा ना केवल इंदौर में वर्न प्रदेश व पूरे देश के हर छोटे-बड़े शहरों में वसूली का हथियार बन गया है। अकेले इंदौर में ही प्रतिदिन नगर निगम के कर्मचारी लगभग छोटे व्यापारियों ठेले वालों खोमचे वालों दुकानदारों को परेशान कर लगभग 20 से 25 लाख रुपए दिन की वसूली पिछले 2 साल के से ज्यादा समय से कर रहे हैं। जिसके मूल में बड़े शॉपिंग मॉल की दुकानदारी और व्यवसाय को बढ़ाकर उनसे मासिक वसूली करने के साथ छोटे व्यापारियों को लगभग संख्या में जो 20,000 से ज्यादा है जो अपनी खाद्य वस्तुओं सब्जी, दूध, दही, तेल मसाले, आटा, गेहू, सब छोटे ग्राहकों को पैक करके देते हैं। उनसे यह हरामखोर जालसाजो की फौज प्रतिदिन लगभग 2000 से ज्यादा ठेले वाले खोमचेवालों दुकानदारों से लगभग 20 से 25लाख रुपए की अवैध वसूली लेते हैं ।इस कमाई में उस मोहल्ले के पार्षद से लेकर उस जोन के अधिकारियों कर्मचारियों से लेकर उपायुक्तों आयुक्त महापौर कलेक्टर कमिश्नर का भी हिस्सा रहता है। इसके विपरीत अपने उन पूंजीपति व उनके शॉपिंग मॉल वालों से लेकर बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो अपने खाद्य पदार्थों से लेकर अन्य सामग्री को प्लास्टिक पैकेजिंग में पैक करके बेंच रही है। यहां तक कि सांची और अमूल जो पूरे प्रदेश और देश में दूध की आपूर्ति अपनी प्लास्टिक की थैलियों में कर रही हैं उनसे ना जिला स्तरों से प्रादेशिक और ना ही राष्ट्रीय स्तर पर कोई बोलने रोकने टोकने वाला है।वह वर्षों से सहकारिता में काम करने वाली संस्थाएं से अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं और नाम दे रही हैं सिंगलयूज प्लास्टिक जबकि जानती है कि 90 प्रतिशत प्लास्टिक का पुनर उपयोग नहीं हो पाता यथार्थ में केंद्रीय प्रादेशिक मंत्रालयों से लेकर क्षेत्रीय स्तर की सभी अर्द्ध शासकीय व शासकीय कर्मचारी अधिकारियों को यह बहुराष्ट्रीय कंपनियां मोटा धन देकर षड्यंत्र पूर्वक तरीके से उनके प्रतियोगी छोटे ठेले वालों से लेकर वड़ी किराना दुकानों को खत्म करने का षड्यंत्र का एक अहम हिस्सा तो है ही। दूसरी तरफ यदि इन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों को पर्यावरण की चिंता है, तो सबसे पहले अपना प्लास्टिक में पैक किया जाने वाला सारा सामान बेचना बंद करें। और यह हाय तौबा मचाने वाली वही बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। जिसमें कोकोकोला जिसने अपने पेय पदार्थों को बेचने के लिए 88000 टन प्लास्टिक का उपयोग 2018 में किया और उसका अधिकतम प्लास्टिक भी 30000 टन भी रीसायकल नहीं हुआ।

दूसरी तरफ दुनिया की जानी-मानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिसमें यूनीलीवर बनाम पुरानी हिंदुस्तान लीवर भारत में वॉलमार्ट जिसका दुनिया के लगभग 100 देशों से ज्यादा में फूड पैकेजिंग करके खाद्य सामग्री को प्लास्टिक पैकेट में बेचने का काम जो हमारे ही किसानों उत्पादकों से 10 -20 प्रश की कीमत पर लेकर 100 से 500 प्रश तक की कीमत पर बेचता है। हम सब इस धरती के निवासी जो इन कंपनियों की निगाहों में मात्र खरीददार उपभोक्ता है और जिन का शोषण करना छोटे लोगों को दबाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित करना और स्वयं प्लास्टिक का उपयोग पैकेजिंग ब्रांडेड के नाम पर कर माल को कई गुना कीमत ज्यादा पर बेचना और मोटा लाभ कमाना। बेशक हम सब उपभोक्ता है। हम धरती पर निवास करते हैं। हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम जल, जंगल, जमीन, जानवरों, जलवायु को प्लास्टिक से बचाते हुए कसम खाते हैं कि हम किसी भी प्लास्टिक पैकेज, पॉलीथिन मैं रखें और पैकेज किए हुए जिसमें कोल्ड ड्रिंक कोको कोला, पेप्सी, थम्सअप, चॉकलेट, बिस्कुट व सभी अनाज व अन्य खाद्य सामग्री के साथ शॉपिंग मॉल में रखें सभी प्रकार के मटेरियल का खाद्य सामग्री का कोल्ड ड्रिंक का टीन के डब्बे, व अन्य जिसमें प्लास्टिक कोटिंग आदि होती है। ना खरीदेंगे, ना उपयोग करेंगे, ना उसमें रखी सामग्री को खाएंगे पिएंगे, न छुयेंगे। हम ही हैं जो इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ब्रांडेड के नाम पर जबकि वह पूरी रासायनिक वस्तुओं से, जानवरों की चर्बी, बसा, रक्त, अस्थि चूर्ण आदि का प्रयोग कर अपनी खाद्य सामग्री तैयार करके स्वादिष्ट बनाती हैं। लंबे समय तक वह खराब ना हो उसमें कीटनाशक के प्रयोग से लेकर अन्य घातक रसायनों का मिश्रण करती हैं। जो हमारे हिंदू धर्म की आस्था के बिल्कुल विपरीत होता है और हमें शाकाहारी और स्वादिष्ट के नाम पर चिप्स, बार, चॉकलेट, बिस्कुट, चिंगम, कुरकुरे, स्पंजी बड़ी आकर्षित प्लास्टिक पैकिंग में एक कागज में जिसमें प्लास्टिक कोटिंग होती है हमें बेचकर मोटा लाभ कम आती हैं। हमारी शाकाहारी आस्थाओं को खंड खंड बिखेरती हैं। इसलिए भी हमको इन्हें छूना नहीं चाहिए। ऐसे सभी विज्ञापनों को टीवी पर आते समय हम टीवी के चैनल बदल देंगे। ताकि ना हम देखे ना हमारे बच्चे देखें और ना हमारे बच्चे उसको खाने पीने की जिद करें।

साप्ताहिक समय माया

विश्व एडस दिवस का सच, कंडोम बेंचने का षड्यंत्र

विश्व स्वास्थ्य संगठन-विश्व में स्वास्थ्य के नाम बिगाड़ों और लूटो संगठन

यह केबल डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन नहीं अर्थात वास्तविकता यह है यह वर्ल्ड हजाड्र्स ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन और यूरोपियन जालसाज डकैतों की बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों का विश्व स्वास्थ्य बिगाड़ो संगठन एक संयुक्त व्यावसायिक संवर्धन संस्था है। वही कंपनियां इस संगठन को धन देकर अपने हिसाब से चलाती हैं। पहले नई खोजों के नाम पहले कुछ भी उल्टा-सीधा बनाओ। सिर बीमारियां खड़ी करो और अपना माल बेचो अर्थात उन ने जो बनाया है। उसे खरीदने के लिए पहले भय पैदा करो। फिर अपना माल, दवाइयां, उपकरण जिसमें मधुमेह, हृदय, किडनी, स्वाईन फ्लू, आदि की हजारों गुना दाम पर मोटा कमीशन सरकारों, डाक्टरों को बांट कर बेचों। यह षड्यंत्र 1910 से अमेरिकी और युरोपियन कंपनियों द्वारा लगातार किया जा रहा है। हर 10 साल में कोई उल्टी-सीधी नई खोज करना फिर उसका परीक्षण करने नई बीमारी पैदा करना फिर अपना हजारों गुना में माल बेंचना।

वही हाल उन्होंने अपने कंडोम बेचने के लिए ऐड्स नाम की बीमारी का पूरी दुनिया में हवा फैलाकर 10 पैसे के कंडोम को आसानी से रू. 10 में बेचने का षड्यंत्र था। जबकि एडस नाम की कोई बीमारी होती ही नहीं।

जो अमेरिका ने अपने देश के बच्चों को 1980 में सरकार की तरफ से ध्यान हटाने के लिए और स्कूलों में ही बच्चों को संभोग केली क्रीड़ा में रत करने के उपरांत भी बच्चे पैदा ना हो। लड़कियां गर्भ की शिकार ना हो। इसलिए उन्होंने पहले फ्री कंडोम बांटने उसका खर्चा निकालने के लिए दुनिया में एड्स की हवा फैलाई गई। ताकि बेंच कर मोटा धन बटोरता जा सके और अपने खर्चे वसूले जा सके।

40 साल के बाद आज तक कंडोम का कोई भी वायरसों कीटाणु नहीं खोज पाए। क्योंकि यथार्थ में ऐड्स नाम की कोई बीमारी दुनिया में होती ही नहीं और डॉक्टर एलोपैथिक के जब बहुत सारी बीमारियां एक दूसरे के विपरीत स्वभाव की मानव शरीर में हो जाने के कारण जब अनियंत्रण की स्थिति बन जाती है। तो आसानी से अपने आप की खाल बचाने के लिए डॉक्टर चला देते हैं कि इसे एड्स हो गया।

मैंने आयुर्वेद और होम्योपैथि का अध्ययन किया था और गाहे में बगाहे अभी भी पढ़ता रहता हूं। आयुर्वेद में 14 प्रकार के प्रमेह का वर्णन व उनकी चिकित्सा मिलती है। प्रमेह रोग स्त्री और पुरुषों की यौन और जननांग रोगों का विवरण देता है।

जिसमें अंतिम उपदंश और सुजाक होते हैं। यदि दोनों एक साथ भी हो जाएं तो भी आयुर्वेद में चिकित्सा के साथ साथ उसके वृहत नियंत्रण के उपाय दिए हुए हैं। जो की महर्षि धन्वंतरि द्वारा हजारों वर्ष पूर्व ही लिख दिए गए थे। उसके बाद में सुश्रुत, चरक, आदि अनेकों समय-समय पर जन्में आयुर्वेदाचार्य ऋषि-मुनियों ने भी इन पर काफी काम किया।

पुरुषों स्त्रियों को संभोग के उपरांत जननांगों को सहवास से फैलने वाले रोगों से बचाव के लिए तात्कालिक उपायों में अपने जननांगों को अपने ही मूत्र से प्रक्षालन का सबसे सटीक उपाय दे दिया था।

होम्योपैथिक में भी उपदंश व सुजाक के नियंत्रण के लिए जर्मन वैज्ञानिक और होम्योपैथिक चिकित्सा के जन्मदाता हेनमन ने अनेकों औषधियां तैयार कर दी थी। बेशक 16 -17वीं शताब्दी में में मलेच्छ राष्ट्र फ्रांस और यूरोप में उपदंश व सुजाक महामारी का रूप ले लिया था। यथार्थ में लिंग को कवर करने के लिए बाारीक पतले चमड़े का खोल बनाकर संभोग को पूरा करने के लिए कबर तैयार किया गया था ताकि योन रोग ना फैल सके स्त्री और पुरुषों में कंडोम का चलन तभी से शुरू हुआ था।

निसंदेह पूरे आयुर्वेद में लिंग को कवर करके संभोग करने की कोई प्रणाली विकसित नहीं हुई थी। परंतु यौन रोगों से संबंधित, बारीकी से विश्लेषण और चिकित्सा की जितनी व्यवस्था आयुर्वेद में की गई है। दुनिया की किसी भी अन्य चिकित्सा पद्धति में आज तक नहीं की जा सकी।

आयुर्वेद में भी प्रमेह की अंतिम दोनों अवस्थाओं उपदंश सुजाक में भी जब अपनी अंतिम अनियंत्रित अवस्था में पहुंचता है। तो स्त्री पुरुषों की मृत्यु का कारण बन जाता है जो शरीर के हर अंग में फैल कर भारी विकृतियों उत्पन्न कर देता है।

निसंदेह कंडोम ऐसे सभी यौन रोगों और अनावश्यक स्त्रियों में गर्भ को रोकता है। जिसे 1998 से लगातार बार-बार मेरे समय माया द्वारा प्रकाशित करने के कारण जो कि अमेरिका के व्हाइट हाउस, व अन्य देशों के दूतावासों को डब्ल्यूएचओ को भी पीडीएफ कॉपी भेजी जाती है। जानबूझकर उन्होंने एड्स के प्रचार की अपेक्षा अस्पतालों में भी यौन रोग और गर्भनिरोधक के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया।

इसके संबंध में भोपाल के ज़ी टीवी कंपलेक्स में सन 1960 से लेकर 2008 तक चलने वाली ब्रिटिश लाइब्रेरी में 98 के अंत में लंदन टाइम्स में नार्वे के 200 डॉक्टरों के एक समूह ने इस पर काफी शोध करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला की यथार्थ में एड्स नाम की कोई बीमारी नहीं होती। वह केवल कंडोम बेचने और उससे अरबों रुपए प्रतिदिन की कमाई करने का षडयंत्र मात्र है। एड्स के भय को फैलाने और कंडोम से मोटी कमाई करने में एशियाई देशों में बढ़ती आबादी को रोकने के लिए वर्ल्ड हजार्डियस आर्गेनाइजेशन ने हीं इस प्रपंच का षड्यंत्र रुचकर एड्स नाम की काल्पनिक बीमारी को पैदा कर यह भय 1980 से सभी प्रसार माध्यमों पर फैलाना शुरू कर दिया था। वैसे इस षड्यंत्र के पीछे विश्व शैतान संघ का छिपा षडयंत्र यह भी था कि एशियाई देशों में पारिवारिक संबंधों और मूल्यों को खत्म कर यौनाचार की उच्श्रृंखलता फैला कर आसानी से हिंदू धर्म को नष्ट किया जाए और ईसाइयत को बढ़ावा दिया जाए। इसमें वे पूर्णतया सफल रहे हिंदू धर्म के पारिवारिक मूल्यों को नष्ट कर उच्श्रृंखलता को बढ़ाने में वे सफल रहे।

मेरे पाठकों को अब समझ में आ गया होगा कि एड्स नाम की बीमारी क्या है।

संचार क्रांति का अंतरजाल मनुष्य की जिंदगी का भयावह मकड़जाल बन गया

राक्षस बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट और गूगल दम घोट रहे आम आदमी से खास तक

सारी मनुष्यता की निजता सरेआम चौराहों पर बिकने, लुटने और नीलाम हो पोस व आधुनिक ठगी का साधन बनी

विश्व भर में फैले संचार क्रांति के इंटरनेट जाल ने बेशक जिंदगी को सरल बनाने का जो एहसास करवा रहा है। यथार्थ में वह वर्तमान पीढ़ी को मानसिक शारीरिक और व्यवहारिक रूप से अत्यधिक पंगु बनाने के साथ आने वाली पीढ़ियों को पूर्णताः पौरूषहीन बना देगा। जिसके भयावह परिणाम सामने तेजी से आने लगे हैं। इस मैं उलझकर आदमी अपनी व्यवहार कुशलता सामाजिकता भूलता जा रहा है। यह तो वर्तमान पीढ़ी की बात हुई परंतु आने वाली पीढ़ी शायद बच्चे अपने मां बाप को घर में रहकर भी नहीं पहचानेंगे। दूसरी तरफ इस इंटरनेट के मकड़जाल में इसके संस्थापक महा ठगोरे माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स से लेकर याहू गूगल जैसे खोजी सर्च इंजनों से लेकर पूरी दुनिया में लाखों इनके सॉफ्टवेयर बनाने वाले और मोबाइल के सॉफ्टवेयर बनाने वाले राक्षसों में पूरी दुनिया के लगभग 50 से 70प्रतिशत लोगों की अपनी निजी जीवन की सारी जानकारियां न केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों जिसमें दवा, कॉस्मेटिक, बैंकिंग, फाइनेंस से लेकर हैकरों द्वारा रोहतक के भेज दी गई। आज बड़ी बैंकिंग कंपनियों का डाटा जिसमें उनके ग्राहकों की जमाओं का, उनके कर्जों की जानकारियां गुड डेबिट क्रेडिट कार्ड की जानकारियां एटीएम, पेटीएम आदि की जानकारियां भी हैकरों के हाथ में जाने से वह एक सफेदपोश डकैती का नया व्यवसाय बन गया। इसके दूसरी ओर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इंस्टाग्राम, जैसी सोशल साइटों ने आतंकवादियों की भर्ती से लेकर आईएसआई जैसे वैश्विक आतंकी गुटों को लोगों को डराने धमकाने ब्लैकमेल करने, खातों को खाली करने आदि तक के काम में इन माइक्रोसॉफ्ट, गूगल व अन्य कंपनियों के जो आपसे हर बात में आपके मोबाइलों की संपर्कों की सूची, संदेशों, बातचीत का ब्यौरा आज तक पूरी दुनिया में फैला कर मोटा पैसा कमाते हैं। बात यहीं तक खत्म नहीं हुई माइक्रोसॉफ्ट ने ही अपनी मोटी कमाई की आड़ में भी अपने पुराने सॉफ्टवेयरों को बंद करके नए सॉफ्टवेयरों को डाउनलोडिंग का मासिक किराया लेने के साथ-साथ उस आपके डेटा को इकट्ठा करके सरकारों से लेकर हैकरो को बताने, लोगों के खातों में उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में हस्तक्षेप करने का भी पूरा इंतजाम कर दिया। आज अकेले भारत में ही हर सेकंड 10 से 20 खातों में सेंध लगाई जाती है। और उनके खाते खाली कर दिए जाते है जिसमें हमारे देश की भारत सरकार भी पूरा अंध्र सहयोग करती है। खुद सरकार के पास अपनी डाटा इकट्ठा करने की कोई व्यवस्था नहीं फिर भी आधार कार्ड, पेटीएम, पेटीएम बैंक के डेबिट-क्रेडिट कार्ड सारे हैकरों को इस संचार क्रांति के अंतरजाल के मकड़जाल में उलझा चुकी है। और स्वयं भी बुरी तरह से उलझ चुकी है। हमारी सरकार सोचती है कि वह सारा

काम बहुत अच्छा कर रही है पर शायद यह उसकी बहुत बड़ी भ्रम पूर्ण स्थिति है। क्योंकि उसकी सरकारो इसमें केंद्र व राज्य सरकारें के सभी मंत्रालय का सारा डाटा भी विदेशी कंपनियों माइक्रोसॉफ्ट गूगल के पास इकट्ठा होता रहता है। जिसका वह तरीके से उपयोग और ब्लैकमेलिंग करके सरकार से भी मोटी वसूली करते हैं भारत सरकार के केंद्रीय व राज्यों के सभी मंत्रालय और उनके सभी विभाग आमजन को सूचना के अधिकार में जानकारी देने के लिए तरह-तरह के नाटक नौटंकी करते हो और 90 प्रतिशत आवेदकों को जानकारी ना दी जाती हो परंतु वह सारी जानकारी हमारे देश से दूर विदेशों में ट्रिलियन गीगाबाइट के रूप में हर दिन इकट्ठी होती रहती है जिसका पाकिस्तान चीन रूस अमेरिका से लेकर अन्य अनेकों देशों की सरकारे वहां बैठी हुई बहुराष्ट्रीय कंपनियां तरीके से उपयोग कर की कमाई में लगी हुई है।

विश्व की जनता को यह अच्छी तरह से समझ देना चाहिए यह संचार क्रांति का अंतरजाल के मकड़जाल मैं पूरी दुनिया का हर आदमी बुरी तरह से इस माइक्रोसॉफ्ट गूगल व अन्य ऐप निर्माता कंपनियों क्यों आपको मुफ्त में देकर वसूली कर सुविधाएं दें। आप की सारी बातचीत लेखन सारे आपके फोटो वीडियो आपकी सारी फाइलें आपको सारे बैंक अकाउंट की जानकारी एक बार आपके कंप्यूटर मोबाइल से इंटरनेट पर यह इंटरनेट के माध्यम से उस पर पहुंची वह पूर्ण रूप से सार्वजनिक जीवन में इन राक्षसों के हाथ में पहुंचकर व्यवसायिक उपयोग में आपको ब्लैकमेलिंग करने के उपयोग में कभी भी कहीं भी कैसे भी काम में ली जा रही है, जिसका दुष्परिणाम देखने और झेलने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। जो भी कार्य जनता ने मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से किया है या नहीं भी किया है। परंतु ना उपयोग करने वाली जनता की भी उसके संबंधित कार्यों की जानकारी भी जिसमें भारत में आधार कार्ड, मजदूर कार्ड, बिजली के बिल, बीमा बैंक के खाते सब की जानकारियां दुनिया के 2 बड़े राक्षसों के साथ लाखों जालसाज ठगोरों के व्यवसायिक उपयोग में पहुंच चुकी है। जो भविष्य में कहीं ना कहीं संबंधित को और दुनिया के 500 करोड़ से ज्यादा उपयोगकर्ताओं को चाहे वे विद्यार्थियों, व्यवसायी हो, घरेलू महिलाएं, मजदूर हों, कृषक, कर्मचारी हों। सब का उपयोग ना केवल यह गोरे जालसाज कर रहे हैं वरन देश की सरकारें भी उन जानकारियों का भरपूर दुरुपयोग अपने हितों के साधन में अपने पूंजीपति आकाओं के लिए भी पूंजीवादी और लोकतांत्रिक राष्ट्रों में अपनी लूट के लिए वहां के मंत्री अधिकारी कर रहे हैं इसे जनता को समझना ही होगा। शीघ्र ही इस अंतरजाल के मकड़जाल से निकलने के लिए प्रयास करने होंगे व्यक्तिगत स्तर पर अपना कम से कम मोबाइल कंप्यूटर का और कंप्यूटर पर इंटरनेट रूपी अंतरजाल के मकड़जाल का उपयोग न्यूनतम करना होगा। साथी मोबाइल इंटरनेट से बाहर निकल ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर ऑनलाइन सारे काम करने शीघ्र त्यागना होंगे। अन्यथा अब कौन कहां कैसे परेशानी में फंस जाएगा इसका अनुमान लगाना भी संभव नहीं। सरकारी स्वयं अपने स्वार्थ के लिए माइक्रोसॉफ्ट गूगल व अन्य कंपनियों के हाथों बिकी हुई है। वे स्वयं इन जानकारियों का उपयोग कर रही है तो वह जनता की कैसे और क्या सुरक्षा कर पाएंगे? व्हाट्सएप भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय और चलन में आ जाने के कारण सरकार की निगाहों में आने के साथ-साथ व्हाट्सएप जो फेसबुक का हिस्सा बन गया है। उनके अनुसार सरकार तो अभी जासूसी करने की बात कर रही है। वह तो पहले से ही पिछले 10 सालों से उपयोगकर्ताओं के संदेशों की जासूसी करना, उनके डाटा इकट्ठे करना, उनके संपर्कों की सूची से लेकर उपयोगकर्ताओं के मोबाइल में पड़े फोटो-वीडियो व अन्य सभी तथ्यों की जानकारी एकत्रित कर उनका व्यवसायिक उपयोग करने का अनुबंध की तो गूगल प्ले के माध्यम से डाउनलोड करते समय आपसे हामी भरवा ली जाती है। जिसके व्यवसायिक उपयोग दुरुपयोग के साथ आपकी गोपनीयता का दुरुपयोग का कारण भी बन चुका है। बेहतर होगा कि इसको त्याग कर हमारे देश की भारती एयरटेल के संस्करण व्हाटसएप के भारतीय संस्करण हाइक का उपयोग करना शुरू कर दिया जाए। बेशक डाटा वह भी इकट्ठा करेगा और मौका मिलने पर दुरुपयोग भी करेगा। जिस पर अभी सरकार की नजर नहीं है। और वह अभी पूरी दुनिया में फैला हुआ भी नहीं है। जिससे आपकी गोपनीयता विश्व स्तर पर भंग नहीं होगी। और विश्व स्तर पर आपके तथ्यों संपर्क सूची चित्रों और चल चित्रों के भंडारण पर भी ज्यादा दुरुपयोग नहीं किया जा सकेगा। (शेष पृष्ठ 4 पर)

www.samaymaya.com की साइट से समाचार पत्र की पीडीएफ डाउनलोड कर सोशल मीडिया पर अपने मित्रों को भेज सकते हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 94256-37958, इंदौर कार्यालय- मोबा. 94251-25569, 94795-35569